Tuesday 12, March, 1974

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 5th LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
Parliament Library
28-8-92

[खंड 36 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपए

Price : Two Rupees

विषय सूची CONTENTS

क्रम सं० 15, मंगलवार, 12 मार्च, 1974/21 फाल्गुन, 1895 (शक)

No. 15, Tuesday, March 12, 1974/Phalguna 21, 1895 (Saka)

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
265	'सागर सम्राट्' द्वारा की गई तेल की खोज	Oil Exploration by "Sagar Samrat"	1
269	एक और 'कस्टम बिल्ट ड्रिलिंग प्लेटफार्म' प्राप्त करने का निर्णय	Decision to Acquire another custom Built Drilling Platform .	4
271	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा डीजल पम्पिंग सैटों को विद्युत् पम्पिंग सैटों में परिवर्तित करना	Conversion of Diesel Pumping sets to Electrical ones by R.E.C. .	5
274	निर्धारित स्थानों तक कोयले को ढोने के लिये रेलवे की असफलता	Railway's Failure to Transport Coal to Destinations .	8
275	केरल में विभिन्न स्थानों पर तेल के लिये छिद्रण कार्य	Drilling operations at Different places in Kerala.	9
279	व्यय खर्च को रोकने के उपाय सुझाने के लिये समिति	Committee to suggest Measures to Check Westeful Expenditure . .	11
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
261	अमरीकी फर्मों के साथ तेल के लिये तटदूर छिद्रण के लिये बात-चीत	Negotiations with U.S. Firms for Off-shore Drilling	13
262	दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के विद्युत् प्रजनन संयंत्रों में कोयले की कमी	Shortage of Coal in Power Generation Plants of DESU . .	14

किसी नाम पर अंकित यह †इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign †marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
263	पश्चिम कोसी नहर परियोजना	Western Kosi Canal Project .	14
266	औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 और संश्लिष्ट रबड़ (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1969 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के मूल्य	Prices of Articles covered by the Drugs (Price Control) Order, 1970 and the Synthetic Rubber (Price Control) Order, 1969 . . .	15
267	सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों को हुआ वार्षिक घाटा	Annual Loss suffered by Public Sector Refineries . . .	15
268	आल इंडिया रेलवे एकाँउन्टस एम्प्लाइज एसोसियेशन की कार्ड पास और कम्प्लीमेंटरी पासों के लिये मांग	Demand for card pass and Complimentary passes by All India Railway Accounts Employees' Association .	15
270	तेल के संकट के बारे में वाशिंगटन में हुये सम्मेलन में हुई चर्चा	Discussions at the Conference on oil crisis held in Washington . .	16
272	पूर्वोत्तर रेलवे में गंभीर श्रम स्थिति	Serious Labour Situation on North Eastern Railway . .	16
273	आसाम तथा गुजरात में तेल भंडारों की खोज	Exploration of Oil Reserves in Assam and Gujarat . . .	16
276	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई रेल लाइनों के लिये कुल धनराशि का नियतन	Total Allocation for new Railway Lines during Fifth Five Year Plan . .	17
277	गाजियाबाद में सिगनल वर्कशाप से लोहे की सामग्री और कोयले की चोरी की जांच	Investigation into the theft of Iron Material from Signal Workshop and Coal at Ghaziabad.	18
278	कैप्रोलैक्टम और डी० एम० टी० का निर्माण करने वाले कारखाने	Factories producing Caprolactum and D.M.T.	19
280	शाहदरा के निकट रेल गाड़ियों की टक्कर	Train Collision near Shahdara	19
अता० प्र० संख्या U.S.Q No.			
2605.	26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली विदेशी रासायनिक फर्मों द्वारा अपना लाभ अन्य वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जाना	Diverting profits by Foreign Chemical Firms having more than 26 per cent Foreign Equity	20

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2606	दिल्ली में कुकिंग गैस उपभोक्ताओं के लिये कोयले तथा मिट्टी के तेल की मात्रा में कमी	Reduction in Quantum of Coal and Kerosene for Cooking Gas Consumers in Delhi.	21
2607	मध्य रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक	Casual Labourers in Central Railway .	22
2608	वर्ष 1974–75 के दौरान जल-परियोजना को स्वीकृति	Clearance of Hydel Project during 1974-75	22
2609	22 कम्पनियों की प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के बारे में जांच	Enquiry into the Restrictive Trade Practices of Twenty two Companies. .	22
2610	कर्नाटक राज्य के दक्षिण कनारा जिले में पंजीकृत कार्यालय वाली कम्पनियां	Companies having their Registered Offices in South Kanara District (Karnataka State).	23
2611	अनुमति पत्रों और लाइसेंसों के अधीन हुए उत्पादन का मूल्य	Value of production covered under Permission letters and Licences. .	23
2612	मैसर्स होयस्ट द्वारा कीटनाशक एन्डोसूफन के लिये तकनीकी जानकारी दिये जाने की पेशकश	Technical know-how offered by M/s Hoechst for an Insecticide ENDOSUIFAN .	24
2613	केरल के कजाकुट्टम रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण	Modernisation of Kazhakuttam Railway Station in Kerala	24
2614	कजाकुट्टम रेलवे स्टेशन (केरल) पर यात्रियों के लिये सुविधायें	Facilities for the Passengers at Kazhakuttam Railway Station (Kerala). .	25
2615	रेलों में विभिन्न श्रेणियों के स्थानों के लिये पात्रता	Eligibility to various Classes of Railway Accommodation	25
2616	अजमेर (पश्चिम रेलवे) में काम करने वाले कर्मचारियों को देय राशि का भुगतान न किया जाना	Non-payment of Due to Staff working at Ajmer (Western Railway). .	25
2617	बजुआ में काम करने वाले कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की अदायगी	Payment of House Rent Allowance to Staff working at Bajuwa . . .	26
2618	उत्तर रेलवे द्वारा पश्चिम रेलवे को दिल्ली में क्वार्टरों का हस्तान्तरण	Transfer of Quarters from Northern Railway to Western Railway at Delhi	28

अता०प्र ० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2619	उत्तर रेलवे के लेखा कर्मचारियों में से "स्टाक वेरीफायरों" का पेनल बनाया जाना	Fomation of Panel of Stock Verifiers from Accounts staff, Northern Railway .	26
2620	तापीय संयंत्रों को कोयले की सप्लाई तापीय संयंत्रों में कोयले की खपत	Supply of Coal to Thermal Plants	27
2621	तापीय संयंत्रों में कोयले की खपत	Consumption of Coal in Thermal Plants	27
2622	पूर्व रेलवे के कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confermation of Employees of Eastern Railway	28
2623	हड़तालों तथा अन्य प्रदर्शनों के फलस्वरूप पूर्व रेलवे की सम्पत्ति को पहुंची क्षति	Loss of property suffered by Eastern Railway due to Strike and other agitation	28
2624	गत वर्ष के दौरान मध्य रेलवे में अपराध	Crimes on Central Railway during the Last Year	29
2625	मध्य रेलवे में बिना जंजीर वाली यात्री गाड़ियां	Passenger Trains without chain pulling device on Central Railway . . .	29
2626	भारतीय रेलवे प्रतिनिधि मण्डल को न्यूयार्क के दौरे में मिली सफलता	Success of visit of Indian Railway delegation to New York	29
2627	दिल्ली डिविजन (उत्तर रेलवे) के लिये रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति का गठन	Composition of Railway User's Consultative Committee for Delhi Division (Northern Railway)	30
2628	फिरोजपुर डिविजन (उत्तर रेलवे) के लिये रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति का गठन	Composition of Railway User's Consultive Committee for Ferozepur Division (Northern Railway) .	30
2629	राष्ट्रीय रेल प्रयोक्ता समिति का गठन	Composition of National Railway User's Committee	30
2630	मद्रास उर्वरक कारखाने से विस्तार के लिये आवेदन पत्र	Applications for Madras Fertilizers for expansion	31
2631	मध्य प्रदेश में तेल निक्षेपों के लिये सर्वेक्षण	Survey for oil deposits in Madhya Pradesh	31

अता०प्र० सख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2632	पांचवीं योजना में मध्य प्रदेश के लिये सिंचाई परियोजना	Irrigation projects for M. P. in Fifth Plan	31
2633	भारतीय रेलवे संहिता का उल्लंघन करने के बारे में अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक क्लर्क एसोसियेशन के अभ्यावेदन के बारे में निर्णय	Decision on representation from all India Railway Commercial Clerk's Association Re : violation of Indian Railway Code	32
2634	खराब होने वाली वस्तुओं के लिये मध्य रेलवे में भाड़ा वसूल करना	Charging Freight on Perishable Articles on Central Railway	32
2635	त्रिपुरा खुदाई स्थल के परियोजना प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच	Investigations into charges of Corruption against Project Manager of Tripura Drilling Site	33
2636	योजना मंत्री का कुछ तेल उत्पादक देशों का दौरा	Visit of Planning Minister to some Oil Producing Countries . . .	33
2637	बड़े व्यापार गृहों से व्यक्तिगत उद्यमों का अलग किया जाना	Delinking of Individual Enterprises from large Houses	33
2638	अन्तर्सत्र अवधि में सलाहकार समितियों की बैठक	Meeting of Consultative Committee during Inter Session Period. . . .	34
2639	बिजली के विकास कार्यक्रमों पर खर्च	Expenditure on Power Development Programmes	34
2640	चुनावों के लिये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्राणाली आरम्भ करना	Introduction of System of Proportional Representation on Elections .	35
2641	मैसर्स होचेस्ट से औद्योगिक लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र	Applications from M/s. Hoechst for Industrial Licences . . .	35
2642	बिजली के संकट को दूर करने के लिये बिजली उद्योग के संगठनात्मक ढांचे को युक्तिसंगत, पुनर्गठित तथा सुदृढ़ करना।	Rationalisation Restructuring and Strengthening of Organisational Set-up of Power Industry to meet Power Famine	36
2643	कच्चे तेल के भंडार बनाने के लिये संभावित दस वर्षीय योजना	Ten Year Prospecting Plan for Crude Reserve	36
2644	26 प्रतिशत से अधिक विदेशी ईक्विटी वाली विदेशी औषध फर्मों का पूंजीनिवेश	Investment of Foreign Drug Firms with more than 26 per cent Foreign Equity	37

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2645	औषध तथा मेषज विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन	Expert Body Report on Drugs and Pharmaceuticals	38
2646	कोयले के लदान में लगाये गये नैमित्तिक श्रमिक	Casual Labour Engaged in Loading of Coal	38
2647	रेलवे के लिये एक यूनियन	One Union for Railways	38
2648	बेसिक औषधियों को बढ़ाने की योजना	Plan to Boost the Production of Basic Drugs	39
2649	ईरान द्वारा, भारत की अपेक्षा पाकिस्तान को सस्ती दर पर अशोधित तेल की बिक्री	Sale of Crude Oil by Iran to Pakistan at Cheaper Rates than to India . .	39
2650	रेलवे के भावी कार्यकरण पर तेल संकट के प्रभाव का रेलवे प्रशासन द्वारा अध्ययन	Railway Administration's Study on Impact of Oil Crisis on future working of Railway	39
2651	औषध बनाने वाली देशी तथा विदेशी कम्पनियां और उनका उत्पादन	Indian and Foreign Pharmaceutical Companies and their production	40
2652	वैगनों की कमी के कारण पटसन और कोयले का जमा हो जाना	Accumulations of Jute and Coal due to Shortage of Wagons. .	41
2653	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मध्य प्रदेश में मंजूर की गई लघु परियोजनाएं	Mini Projects Sanctioned by Rural Electrification Corporation in Madhya Pradesh	41
2654	18 और 19 फरवरी, 1974 को हुआ वकीलों का सम्मेलन	Lawyers Conference held on 18th and 19th February, 1974	41
2655	दक्षिण-पूर्व रेलवे में लोको मैनों के लिये 10 घंटों की ड्यूटी	10-Hour Duty for Locomen on South-Eastern Railway	42
2656	चौथी योजना में बिहार के लिये सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects for Bihar in Fourth Plan	42
2657	बाणसागर परियोजना करार को कार्यान्वित करना	Implementation of Bansagar Project Agreement	43
2658	जयन्ती जनता एक्सप्रैस के लिये चित्रों का चयन	Selection of Paintings for Jayanti Janta Express	43
2659	हिन्डालको को बिजली की सप्लाई	Power Supply to Hindalco .	43

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2660	टैक्सियों और आटोरिक्शा की मालिकों की सहकारिता को पेट्रोल पम्प अलाट करना	Allotment of Petrol Pumps to Co-Operatives of Taxis and Auto-Rikshaw owners	44
2662	मैसर्स सेन्डोज तथा अन्य कम्पनियों द्वारा फार्म्यूलेशन का बिना लाइसेंस उत्पादन	Production of Formulations by M/s. Sandoz and other Firms without Licence . . .	44
2663	पांचवीं योजना में केरल सिंचाई और विद्युत् परियोजनाएं स्थापित करना।	Setting up of Irrigation and Power Projects in Kerala in Fifth Plan .	45
2664	केरल को कोयला भेजने के लिये उपलब्ध रेलवे वैगन	Railway Wagons available for Transportation of Coal to Kerala . . .	46
2665	केरल के प्रति एक लाख व्यक्तियों पर रेलवे लाइन की लम्बाई	Length of Railway Line per one Lakh Persons in Kerala . . .	46
2666	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा 1973–74 के दौरान केरल के लिये स्वीकृत परियोजनायें	Projects sanctioned by R.E.C. for Kerala during 1973-74	47
2667	रेलवे के गार्डों को अपने नये वेतनमानों पर असंतोष	Railway Guards' dissatisfaction with New Pay Scales	47
2668	पेट्रोल और अन्य उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Petrol and other Products	47
2669	सिंचाई परियोजनाओं की क्रियान्विति	Implementation of Irrigation Projects .	48
2670	तेल की स्थिति को देखते हुये सरकारी विभागों में वाहनों की संख्या में कमी	Reduction in number of Vehicles with Government Departments in view of Oil situation .	48
2671	नागपुर के रेल कर्मचारियो को अनाज की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Railway Workers of Nagpur	48
2672	दक्षिणी पेट्रो-रासायनिक उद्योग निगम को कुड्डालोर में उर्वरक संयंत्र लगाने की अनुमति	Permission to Southern Petro-chamicals Industries Corporation to set up a Fertilizer Plant at Cuddalore . .	49
2673	प्रत्येक रेलवे द्वारा बेचे गये स्क्रेप की मात्रा और उनका मूल्य	Value and Quantity of Scrap disposed of by each Railway	49

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2674	काम के घंटों के समायोजन द्वारा इंधन तथा विद्युत् की बचत	Saving of Fuel and Power through Adjustment of Working Hours . . .	50
2675	रेल कर्मचारियों को उचित दर की दुकानों से राशन दिलाने का प्रस्ताव	Proposal to supply ration to Railway Employees through Fair Price Shop	50
2676	तेल की खोज के लिये 'कांटिनेंटल शैल्फ' का सर्वेक्षण	Survey of Continental Shelf for Oil Exploration	51
2677	शोलापुर डिवीज़न को मध्य रेलवे ज़ोन में शामिल करना	Inclusion of Sholapur Division in Central Railways Zone	51
2678	इस्पात संयंत्रों के लिये रेल के पर्याप्त माल डिब्बे	Adequate Railway Wagons to Steel Plants	52
2679	रेल पट्टी को सुदृढ़ बना कर कोयले की खपत में बचत	Economy in Consumption of Coal by Strengthening Railway Tracks . .	52
2680	एकाधिकार गृह द्वारा नये उपक्रम की स्थापना के बारे में एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग का निर्णय	Decision by M.R.T.P. Commission on setting up a new undertaking by Monopoly House	53
2681	पाज्जासी परियोजना और थान्निरमुक्कोम परियोजना का निर्माण	Construction of Pazassi Project and Thannirmukkom Project . . .	53
2682	आलावाकोड्डे डिवीज़न (दक्षिण रेलवे) के रेलवे कर्मचारियों द्वारा मकान निर्माण के लिये आवेदन	House Building Applications by Railway Employees of Olavakkode Division (Southern Railway)	54
2683	ओलावाक्कोडे क्षेत्र (दक्षिण रेलवे) में रेल गाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of Trains in Olavakkode Region (Southern Railway). . .	54
2684	अरकोनम से कोचीन तक दोहरी रेलवे लाइन बिछाना	Doubling of Railway Track from Arkonam to Cochin . . .	54
2685	ईंधन तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग	Use of Coal in place of Oil Fuel. .	55
2686	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये धनराशि	Funds for Rural Electrification in Fifth Plan	55
2687	कलकत्ता के लिये तीसरा बड़ा स्टेशन	Third big Station for Calcutta.	56

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2688	पश्चिम बंगाल में सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनाओं की प्रगति	Progress of Irrigation and Power Projects in West Bengal. .	57
2689	पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को निर्धारित करने के लिये समिति	Committee for Fixation of Prices of Petroleum Products .	58
2690	मालगाड़ियों को रद्द करने के कारण वाणिज्यि कमाल का परिवहन अस्तव्यस्त होना	Disruption of Transportation of Commercial Goods due to Cancellation of Goods Trains . . .	58
2691	उर्वरक उद्योग के सहकारी क्षेत्रीय विकास के लिये योजना	Plan for Co-operative Regional Development of Fertilizer Industry . .	58
2692	भारत में ड्रिलिंग रिगों का निर्माण	Manufacture of Drilling Rigs in India .	59
2693	विदेशों से भारतीय रेलवे में प्रयोग हेतु, सामान और मशीनों की खरीद	Purchase of Goods and Machinery from foreign countries for Indian Railway .	59
2694	पिछले तीन मास में रेलों में अपराधों की घटनायें	Crimes on Railway registered during the last three months . . .	60
2695	पटना जंकशन स्टेशन पर अप तथा डाउन गाड़ियों का देरी से पहुंचना	Late arrival of Up and Down Trains at Patna Junctions	60
2696	अन्य नगरों में भी राजधानी एक्सप्रैस रेलगाड़ियां चलाना	Introduction of more Rajdhani Express Trains to cover more cities . .	60
2697	वर्ष 1973 में भारतीय तेल निगम की अधिक बिक्री	Higher Turnover of I. O. C. in 1973 .	61
2698	नेशनल रबर मैन्यूफेक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता और इन्चेक टायर लिमिटेड कलकत्ता का निवेश ढांचा	Investment structure of National Rubber Manufacturers Limited, Calcutta and Inchek Tyres Limited, Calcutta . .	61
2699	नेशनल रबर मैन्यूफैकचरर्स (लिमिटेड) कलकत्ता के कार्यकरण की जांच	Prove into the Affairs of National Rubber Manufacturers (Limited), Calcutta .	62
2700	खराब माल डिब्बों की संख्या और उनकी मरम्मत	Number of Sick wagons and Repair thereof	63
2701	पश्चिम बंगाल को बिजली की सप्लाई	Supply of Power to West Bengal . .	63

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2702	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण की जांच के लिये समिति	Committee to go into the working of O & N. G. C.	63
2703	देहरादून एक्सप्रैस गाड़ी से नई दिल्ली स्टेशन पर कुछ डिब्बे काट देना	Detachment of Bogies from Dehradun Express at New Delhi . . .	64
2704	पश्चिम रेलवे में गार्डों को गरम ओवरकोट देना	Issue of Woollen over-coats to Guards on Western Railway . . .	64
2705	उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मनीपुर में चुनाव प्रत्याशीयों में प्रेट्रोल की खपत में कमी करने के लिये अपील	Appeal to contestants of elections in U. P., Orissa and Manipur to consume less petrol.	64
2706	हावड़ा और बाल्टेयर के बीच विद्युत गाड़ी	Electric Train between Howrah and Waltair	65
2707	उड़ीसा में द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत 'टेस्ट रिलीफ' कार्यों पर किया गया व्यय	Expenditures incurred on Test Relief work under crash programme in Orissa	65
2708	उड़ीसा में उद्योगों को बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Industries in Orissa .	65
2709	अशोधित तेल का क्रम मूल्य	Purchase Rate of crude Oil .	66
2710	पेराक्साईलीन संयंत्र के कम्प्रेशन में दोष	Defects in the Compressor of Paraxylene Plant	66
2711	बोदरा, पश्चिम बंगाल में तेल के लिये छिद्रण कार्य	Drilling at Bodra in West Bengal .	67
2712	हावड़ा स्टेशन पर आकस्मिक श्रमिकों को मिलने वाली मजूरी की दरों पर काम करने वाले कुली	Luggage Porters working on casual labour Rates at Howrah Station . .	67
2713	हावड़ा और सियालदह स्टेशनों को नया रूप देना	Remodelling of Howrah and Sealdah Stations	67
2714	पूर्वी जोन में गाड़ियों का विलम्ब से चलना	Late Running of Trains in Eastern Zone .	68
2715	पटना और आरा के बीच यात्री तथा शटल रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना	Late Running of Passenger and Shuttle Trains between Patna and Arah . .	68

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2716	रेल कर्मचारियों को सशस्त्र सेनाओं और सीमा सुरक्षा दल के सामान राशन और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई	Supply of Ration and Essential Commodities to Railway Employees at par with Armed Forces and B. S. F. .	69
2717	पुनरीक्षित वेतनमानों, 1973 में वेतन निर्धारित करने में असमानता	Disparity in fixation of pay in revised scales, 1973	69
2718	औषध उद्योग के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के लिये औद्योगिक विकास मंत्रालय के साथ परामर्श	Consultation with Ministry of Industrial Development for preparing guide lines for drug industry	71
2719	मैसर्स फाइज़र्स के विस्तार के प्रस्ताव	Expansion proposals of M/s Pfizers .	71
2720	मैसर्स होचेस्ट को जारी किये गये लाइसेंस	Licences issued to M/s. Hoechst	72
2721	आगरा और कोटा के बीच चलने वाली 84 अप और 83 डाउन गाड़ियों को रद्द करना	Cancellation of 84 Up and 83 Down Passenger Trains between Agra and Kota	73
2722	बम्बई में हुई विद्युत विषयक विचार-गोष्ठी	Seminar on Power held in Bombay ..	73
2723	रेलवे तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के बीच मतभेद	Confrontation between Railways and DESU	74
2724	दक्षिण रेलवे में कोयले की कमी	Coal shortage in Southern Railway .	74
2725	तेल के प्रयोग में मितव्ययता के लिये मार्ग दर्शी सिद्धांत	Guide lines for Economy in use of Oil	75
2726	कलकत्ता और मद्रास की उपनगरीय गाड़ियों में अत्याधिक भीड़	Overcrowding in Suburban Trains of Calcutta and Madras . . .	75
2727	गुजरात में तेल क्षेत्रों में खुदाई का कार्य स्थागित करना	Suspension of Drilling operations in Gujarat	76
2728	अहमदाबाद और बम्बई के बीच वातानकूलित डीलक्स एक्सप्रैस गाड़ी पुनः चलाने का प्रस्ताव	Proposal to reintroduce Air Conditioned Delux Express Trains between Ahmedabad and Bombay . . .	76

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2729	रेलवे के लिये बिजली घरों की स्थापना के लिये विदेशी तकनीकी सहायता	Foreign Technical Assistance for setting up Power Houses for Railways . .	76
2730	रेलवे में कमीशन के आधार पर काम कर रहे बैरे	Waiters working on Commission basis in Railways	77
2731	कर्मचारियों के भारी संख्या में काम पर न आने के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे में गाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellations of Trains on South Eastern Railway due to Mass Absenteeism .	77
2732	गाड़ियों का समय पर ना चलना	Reasons for late running of Trains .	78
2733	पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ के डीज़ल के ड्रमों का गणेश चीनी मिल के अहाते के अन्दर जब्त किया जाना	Diesel Drums of N. E. Railway Lucknow seized inside Ganesh Sugar Factory premises	78
2735	भारत में तेल क्षेत्र	Oil Fields in India . . .	78
2736	नाभा जाने वाली एक टेंकर से जबरन डीज़ल तेल का वितरण	Forced Distribution of Diesel Oil from a Tanker on way to Nabha . . .	79
2737	मिट्टी तेल की कमी का डबलरोटी के उत्पादन पर प्रभाव	Impact of shortage of Furnace Oil on Bread	79
2738	पांचवी पंचवर्षिय योजना में सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने की स्थापना	Setting up of Fertilizer Plants in Co-Operative Sector in Fifth Plan . .	76
2739	आसाम में अशोधित तेल परिष्करण संयंत्र की स्थापना	Setting up of a crude Oil conditioning Plant in Assam	80
2740	रतनगढ़ में पैदल चलने वालों के लिए उपरी-पुल	Over-bridge for Pedestrians at Ratangarh	80
2741	रूस से मिट्टी के तेल का आयात तथा राज्यों को इसका वितरण	Import of kerosene from USSR and its distribution to states . . .	81
2742	राज्यों में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	Electrification of Harijan Basties in States	81
2743	भाप तथा डीज़ल से चलने वाले इंजनों का निर्माण करने में आत्म-निर्भरता	Self-sufficiency in manufacture of Steam and Diesel Loco-motives . . .	82

अता० प्र० संख्या U.S.Q No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2744.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तृतीय श्रेणी की शायिकाओं और चेयरों वाली अधिक वातानुकूलित गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव	Proposal to run more Air-conditioned Trains with Third class Sleepers and chairs during the Fifth Five Year Plan	82
2745.	कर्नाटक में अपर कृष्णा नदी परियोजना को पूरा करने के लिये सहायता	Assistance for Execution of Upper Krishna Project in Karnataka	82
2746.	भारत द्वारा फारस की खाड़ी के देशों के साथ संयुक्त उपक्रम से मिलने वाले रूस्तम अशोधित तेल में से अपने भाग की बिक्री बन्द करना	India stopping sale of her share of Rustam crude from Persian Gulf Joint . Venture	83
2747.	फरक्का बांध का निर्माण कार्य	Construction work on Farraka Barrage .	83
2748.	ब्रैडा एण्ड कम्पनी, बम्बई	Brady & Co., Bombay . .	84
2749.	वर्ष 1973–74 के दौरान भाखड़ा कम्पलेक्स से बिजली का उत्पादन	Production of Power in Bhakra Complex during 1973-74	85
2750.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अमरीकन सर्वेक्षण जहाज की प्राप्ति	Acquisition of American Survey ship by O & N.G.C.	86
2751.	ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों तथा ग्रामीण सहकारी समितियों की स्थापना	Setting Up of Training Centres and Rural Co-operatives for Rural Electrification.	86
2752.	राष्ट्रीय जल संसाधान परिषद तथा नदी बेसिन आयोग की स्थापना	Setting up a National Water Resources Council and River Basin Commissions	87
2753.	प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों द्वारा डीजल इजनों का खराब किया जाना	Diesel Locomotives damaged by Members of Territorial Army	88
2754.	रतलाम रेलवे स्टेशन पर यात्री सहायक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव	Proposal to open Passenger Assistance Booth at Ratlam Railway Station	88
2755.	मिलावट को रोकने हेतु, पुलिस द्वारा पैट्रोल पम्पों पर मारे गये छापे	Police raids on Petrol Pumps to check Adulteration	88

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2756.	गुना-मक्सी रेलवे लाइन चालू करना	Opening of Guna-Maksi Railway line .	89
2757.	आसाम तथा अरुणाचल प्रदेश में तेल की खुदाई	Oil Drilling in Assam and Arunachal Pradesh	89
2758.	भारतीय संविधान और केन्द्रीय कानूनों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद	Translation of constitution of India and Central Laws in Regional languages .	89
2759.	इंडियन एक्सप्लोसिब लिमिटेड द्वारा दूसरा उर्वरक संयत्र स्थापित करने की संभाव्यता	Possibility of setting up a second Fertilizer Plant by Indian Explosive Limited	90
2760.	कम्पनी अधिनियम, 1956 में परिवर्तन करने संबंधी विशेषज्ञ समिति	Expert Committee on changes in the Companies Act, 1956	91
2761.	रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एसोसिएशन, उत्तर रेलवे द्वारा वेतनमानों में समानता की मांग	Parity in Scales demanded by Railway Protection Force Association, Northern Railway	91
2762.	तेल की सप्लाई न होने के कारण महाराष्ट्र की छोटी कागज मिलों का बन्द होना	Closure of Small Paper Mills in Maharashtra for want of Oil Supply .	91
2763.	केरल में उर्वरक संयत्र की स्थापना	Setting up of a Fertilizer Plant in Kerala .	92
2764.	कन्नानुर (दक्षिण रेलवे) के निकट एझीमाला पर हाल्टिंग प्वांइट को समाप्त करना	Cancellation of Halting point at Ezhimala near Cannanore (Southern Railway).	92
2766.	नायलन धागा बनाने वाली परियोजनाओं की स्थापना	Setting up of Nylon Yarn Manufacturing Projects	93
2767.	फोरन ट्रैफिक एकाउन्टस आफिस दिल्ली (पश्चिम रेलवे) में काम करने वाले कर्मचारियों को पास सुविधा	Pass facility to staff working in FTAO, Delhi (Western Railway) . . .	93
2768.	उत्तर प्रदेश उड़ीसा तथा पांडेचेरी के लिये स्वीकृत विद्युत परियोजनाएं	Power Projects sanctioned for U.P., Orissa and Pondicherry . . .	93
2769.	रेलवे में कोयला वैगनों की कमी	Shortage of coal wagons felt by Railways .	94

अतां०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ
2770.	उत्तर रेलवे के बीकानेर तथा जोधपुर डिविज़न के रेलवे स्टेशनों पर खाद्य पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध खाद्य निरीक्षण अधिकारियों की शिकायतें	Complaints made by Food Inspectors against food stuff vendors at stations on Bikaner and Jodhpur Divisions (Northern Railway)	95
2771.	चौथी और पाचवीं योजनाओं में औषध उत्पादन का लक्ष्य	Target of drug production in Fourth and Fifth Plans	95
2772.	बड़ी सिंचाई परियोजनाओं द्वारा अर्जित लाभ-हानि	Profit/Loss incurred by Major Irrigation Projects	96
2773.	बिलासपुर तथा कटनी-बीना के बीच चल रही एक्सप्रैस गाड़ी का पेसेंजर गाड़ी में बदलना	Conversion of Express Train running between Bilaspur and Katni-Bina into a Passenger Train . . .	96
2774.	दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय का कलकत्ता से बिहार में स्थानांतरण	Shifting of D. V. C. Head Quarter from Calcutta to Bihar . . .	97
2775.	धर्मनगर से अगरतला तक रेल लाइन का निर्माण	Construction of Railway Line from Dharamnagar to Agartala . . .	97
2776.	मतदान की आयु में कमी करना	Lowering of Voting Age . .	97
2777.	मिट्टी के तेल की बिक्री संबंधी घोटाले का पता लगाना	Kerosene Sale Racket exposed .	98
2778.	नेफथा पर आधारित उर्वरकों के संबंध में भारत द्वारा अमरीका का सहयोग प्राप्त किया जाना	India seeking U. S. Cooperation regarding, Naphtha based Fertilizers . . .	98
2779.	गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा बिजली घरों की स्थापना	Setting of Power Houses by Private Sector Undertakings	98
2780.	पानीहाटी क्षेत्र और सियालदाह क्षेत्र में रेलवे भूमि का बेघर लोगों में वितरण	Allotment of Railway Land to homeless in Panihati Area and Sealdah Zone .	99
2881.	तेल की खोज का विस्तार तथा उसके लिए सोवियत सहायता	Intensified Oil exploration and Soviet Assistance therefor	99
2782.	'ज्वांइट स्टाक' कम्पनियों और उन की प्रदत्त पूंजी	Joint Stock Companies and their paid up Capital	100
2783.	विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों के कार्यकरण को विनियमित करने का प्रस्ताव	Proposal to regulate working of foreign Pharmaceutical Companies .	100

12 LSS/74—2

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2784.	कोसी परियोजनाओं की अनुमानित लागत में संशोधन	Revision of estimated Cost of Kosi Project	101
2785.	रायपुर-राजिम-धनतरी (मध्य प्रदेश) छोटी रेल लाइन का विस्तार	Extension of Raipur-Rajim-Dhanteri (Madhya Pradesh) Narrow Gauge Line	102
2786.	मध्य प्रदेश के छत्तीगढ़ क्षेत्र में यात्री तथा मालगाड़ी सेवायें	Passenger and Good Train services in Chhatisgarh Area (Madhya Pradesh) .	102
2787.	एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालयों में ले जाए गए मामले	Cases taken to law Courts under M. R. T. P. Act	102
2788.	चौथी योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश को मुख्य सिंचाई योजनायें	Major Irrigation facilities in Himachal Pradesh during Fourth Plan . .	103
2789.	कटिहार (बिहार) में रेलवे गोदामों से सामान की चोरी	Pilferage of Goods from Railway Godowns at Katihar (Bihar) . . .	103
2790.	पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में हिमाचल प्रदेश की सिंचाई सुविधायें देने का लक्ष्य	Target of Irrigation facilities to Himachal Pradesh in Ist Year of Fifth Plan . .	104
2791.	हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन का लक्ष्य	Target of Power Generation in Himachal Pradesh	104
2792.	पांचवी योजना के प्रथम वर्ष में हिमाचल प्रदेश के लिये रेलवे सुविधाओं के बारे में अंतिम निर्णय	Finalisation of Railway facilities for Himachal Pradesh during First Year of Fifth Plan	105
2793.	चौथी योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में रेल सुविधा संबधी लक्ष्य	Target of Rail facilities in Fourth Plan in Himachal Pradesh	105
2794.	मोदी, जे० के० मोहन मीकेन, मफत लाल और भारत टयूब (रौनक सिंह) औद्योगिक समूह	Modi, J. K., Mohan Meakan, Mafatlals and Bharat Tube (Raunak Singh) Industrial Groups	105
2795.	श्री सिंथेटिक्स को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिय आशय पत्र का जारी किया जाना	Issue of letter of Intent to Shree Synthetics for expanding their capacity . .	106
2796.	ब्यूटिल एल्कोहल के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Butyle Alcohol .	107
2797.	लेखापरीक्षा विभाग के सीनियर स्केल अफसरों की उत्तर रेलवे में प्रतिनियुक्ति	Deputation of Senior Scale officers of Audit Department to Northern Railway	107
2798.	भारतीय संविधान पर पूर्ण रूप से पुर्नविचार करने का प्रस्ताव	Proposal to review the Constitution of India Thoroughly	108

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2799.	अरकोणम (दक्षिण रेलवे) इंजीनियरिंग वर्कशाप का निरीक्षण	Inspection of Engineering Workshop at Arkonam (Southern Railway) .	103
2800.	एकाधिकार गृहों की आस्तियों में वृद्धि	Increase in the Assets of Monopoly Houses	108
2801.	अशोधित तेल के मूल्यों के बारे में भारत और इराक के बीच समझौता	Agreement between India and Iraq on Prices of crude Oil .	109
2802.	पैट्रोल तथा पैट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने के बारे में विचार	Plan to Reduce Consumption of Petrol and Petroleum Products .	110
2803.	फरक्का बांध परियोजना फीडर-नहर के ऊपरी पुलों का निर्माण	Construction of Bridges Over Farakka Barrage Projects Feeder Canal .	110
2804.	केजहूर (केरल) तथा मुदुरै (तमिलनाडु) को भारतीय रेलवे की 'माइक्रोवेब नेट वर्क' के साथ जोड़ने का प्रस्ताव	Proposal to link Kezhoor (Kerala) and Madurai (Tamil Nadu) with 'Microwave net work' of Indian Railways .	111
	अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance . . .	112
	अमरीकी परमाणु शक्ति-युक्त-विमान वाहक 'किट्टी हाक' का हिन्द महासागर में प्रवेश	U. S. Nuclear powered Aircraft Carrier 'Kitty Hawk' sailing into the Indian Ocean	112
	श्री ज्योतिमर्य बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	112
	श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	113
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में	*Re.* Motion for Adjournment .	118
	अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) 1973–74	Supplementary Demands for Grants (General)' 1973-74	123
	वक्तव्य प्रस्तुत किया गया	Statement presented . .	123
	नियम 377 के अधीन मामले	Matters Under rule 377	123
	(एक) अनाज आदि के मूल्यों में कमी करने और उचित दर की दुकानों के माध्यम से अनाज का वितरण किये जाने की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के निवास स्थान के सामने महिलाओं द्वारा कथित प्रदर्शन	(i) Reported demonstration by women before West Bengal Governor's residence demanding reduction in price and distribution of foodgrains etc. through Fair Price Shops;	123
	(दो) मध्य प्रदेश के कतिपय जिलों में अनाज की कमी और वर्षा का अभाव	(ii) Failure of rains and inadequate supply of Foodgrains in certain districts of Madhya Pradesh	123

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
रेल बजट, 1974-75--सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1974-75—General Discussion	123
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra .	124
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	125
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni . . .	126
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty .	127
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह	Shri Ramshekhar Prasad Singh . . .	128
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan . .	129
श्री के० राम कृष्ण रेड्डी	Shri K. Ramakrishna Reddy .	130
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi .	131
श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B. K. Daschowdhury . . .	132
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee .	133
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A. K. M. Ishaque .	134
श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे	Shri Annasaheb Gotkhinde .	135
श्री सी० डी० गौतम	Shri C. D. Gautam	135
श्री राम भगत पासवान	Shri Ram Bhagat Paswan . .	136
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta .	137
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar .	138
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh	139
श्री टी० डी० काम्बले	Shri T. D. Kamble . . .	140
श्री मुहम्मद जमीलर्रहमान	Shri Mohd. Jamilurrahaman . .	141
श्री शंकर राव सावंत	Shri Shanker Rao Savant	141
श्री राम सूरत प्रसाद	Shri Ram Surat Prasad .	142
श्री चिरंजीव झा	Shri Chiranjib Jha .	143
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga . .	143
श्री राम प्रकाश	Shri Ram Prakash	143
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	144
डा० कैलास	Dr. Kailas . . .	144
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra	144
दर्शकों को संसद सदस्यों से मिलने से रोकने के बारे में	Re. Alleged prevention of Visitors from meeting Members of Parliament.	136

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 12 मार्च, 1974/21 फाल्गुन, 1895 (शक)

Tuesday March 12, 1974/Phalguna 21, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**

Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

'सागर सम्राट' के द्वारा की गई तेल की खोज

*265. **श्री एस० आर० दामाणी :**

श्री राम कंवर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापानी सप्लायरों से 'सागर सम्राट' की प्राप्ति के बाद उसे प्रयोग में लाये जाने संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) इसके प्रयोग में तेल की खोज में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

(1) इसे पहले 11 अक्तूबर, 1973 से अरब सागर में तारापुर संरचना में व्यधन करने के लियें इस्तेमाल किया गया था। इस संरचना में कुएं की परियोजित गहराई 4,500 मीटर थी। भूमिगत फटन, जो 2781 मीटरों की गहराई पर हुई थी, के कारण इस कुएं को अस्थाई तौर पर छोड़ देना पड़ गया था। इस कुएं में किसी वाणिज्यिक महत्व के तेल या प्राकृतिक गैस की विद्यमानता के कोई संकेत नहीं मिले हैं;

(2) इस समय 'सागर सम्राट' बम्बई हाई संरचना में 3 फरवरी, 1974 से एक कुआं खोद रहा है और 5-3-1974 को व्यधन 1505 मीटर की गहराई तक पहुंच गया था। 962-990 मीटरों के मध्यान्तर पर ड्रिल-स्टेप-टेस्ट के दौरान, तेल की विद्यमानता के संकेत थे। कुएं की खुदाई इसकी 2,000 मीटरों की परियोजित गहराई तक की जा रही है।

श्री एस० आर० दामाणी : क्या 'सागर सम्राट' का प्रयोग किये जाने से पूर्व वाणिज्यिक दृष्टि से तेल की उपलब्धता का पता लगाने के लिये कोई व्यापक सर्वेक्षण किया गया था ? दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उसी क्षेत्र में एक अन्य ड्रिलिंग प्लेटफार्म स्थापित करने के लिये बर्मा आयल कम्पनी के साथ भी कोई बातचीत चल रही है और क्या वे व्यापक सर्वेक्षण करेंगे ?

श्री देवकांत बरुआ : छिद्रण के बाद ही तेल की व्यापारिक उपलब्धता का पता लगाया जा सकता है। जहां तक सर्वेक्षण का संबंध है पहला सर्वेक्षण एक रूसी सर्वेक्षण जहाज़ द्वारा किया गया था और उन्होंने सोचा था कि वहां पर तेल मिलने की संभावनाएं हैं। तत्पश्चात् एक सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी कंपनी सी० जी० जी० ने समुद्र तल सर्वेक्षण (सी बैड सर्वे) किया था और फिर इंग्लैण्ड की आफ़शोर डाइनामिक्स और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने मिल कर उसकी समीक्षा की। इस क्षेत्र में सर्वेक्षण के बारे में हमने बर्मा आयल कम्पनी से कोई बातचीत नहीं की है। जहां तक 'बम्बई हाई' का संबंध है, वह केवल तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा छिद्रण के लिये आरक्षित है।

श्री एस० आर० दामाणी : क्या यह सच है कि सरकार एक दूसरे ड्रिलिंग प्लेटफार्म के लिये आर्डर देने वाली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्य-वाही की गई है कि 'सागर सम्राट' में पाई गई कमियां उसमें न हों ?

श्री देवकांत बरुआ : 'सागर सम्राट' में कोई बुनियादी कमियां नहीं हैं। 'बम्बई हाई' में ड्रिलिंग के लिये एक अन्य ड्रिलिग प्लेटफार्म प्राप्त करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

श्री एस० आर० दामाणी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस प्लेटफार्म पर बारह महीने काम जारी रखा जा सकता है या नहीं।

श्री देवकांत बरुआ : जी हां, यदि इस पर समुद्र की जलवायु और तरंगों की स्थिति के अनुकूल कार्य किया जाये तो वहां पर बारह महीने काम हो सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि सी० जी० जी० नामक इस फ्रांसीसी कम्पनी ने संभावित छिद्रण के लिये नौ स्थान चुने थे ? क्या यह भी सच है कि 'सागर सम्राट' इनमें से किसी भी स्थान पर तरंगों की ऊंचाई के कारण छिद्रण करने में सफल नहीं हुआ, जिसका प्रभाव सागर सम्राट में उतरने पर पड़ता है और क्या इसका एक कारण यह भी है कि 'सागर सम्राट' के पायें अत्यधिक गहराई तक चले जाते हैं जहां तक उन्हें नहीं जाना चाहिये ? क्या ये नौ स्थान, जिनके सर्वेक्षण पर हमने सी० जी० जी० कम्पनी को काफ़ी धन दिया है और अब हमें अन्य ढांचों पर छिद्रण करना पड़ेगा ? फिर क्या यह भी सच है कि 'सागर सम्राट' के इंजनों के काफ़ी कलपुर्जे जमा पड़े हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जापानी फर्म 'मित्सुभाषी' ने 'सागर सम्राट' में पुराने इंजन लगा रखे हैं ? क्या आवश्यकता पड़ने पर इनके फालतू पुर्जे मिल सकेंगे ?

श्री देवकांत बरुआ : माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न सी० जी० जी० सर्वेक्षण के बारे में पूछा है उन्होंने गहरे पानी में 13 और कम गहराई वाले पानी में तीन स्थानों का पता लगाया था। पहले प्रयत्न में समुद्र की स्थिति अनुकूल न होने और वर्षा के कारण प्लेटफार्म स्थिर नहीं हो सका। समुद्री बीमा करने वाले इन क्षेत्रों का परित्याग करने पर सहमत नहीं थे परन्तु बाद में, जैसाकि मैंने पहले बताया है, हमने एक बार पुनः आफ़शोर डाइनामिक्स नामक एक अन्य कम्पनी द्वारा तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों ने स्वयं सर्वेक्षण संबंधी आंकड़ों पर विचार किया। फिर समुद्री बीमा करने

वाले इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह संभव है और 'बम्बई हाई' में, जहां पर सी० जी० जी० ने सर्वेक्षण किया था, प्लेटफार्म बना दिया गया।

दूसरे, यद्यपि जहाज़ जापानी जहाज़ कारखाने में बनाया गया था, उसका डिजाइन बनाने वाली एक अमरीकी आफ़शोर कम्पनी थी और इन्हीं की प्रौद्योगिकी भी थी। जापानी फर्म 'मित्सुबीषी' ने इस प्लेटफार्म पर पुरानी मशीनों का उपयोग नहीं किया बल्कि उसने नवीकृत विद्युत उपकरणों का प्रयोग किया गया जिसका मूल्य 5 लाख डालर निर्धारित किया गया था जिसके लिये उन्होंने हमें 4 लाख डालर का मुआवज़ा दिया था। जहां तक फालतू पुर्जों का संबंध है, वह उपलब्ध हैं।

श्री रामसहाय पांडे : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि अधिक गहराई तक खुदाई करने से हमें कितना तेल मिल सकेगा जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जा सकेगा? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि उन देशों के नाम क्या है जिनके साथ खोज और छिद्रण के लिये सहयोग करार किये गये हैं?

अध्यक्ष महोदय: आप मूल प्रश्न से बहुत दूर चले गये हैं।

श्री देवकांत बरुआ : जहां तक 'बम्बई हाई' का संबंध है हम स्वयं इस प्लेटफार्म से छिद्रण का काम कर रहे हैं और यह काम तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया जा रहा है। हमने निःसंदेह ड्रलिंग ठेकेदारों के रूप में कुछ विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त किये हुए हैं। 'सागर सम्राट' 11 मार्च, 1974 तक 1,577 मीटर की गहराई तक पहुंच गया था। 2,000 मीटर तक की गहराई तक खुदाई की जानी है। जहां तक वर्तमान संकेत हैं, हमें छिद्रयुक्त चूना पत्थर मिला है जो निश्चय ही बहुत अच्छा शकुन है। हम इस क्षेत्र में 6 या 7 अनुमान (असेंसमेंट) कुएं बनायेंगे और तभी हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे कि कितना तेल उपलब्ध हो सकेगा। इस समय कोई अनुमान लगाना उचित नहीं होगा।

श्री समर गुह: क्या यह सच है कि किनारे पर छिद्रण के मामले में तेल का पता लगाने के लिये 10-12 बार तेल अनुमान लगाने होते हैं और उसका विकास करने के लिये लगभग 5 वर्ष लगते हैं और तट-दूर छिद्रण के मामले में तेल का पता लगाने के लिये दो या तीन बार अनुमान लगाने पड़ते हैं और उनका विकास करने के लिये 18 महीने का समय लगता है। यदि यह बात ठीक है तो क्या यह सच है कि दो छिद्रण सफल सिद्ध हो चुके हैं और बम्बई तट-दूर में तेल प्राप्त होने की काफी संभावनाएं हैं और यदि हां, तो एक अन्य ड्रिलिंग प्लेटफार्म बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या बम्बई के तट-दूर क्षेत्र में तेल की खोज करने हेतु विदेशी सहयोग के संबंध में सरकार के पास 40 आवेदन पत्र अभी पड़े हुए हैं?

श्री देवकांत बरुआ : मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि तट-दूर छिद्रण में केवल दो वर्ष का समय लगता है। हमने अपने मंत्रालय का एक दल 'नार्थ सी' को भेजा है और 'नार्थ सी' में लगभग वर्ष 1969 में तेल का पता चला था और उन्हें वर्ष 1980 में तेल मिलेगा। परन्तु इस बीच एक नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, एक परम्परागत 'आन-शोर पाइपलाइन' जिससे तेल बनाया जा सकता है और चलते-फिरते (मोवाइल) प्लेटफार्म द्वारा भेजा भी जा सकता है। यह काम थोड़े समय में किया जा सकता है। परन्तु यह कहना कठिन है कि इसमें कितना समय लगेगा? यह बात सिद्ध हो गई है कि यह काम 2 वर्ष में हो सकता है, परन्तु यह बात केवल एक स्थान पर अर्थात् नार्वे में हुई है। हम निश्चय ही चाहते हैं कि यथासंभव इस काम को शीघ्र से शीघ्र किया जाये ताकि हम कम से कम अपनी कुछ कमी को पूरा कर सकें।

जहां तक दूसरे ड्रिलिंग प्लेटफार्म का संबंध है, 'बम्बई हाई' बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में तेल मिलने का संकेत मिला है। इस क्षेत्र में दूसरा प्लेटफार्म बनाना भी ठीक रहेगा। परन्तु प्लेटफार्म एकदम उपलब्ध नहीं हैं। अतः हमें उसे खरीदना या किराये पर लेना पड़ेगा।

श्री राजा कुलकर्णी : मैं यह जानना चाहता हूं कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और अमरीकी आफ़शोर कम्पनी के काम के बीच क्या संबंध है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न से अलग बात पूछ रहे हैं।

श्री राजा कुलकर्णी : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से यह प्रश्न पैदा होता है।

श्री देवकान्त बरुआ : मैंने कहा था कि प्लेटफार्म का डिजाइन वास्तव में एक अमरीकी आफ़शोर कम्पनी ने तैयार किया था और प्रौद्योगिकी भी अमरीकी थी परन्तु इसको जापानी शिपयार्ड में केवल बनाया गया था। दूसरे प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को यह काम सौंपा गया है परन्तु उन्होंने एक आफ़शोर डाइनामिक्स को सामान्य ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया है। वे मिलकर काम कर रहे हैं। जिस जहाज़ में प्लेटफार्म बनाया जा रहा है, वह एक भारतीय कैप्टन शुलिकार द्वारा किया जा रहा है। परन्तु इस काम का यांत्रिक भाग एक अमरीकी इंजीनियर के निर्देशन में किया जा रहा है।

एक और 'कस्टम बिल्ट ड्रिलिंग प्लेटफार्म' प्राप्त करने का निर्णय

*269. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शैल्फ क्षेत्र में खुदाई कार्य में तेजी लाने के लिए एक अन्य 'कस्टम बिल्ट ड्रिलिंग प्लेटफार्म' खरीदने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कुल व्यय कितना आयेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) नए प्लेटफार्म के अभिग्रहण द्वारा या संविदाकारी द्वारा एक और उचित चल अपतटीय व्यधन यूनिट का उपयोग कर, भारतीय महाद्वीप मग्नतट भूमि के विभिन्न भागों में अन्वेषण कार्य के विस्तार करने का प्रश्न तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विचाराधीन है।

(ख) अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इस कार्य पर कितना व्यय होगा।

श्री राम भगत पासवान : सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि जिस प्रकार का दोष 'सागर सम्राट' में पाया गया है वह प्रस्तावित प्लेटफार्म में न हो ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ड्रिलिंग प्लेटफार्म के डिजाइन के बारे में कोई निर्णय किया गया है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्री देवकांत बरुआ : यदि मैंने उनके प्रश्न को सही समझा है तो मैं उसका उत्तर पहले दे चुका हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व एक विदेशी फर्म ने एक नये ड्रिलिंग प्लेटफार्म---यह आवश्यक नहीं कि वह चलता-फिरता हो---का डिजाइन बनाने की पेशकश की थी जो

उन के अनुसार बम्बई में हमारी मझगांव गोदी में बन सकता है और उसके लिये अपेक्षित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिये भी तैयार थे ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश में ही ड्रिलिंग प्लेटफार्म बनाने के लिये यथावश्यक विदेशी तकनीकी सहायता से कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि हम भविष्य में खोज कार्य के लिये देश में ही निर्मित प्लेटफार्म का प्रयोग कर सकें ?

श्री देवकांत बरुआ : जहां तक बम्बई हाई में ड्रिलिंग का संबंध है उन्हें जिस प्रकार के प्लेटफार्म की आवश्यकता होगी वह स्वतः आगे बढ़ने वाला और स्वतः ऊपर उठने वाला होना चाहिये और मेरे विचार में इस प्रकार का प्लेटफार्म अभी देश में नहीं बनाया जा सकता। हमें चलता फिरता प्लेटफार्म चाहिए एक स्थान पर खड़ा रहने वाला नहीं ।

श्री समर गुह : हाल ही में प्राप्त समाचारों से पता चलता है कि तेल प्राप्त होने की काफी अच्छी संभावनाएं हैं और यदि ये समाचार सही हो तो हम वर्ष 1977 के अन्त तक तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। इसीलिये मैं पूछना चाहता था कि क्या सरकार शीघ्र ही दूसरा प्लेटफार्म प्राप्त करने पर विचार करेगी और यदि हां तो कब तक ताकि बिना विलम्ब के उचित ढंग से तेल की खोज का काम आरंभ किया जा सके।

श्री देवकांत बरुआ : मैं माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव के लिये उनका अहसानमन्द हूं। मैं निश्चय ही इस कार्य को यथाशीघ्र करवाऊंगा ।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा डीजल पम्पिग सैटों की विद्युत् पम्पिग सैटों में परिवर्तन करना

*271. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :
श्री वी० मायावन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की डीजल पम्पिग सैटों को विद्युत् पम्पिग सैटों में परिवर्तन करने की विशेष परियोजनाओं के लिये बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता देने की योजना है;

(ख) क्या इस बारे में विभिन्न राज्यों में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) इस समय ग्राम विद्युतीकरण निगम के पास डीजल पम्प सेटों को विद्युत् पम्प सेटों में परिवर्तित करने के लिए विशेष स्कीमों को हाथ में लेने की कोई योजना नहीं है। बहरहाल, निगम के सामान्य कार्यक्रमों में डीजल सेटों को विद्युत् सेटों में परिवर्तित करना शामिल है।

ग्राम विद्युतीकरण निगम ने कुछ ऐसे राज्यों में पाइलट स्कीम के आधार पर विस्तृत अध्ययन करने आरंभ कर दिये हैं जहां पर पम्प सेटों की संख्या काफी अधिक है और जहां पर बड़ी संख्या में

डीजल पम्प प्रचालन में हों। इस समय सम्बद्ध आंकड़े, जिसमें पारेषण एवं वितरण लाइनों को प्रतिष्ठापित तथा सुदृढ़ करने, अतिरिक्त विद्युत् की आवश्यकता, पम्प सेटों आदि को प्रतिष्ठापना हेतु कृषकों को वित्तीय आवश्यकताओं संबंधी आंकड़े शामिल हैं, एकत्र किये जा रहे हैं।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें ग्राम विद्युतीकरण निगम ने यह अध्ययन आरंभ किया है और क्या इस अध्ययन के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है और अंतिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इन राज्यों के नाम उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। क्योंकि इन राज्यों में डीजल सेटों की संख्या अधिक है अतः इनमें परिवर्तन के बारे में अच्छी प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है।

कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। निगम आंकड़े एकत्र कर रहा है।

इस बीच निगम, अपने सामान्य कार्य के रूप में, कुछ डीज़ल सेटों को विद्युत् सेटों में बदलने का काम भी करने लगा है परन्तु यह छोटे पैमाने पर है। अन्ततोगत्वा यह बात योजना आयोग द्वारा की गई वित्तीय व्यवस्था पर निर्भर करती है कि निगम को इस दिशा में कितना काम करना है।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या यह सच है या नहीं कि गुजरात सरकार यह अध्ययन इस लिये आरंभ नहीं करवा सकी क्योंकि वहां के सरकारी कर्मचारियों के मन में उत्तेजना है और वे भी उस लोकप्रिय आन्दोलन में शामिल हो गये जिसमें विधान सभा के विघटन की मांग की जा रही है और वहां पर प्रशासन ठप्प हो गया है। यदि हां, तो सरकार इस अध्ययन को यथाशीघ्र समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि मैंने पहले बता दिया है गुजरात उन राज्यों में से एक है जहां पर ग्राम विद्युतीकरण निगम यह अध्ययन कर रहा है और इनके सहयोग से इस कार्य को अच्छे और शान्तिपूर्ण ढंग से पूरा किया जा सकता है।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मेरा प्रश्न यह था कि गुजरात की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार का ऐसे कौनसे उपाय करने का विचार है जिससे यह अध्ययन शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जा सके ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक विस्तृत प्रश्न का संबंध है उस पर कल सभा में चर्चा की गई थी और निःसंदेह उसका प्रभाव गुजरात में सभी गतिविधियों पर पड़ा है। परन्तु जहां तक इस प्रकार की विकास संबंधी गतिविधियों का संबंध है, इसमें सब का हित होने के कारण मैंने सबसे सहयोग करने की अपील की थी।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण के काम में काफ़ी प्रगति हो रही है जबकि कुछ राज्यों में कुछ भी काम नहीं किया गया है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि सरकार अध्ययनों के परिणाम उन राज्यों को उपलब्ध करने के लिये, जो राज्य इस काम में पीछे रह गये हैं और उन पिछड़े राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वास्तव में उपरोक्त निगम पिछड़े राज्यों में विशेष ध्यान दे रहा है और मेरे पास उन सभी परियोजनाओं की सूची है जो विभिन्न राज्य में आरम्भ की गई हैं । किसी भी प्रकार के अध्ययन का परित्याग नहीं किया गया। माननीय सदस्य को सूचनार्थ मैं बताना चाहूंगा कि आसाम के लिये 12 योजनाएं हैं ।

श्री राम सहाय पांडे : सब राज्यों में से मध्य प्रदेश अधिक पिछड़ा हुआ राज्य है।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या यह सच है कि ग्राम विद्युतीकरण निगम ने बिहार को इस आधार पर अनुदान देना बन्द कर दिया है कि पहले दिये गये अनुदान को किसी अन्य परियोजना पर खर्च कर दिया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब बिहार को अनुदान देना आरंभ किया जायेगा या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने केवल दो या तीन राज्यों का उल्लेख किया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस बारे में मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से कुछ भिन्न है ।

श्री बूटा सिंह : मेरे राज्य में गरीब किसानों ने दोनों प्रकार की व्यवस्था कर रखी है । विद्युत चालित इंजन भी और डीज़ल चालित इंजन भी—परन्तु दोनों में से कोई भी नहीं चल रहे हैं । क्या मंत्री महोदय इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम डीज़ल चालित पम्पिंग सेट चलते रहें और विभिन्न राज्यों में कौन-कौन सी अग्रिम परियोजनाएं आरंभ की जाने वाली हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने कहा था कि निगम की विशेष योजनाएं आरंभ करने की कोई योजना नहीं है। परन्तु अपने सामान्य कृत्यों के रूप में यह छोटे पैमाने पर डीज़ल सेटों को विद्युतचालित सेटों में बदलता है। कुछ समस्याओं का अध्ययन करने के सिवाय कोई अन्य अग्रिम परियोजनाएं नहीं हैं जैसे अपेक्षित अतिरिक्त बिजली, ट्रांसमिशन लाइनों, पम्पिंग सेट लगाने के लिये किसानों को ऋण की आवश्यकता आदि की समस्याएं। इस संबंध में अध्ययन जारी है और अभी कोई अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अभी आंकड़े अपलब्ध होने हैं अतः धन नियत करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । मैं डीज़ल की सप्लाई के बारे में पंजाब को आश्वासन नहीं दे सकता। परन्तु जहां तक बिजली का संबंध है, हम किसी भी राज्य की सहायता करने के लिये तैयार रहते हैं। हम पड़ोसी राज्य से अपील करते हैं कि वह उस राज्य को कुछ बिजली सप्लाई कर दे। पंजाब के मामले में पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का रवैया काफी सहानुभूति पूर्ण है और वह नांगल उर्वरक संयंत्र की खपत को लगभग एक महीने के लिये कम करने पर सहमत हो गये हैं ताकि पंजाब को अतिरिक्त बिजली मिल सके क्योंकि उन्हें रबी की फ़सल के लिये आवश्यकता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या भारत सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से इस खतरे की सूचना मिली है कि न बिजली और न डीज़ल उपलब्ध है और इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में डीज़ल से चलाये जाने वाले छोटे कारखाने बिल्कुल बन्द हो गये हैं। इसलिये राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों को डीज़ल की न्यूनतम सप्लाई करने की मांग की है जिससे पम्पिंग सेट चलाये जा सकें ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे पम्पिंग सेट को बिजली की सप्लाई में होने वाली कठिनाइयों के बारे में पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से कोई पत्र नहीं मिला है। पश्चिम बंगाल के बारे में मेरा

विचार यह है कि विद्युत् के मामले में वहां पर कोई कमी नहीं है। उन्हें कुछ अस्थाई कठिनाई का सामना करना पड़ा था जब दुर्गापुर में एक संयंत्र जल गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में पम्पिंग सेटों के बारे में मुझे कोई पत्र नहीं मिला है।

निर्धारित स्थानों तक कोयले को ढोने के लिए रेलवे की असफलता

*274. **श्री महेन्द्र सिंह गिल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ठीक समय पर विभिन्न निर्धारित स्थानों तक कोयला ढोने में रेलवे की असफलता के कारण ही देश में कोयले की सर्वत्र कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए कोयले की ढुलाई के लिए साधनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन रेल परिवहन उपलब्ध होने में कुछ कारणों जैसे बिजली की कटौती से गाड़ी संचलन पर दुष्प्रभाव, अगणित कर्मचारी और सार्वजनिक आंदोलन, अचानक हड़ताल, 'धीरे काम करो', राजनीतिक बन्द, पटरियों पर धरना देना जिससे गाड़ी चलने में रुकावट हो, लाइन की टूट-फूट आदि के कारण बारम्बार बुरा प्रभाव पड़ा। यदि काम की सामान्य स्थिति हों तो विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए कोयले की ढुलाई की मांग पूरी करने में रेलों को कोई कठिनाई नहीं होगी।

Shri Mohinder Singh Gill: I would like to know whether this year the coal supplies made to Punjab are more or less as compared to last year ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: About what type of coal the hon. Member is asking about? Steam Coal, slake coal or which coal ?

Shri Mohinder Singh Gill: Details should be given in respect of all varities separately.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: So far as steam coal which is used for industry is concerned, the minimum need of the industry has been fulfiled.

Shri M. C. Daga: How many trains are not in operations in Rajasthan due to coal shortage and since when ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: I do not have separate figures about Rajasthan.

Shri M. C. Daga: All the trains in Rajasthan have been stopped due to coal shortage.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: Not all the trains.

Shri M. C. Daga: Mr. Speaker, Sir, my question has not been replied to.

Mr. Speaker: If the hon. Member wants specific information other than general question, they should give separate notice for the same.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या समाचार पत्रों में छपे समाचारों और फोटोग्राफों के माध्यम से मंत्री महोदय को यह पता लगा है कि कोयले का भारी स्टाक मुहानों पर और विशेषकर रानीगंज क्षेत्र की

कोयला खानों में जमा हो गया है। कोयला खानों के प्रबन्धकों का यह दावा है कि माल डिब्बे न मिलने के कारण कोयले के स्टाक नहीं उठाए जा सके। परिणामतः कोयले के कई स्टाकों में आग लग जाती है। रानीगंज क्षेत्र के मुहानों से कोयला उठाने के लिए माल डिब्बे सप्लाई करने के संबंध में सही स्थिति क्या है। यदि इस बारे में कोई कमियां हैं, तो इसके क्या कारण हैं और कार्य को शीघ्र समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जहां तक दूरवर्ती कोयला क्षेत्र का संबंध है, हमें कोई कठिनाई नहीं हैं क्योंकि हम सिंगरेनी, सिंगरोली तथा तलचेर क्षेत्रों से 2354 टन की तुलना में 2295 टन कोयला ढोते रहे हैं। रानीगंज क्षेत्र में कठिनाई हुई थी क्योंकि हमारे कर्मचारियों ने रेल सेवा अस्तव्यस्त कर दी थी। रेल सेवा को अस्तव्यस्त करना तो आसान है परन्तु रेल सेवा को फिर से सामान्य बनाने में समय लगता है। गत वर्ष की तुलना में हमने 500 वैगन प्रतिदिन कम ढोए। यदि स्थिति फिर से सामान्य हो जाती है तो हम सारा उपलब्ध कोयला ढो सकते हैं।

केरल में विभिन्न स्थानों पर तेल के लिए छिद्रण कार्य

*275. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इस समय केरल में कितने स्थानों पर तेल के लिए छिद्रण कार्य आरंभ किया हुआ है;

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में अन्य किन-किन स्थानों पर छिद्रण कार्य आरंभ किया जायेगा; और

(ग) केरल में तेल और गैस मिलने की क्या संभावनाएं हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अभी तक केरल में कहीं भी व्यधन कार्य नहीं किये हैं।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में इस समय किसी भी व्यधन कार्य की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ग) चूंकि केरल में तलछटों के कम गहन हैं अतः केरल में तेल और गैस प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या केरल राज्य में खुदाई कार्य शुरू करने के बारे में मंत्री महोदय की केरल के मुख्यमंत्री के साथ हाल ही में कोई बातचीत हुई है?

श्री देवकांत बरुआ : मुख्य मंत्री से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है परन्तु उद्योग मंत्री ने मुझे पत्र लिखा था और हमने प्राप्त जानकारी के आधार पर इस प्रश्न पर विचार किया। जहां तक थल क्षेत्रों का संबंध है, उनमें तेल पाए जाने के आसार नहीं है। जहां तक तट-दूर क्षेत्र का संबंध है, रूस के सर्वेक्षण दल ने वहां तेल पाए जाने के आसार नहीं बताये। तत्पश्चात् वर्ष 1973 में शैल इन्टरनेशनल ने एक सर्वेक्षण किया। उनके द्वारा दिया गया प्रतिवेदन विचाराधीन है। लेकिन इसी बीच कुछ विदेशी कंपनियों ने केरल में समुद्र तट-दूर तेल की खोज के लिए कहा है। हमें इतनी ही जानकारी प्राप्त है।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या मंत्रालय को विशेषज्ञों से कोई उत्साहवर्धक प्रतिवेदन मिला है ? यदि हां, तो इस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री देवकांत बरुआ : जहां तक समुद्र-तट पर तेल की खोज का संबंध है, प्रतिवेदन उत्साहवर्धक नहीं है। समुद्र तट-दूर तेल की खोज के बारे में रूसी जहाज का पहला प्रतिवेदन उत्साहवर्धक नहीं था। परन्तु वर्ष 1973 में शैल इन्टरनैशनल ने एक प्रतिवेदन दिया, जो सरकार के विचाराधीन है। साथ ही कुछ विदेशी कम्पनियों ने केरल के समुद्र तट पर तेल की खुदाई के मामले में छूट देने के लिए कहा है।

श्री आर बालकृष्ण पिल्ले : नौसेना विभाग के एक अधिकारी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में बताया गया है कि जहां जहां तेल के भंडार है वहां झींगे पाए जाते हैं। क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है और क्या सरकार उक्त वक्तव्य पर विचार कर रही है ?

श्री देवकांत बरुआ : वास्तव में मुझे याद नहीं कि मैंने अपने मंत्रालय में ऐसा विवरण देखा हो। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञ तथा अन्य विशेषज्ञ, भू-वैज्ञानिक तथा भू-भौतिकी वैज्ञानिक हमारा मार्ग-दर्शन करेंगे। किसी ने भी यह नहीं बताया कि केरल के तट दूर क्षेत्र में तेल पाए जाने की संभावना है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने बताया है कि विदेशी विशेषज्ञों द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों में कहा गया है कि तट-दूर क्षेत्र में तेल पाए जाने की संभावना है।

श्री देवकांत बरुआ : जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है ? दूसरे, एक तरफ तो सरकार कहती है कि वहां तेल पाए जाने की संभावना नहीं है, दूसरी ओर मंत्री महोदय ने स्वयं कहा कि कुछ निजी विदेशी कम्पनियों ने तेल की खुदाई के लिए बातचीत की है। उन्होंने ऐसा क्यों किया ? इसका कोई कारण रहा होगा।

श्री देवकांत बरुआ : उनके अपने कारण हो सकते हैं। मैं प्रतिवेदन में से पढ़कर सुनाता हूं। माइओसीन से अधिक पुरानी गाद नहीं पाई गई है। इस बेसिन के तलछटीकरण का इतिहास माइओसीन काल में प्रारम्भ हुआ जब पावारुर के निकट क्विलोन चूने के पत्थर, जिसकी मोटाई 65 फुट थी, पाए गए। ये चूने के पत्थर समुद्री ढंग के हैं। उसमे कम पुरानी गाद वरकलाई समुद्र तल में है जिनकी मोटाई 250 फुट है। उसमें समुद्री जीवाश्म नहीं है। उनमें मुख्यतया पीट मिट्टी पतली लिग्नाइट, धूसर रेतीली मिट्टी, गुलाबी रेतीले पत्थर (कभी कभी धारावश संस्तरण), कंकरी मिट्टी और मलवा कंकड़ था। भूमिगत जल के लिए कुछ कुओं की 1000 फुट से अधिक गहरी खुदाई की गई थी परन्तु तल नहीं मिला था। कई बार के खुदाई कार्यों में काफी मात्रा में काला कार्बनिक चूना तथा छोटे छोटे टुकड़ों के आकार वाली सीमेंट वाली मिट्टी मिली। पीत मिट्टी की कुछ पतली तह भी मिली। मिट्टियों तथा पीट मिट्टी की तहों में लौह सल्फाइड की पपड़ी तथा कहीं कहीं माइकामाइट मिली। अश्मविद्या सम्बन्धी संगुणन पारालिक तथा लागूनल किस्म का था।

जहां तक तट-दूर क्षेत्र का सम्बन्ध है, केरल तथा लक्षद्वीप के बीच रूसी तट दूर भूकंपन सर्वेक्षण जहाज चलाकर तीन सर्वेक्षण किए गए। केरल समुद्र का जलमग्न तट बहुत संकरा है। रूसी जहाज द्वारा

किए गए भूकंपनीय सर्वेक्षण से पता चलता है कि जलमग्न तट में पाई गई गाद की मोटाई बहुत कम है,. इस प्रकार तेल की संभावना की दृष्टि से परिणाम उत्साहवर्धक नहीं रहे। जलमग्न तट से दूर गाद की मोटाई बढ़ जाती है। फिर भी पानी की गहराई इतनी नहीं कि तेल की खुदाई करके तेल तथा गैस के भंडार, यदि संयोगवश वहां हो, किफायत से निकाले जा सकें।

स्थल क्षेत्र में भू-वैज्ञानिक तथा गुरुत्व सर्वेक्षण कार्य तथा तट-दूर क्षेत्र में क्षेत्रीय भू-कंपन के सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में निकट भविष्य में और कार्य करने की योजना नहीं है।

तत्पश्चात् शैल इन्टरनैशनल पेट्रोलियम कम्पनी के भू-कंपन सर्वेक्षण जहाज़ लेडी ग्लोरीता ने वर्ष 1973 में केरल समुद्र तट सहित क्षेत्रों का और सर्वेक्षण किया। इस कम्पनी ने हाल ही में अपने सर्वेक्षणों के परिणाम भेजे हैं और पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग जांच कर रहा है। कुछ विदेशी फर्मों ने भी केरल समुद्र-तट के साथ लगने वाले क्षेत्र सहित जलमग्न तटों में तेल की खोज के लिए रुचि दिखाई है। किन कारणों से उन्होंने ऐसा किया, यह मैं नहीं जानता। जैसा कि मैंने पहले कहा लेडी ग्लोरीता से हाल ही में प्राप्त रिपोर्ट विचाराधीन है।

श्री पी० के० देव : देश की समुद्री सीमा में तेल के लिए खुदाई करने के बारे में कई बार कार्यवाही की गई। चूंकि जलमग्न तट बम्बई के निकट चौड़ा तथा केरल की तरफ संकरा है। क्या सरकार समुद्री सीमा को 12 मील बढ़ाने पर विचार करेगी जैसा कि आइसलैण्ड ने किया है।

श्री देवकांत बरुआ : यह एक अच्छा सुझाव है।

Committee to suggest Measures to check Wasteful Expenditure

*279. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the economic measures adopted to slash down the non-plan expenditure in view of the heavy losses being incurred by the Railways, indicating the reduction so made in this expenditure; and

(b) whether Government propose to appoint a Committee to suggest measures for checking wasteful expenditure in the Railways ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) रेलवे व्यय में मितव्ययिता लाने के लिए जोरदार उपाय किये गये हैं। 1973-74 में **"आकस्मिकता', "यात्रा भत्ते", "दैनिक भत्ते" और "पैट्रोल की खपत"** जैसी मदों में उपयुक्त तदर्थ कटौतियां की गयीं। इसी तरह सभी राजपत्रित पदों के सृजन और उनके भरे जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध, अराजपत्रित पदों का सीमित मात्रा में सृजन और छः महीने से अधिक अवधि की रिक्तियों को न भरने, सम्मेलनों और विचार-गोष्ठियों के आयोजनों में कमी सरकारी अतिथ्य-सत्कार और स्टाफ़ कारों के इस्तेमाल पर पाबन्दी, इमारतों के पुनरुद्धार पर होने वाले व्यय सहित सभी तरह के ठाट-बाट सम्बन्धी व्यय का परिवर्जन, हवाई यात्रा के खर्च में कमी आदि के द्वारा खर्च में कटौती करने का प्रयास किया गया। रोकड़ वितरण को बजट व्यवस्था के अनुरूप नियंत्रित रखने के लिए 'राजकोष नियंत्रण' प्रणाली भी शुरू की गयी। इन उपायों के परिणामस्वरूप, 1973-74 में रेलों के संचालन व्यय में लगभग 17 करोड़ रुपये की कमी होने की प्रत्याशा है।

(ख) इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Shri M. C. Daga: Mr. Speaker, Sir, Shri Qureshi has forcefully stated the vigorous measures which are being taken to effect economy in railway expenditure. His statement is very forceful. Now, I would like to know what is the administrative expenditure of Railway Board and how the economy is being effected with regard to expenditure incurred in connection with the facilities provided to Members such as saloons etc.?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: Members generally complain about Railway Board but I want to make it clear that Railway has become a part and parcel of the life of Members of Board and they are always anxious for economy in Railway. A recent cut in Railway Board overtime has saved about rupees 1.77 lakhs. That way every attempt is being made to effect economy in Railway Board's expenditure.

Shri M. C. Daga: My question was that what is their administrative expenditure and how much ecconomy has been effected in it. I wanted to know how much economy has been effected in the maintenance of their Banglows, in the mode of their tours but a different answer has been given to me.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: As regards saloons, I am to state that these are no longer being used. Now a days there are only inspection carriages and those too, are used for some special duties. Mostly the use of saloons has been reserved for President and Governors. So far as their banglows are concernred, this is not a new facility and we do not intent to make any cut in it.

Shri M.C. Daga: It has been stated by Public Accounts Committee and others that the crores of rupees which are being spent on Railway Protection Force is wasteful expenditure. They have asked for removal of Railway Protection force because it is not serving any useful purpose and on each and every occasion they have to seek the assistance of State police. What the hon. Minister has to say in this matter ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: There is no question of removal of Railway Protection Force, on the other hand we intend to increase it.

श्री जी० विश्वनाथन्: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि रेलवे पर होने वाले कुल वार्षिक व्यय की तुलना में प्रशासनिक व्यय की प्रतिशतता क्या है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: कुल व्यय का लगभग 60 प्रतिशत कर्मचारियों पर खर्च होता है।

Shri Shankar Dayal Singh: This question has got two parts (a) and (b). Part (a) of the question has been replied but in part (b) it has been stated that such a committee will be constituted which will give its suggestions for economy in expenditure. Will you please elucidate this point ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: This has already been looked into by P.A.C. and convention committee and hence there is no need to set up a separate committee for it.

श्री पी० जी० मावलंकर: रेलवे बोर्ड बना रहे या उसे समाप्त कर दिया जाये, बिना इस प्रश्न को उठाये, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि कार्यकुशलता में कमी किये बिना और सम्पूर्ण देश की

परिस्थितियों और विशेष रूप से वातानुकूलित तथा सैलूनों आदि को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे के व्यय में कमी करने के लिए क्या सक्रिय और ठोस कदम उठाये गये हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इस प्रश्न का उत्तर तो मैं पहले ही दे चुका हूं।

श्री दीनेश चन्द्र गोस्वामी : व्यर्थ के खर्चों का एक कारण यह भी है कि वैगनों की आवाजावी में समन्वय का अभाव है, एक स्थान पर वैगन इकट्ठी हो जाती हैं तो दूसरे स्थान पर उनका एकदम अभाव होता है, अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि वैगनों की आवाजावी में समन्वय लाकर उस पर होने वाले व्यर्थ के खर्चे को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह तो एक सुझाव है जिस पर अमल किया जा सकता है।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि आचार्य कृपालानी की अध्यक्षता में जबकि वह इस सदन के सदस्य थे एक समिति का गठन किया गया था जिसका कार्य रेलवे के भ्रष्टाचार और व्यर्थ के खर्चे की जांच करना था और उस समिति ने कुछ सिफारिशें भी की थीं? क्या सरकार द्वारा उन सिफारिशों में से किसी को क्रियान्वित किया गया है?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मुझे इसके लिए अलग से सूचना चाहिए।

Shri Mohammad Ismail: There are many wasteful items on which expenditure can be curtailed. May I know how the Government is planning to curtail this expenditure—Whether Government is thinking on the lines of Indian Airline's Shri Lal Sahib or some new plan is being formulated ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: No new scheme has been prepared for it. Schemes for it are already there. We want that instead of issuing circulars or orders, there should be staff involvement in it. So that expenditure can be curtailed.

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरे माननीय मित्र, श्री गुह ने आचार्य कृपालानी की अध्यक्षता वाली समिति की बात की है। क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि आचार्य कृपालानी ने उस समिति से त्यागपत्र दे दिया था उनका कहना था कि यदि वह इस समिति में रहे तो वह भी भ्रष्टाचारी बन जायेंगे। क्या यही कारण है कि उन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया? उन्होंने सदन को बताया था कि उन्होंने समिति से क्यों अपना त्यागपत्र दिया।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैंने इस प्रश्न के लिये पूर्व-सूचना की मांग की है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अमरीकी फर्मों के साथ तेल के लिए तट-दूर छिद्रण के लिए बातचीत

*261. **श्री बेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अमरीकी तेल फर्मों के साथ तेल के लिये तटदूर छिद्रण के लिये बातचीत कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं उसका अन्तिम परिणाम क्या रहा

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देव कांत बरुआ) : (क) और (ख) कुछ अतटीय क्षेत्रों में तेल का अन्वेषण विकास तथा उत्पादन करने के लिये इस समय चुनी हुई कुछ विदेशी पार्टियों के साथ बातचीत की जा रही है। इस बारे में कोई व्यौरे बताना जनहित में नहीं है।

दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के विद्युत् प्रजनन संयंत्रों में कोयले की कमी

*262. **श्री कमलमिश्र मधुकर :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बायलर भट्टी कोयला की हाल ही में हुई कमी से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के बिजली पैदा करने वाले यूनिटों में बिजली उत्पादन न होने का ख़तरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) यद्यपि विद्युत केन्द्रों पर कोयले के भंडारों का सामान्य स्तर निम्न हो रहा है, हाल ही में ऐसा कोई अवसर नहीं आया है जबकि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के विद्युत उत्पादन संयंत्रों के लिए कोयले की कमी से विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ हो। कोयला उपलभ्यता स्थिति की रेलवे बोर्ड में स्थापित अन्तर्मंत्रालय नियंत्रण कक्ष द्वारा दैनिक आधार पर जांच की जाती है और उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए तुरन्त उपचारी कार्यवाही की जाती है।

पश्चिम कोसी नहर परियोजना

*263. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम कोसी नहर परियोजना के कार्य का जनवरी, 1974 में उद्घाटन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस योजना की स्वीकृति दे दी है; और

(ग) इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां। पश्चिमी कोसी नहर के भारतीय भाग पर कार्य का उद्घाटन जनवरी, 1974 में किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत 41.62 करोड़ रुपये है। इस परियोजना से बिहार में लगभग 3.25 लाख हेक्टेयर भूमि और नेपाल में 0.26 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधाए उपलब्ध होंगी।

Prices of Articles covered by the Drugs (Price control) order, 1970 and the Synthetic Rubber (Price Control) Order, 1969

*266. **Dr. Laxmi Narayan Pandeya:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether during the last three years no changes have been made in the prices of articles covered by the Drugs (Price Control) Order, 1970 and the Synthetic Rubber (Price Control) Order, 1969; and

(b) If so, reasons therefor?

The Minister of state in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawas Khan) : (a) No, Sir. Changes have been made in the prices of the articles covered by the Drugs (Price Control) Order, 1970 and the Synthetic Rubber (Price Control) Order, 1969 wherever justified.

(b) Does not arise.

सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों को हुआ वार्षिक घाटा

*267. **श्री एम० सुदर्शनन्:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों को लगभग 50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आल इंडिया रेलवे एकाउन्ट्स एम्पलाइज एसोसियेशन की कार्ड पास और कम्प्लीमेंटरी पासों के लिये मांग

*268. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया रेलवे एकाउन्ट्स एम्पलाइज़ एसोसिएशन ने रेलवे के सभी कर्मचारियों के लिए निःशुल्क रिहायशी कार्ड पास तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये कंप्लीमेंटरी पास जारी करने के लिए अभ्यावेदन किया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मांगों पर क्या निर्णय किया गया है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Discussions at the Conference on Oil Crisis Held in Washington

*270. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether India has received any information about the Conference of 13 countries on oil crisis held in Washington recently ;

(b) whether any new scheme has been formulated there at for oil exploration and expansion thereof ; and

(c) if so, the broad features thereof ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri D.K. Borooah): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does no arise.

पूर्वोत्तर-रेलवे में गंभीर श्रम स्थिति

*272. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में गंभीर श्रम स्थिति के क्या कारण हैं; श्रौर

(ख) इस स्थिति के समाधान के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे में श्रमिक स्थिति गंभीर नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रासाम तथा गुजरात में तेल भंडारों की खोज

*273 **श्री डी० डी० देसाई** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **पेट्रोलियम श्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रासाम तथा गुजरात के तेल भंडारों की खोज ग्रभी तक पूरी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; श्रौर

(ग) उनकी पूर्ण खोज के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम श्रौर रसायन मंत्री **(श्री देवकांत बरुग्रा)** : (क) जी, हां।

(ख) (i) ग्रसम श्रौर गुजरात में बहुत से तलछटी क्षेत्र हैं, जिनके कुछ भागों में खराब एवं खतरनाक भू-भागीय स्थिति होने के कारण पहुंचा नहीं जा सकता,

(ii) तेल ग्रन्वेषण कार्य में विशेष रूप से जहां पर भू-भागीय स्थिति ग्रनुकूल है, कुछ खराब एवं खतरनाक हो, पर्याप्त समय लगता है।

(iii) उन क्षेत्रों में से जहां पर भू-भागीय स्थिति ग्रनुकूल है, कुछ क्षेत्रों का दूसरे क्षेत्रों की तुलना में कम प्राथमिकता दिए जाने के कारण ग्रभी विस्तरित ग्रध्ययन करना शेष है।

(iv) कुछ क्षेत्रों, जहां पर कुछ कार्य किया गया है का अभी आधुनिक उपकरणों आदि की सहायता से अध्ययन करना शेष है।

(ग) असम और गुजरात के उन तलहटी क्षेत्रों में जहां पर अभी तक तेल अन्वेषण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है इस कार्य को भू-भागीय तथा भू-भौतिकीय सर्वेक्षणों तथा उसके बाद उपर्युक्त संरचनाओं पर जो इन सर्वेक्षणों के आधार पर छांटी जायेगी अन्वेषी व्यधन कार्य द्वारा और अधिक बढ़ाया जाएगा।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान नई रेल लाइनों के लिये कुल धनराशि का नियतम

*276. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नई रेल लाइनों के लिये कुल कितनी धनराशि का नियतन किया गया है; और

(ख) कितनी और कौन-कौन सी रेल लाइनों का सर्वेक्षण कर लिया गया है और उन्हें पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये विचार किया जा रहा है।

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) अब तक पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नयी लाइनों के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1974-75 में निम्नलिखित नयी लाइनों के निर्माण का प्रस्ताव है:—

(1) धर्मनगर से कुमारघाट तक एक नयी मीटर लाइन का निर्माण (उत्तरी परिषद् से कहा गया है कि वह इसकी लागत पिछड़े हुए पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए अलग रखी गयी धन-राशि में से वहन करे)।

(2) नडिकुडे से बीबीनगर तक एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण।

(3) रोहतक से भिवानी तक नयी बड़ी लाइन।

(4) मुरादाबाद और रामपुर से. रामनगर और काठगोदाम तक बड़ी लाइनों की व्यवस्था।

(5) झारपुर से लौकहा बाजार तक नयी मीटर लाइन का निर्माण।

(6) सकरी से हसनपुर तक एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण।

(7) नाखापुरा से वांसपानी तक एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उपयुक्त ढंग से चरणबद्ध रूप में निर्माण शुरू करने और उसे चलाते रहने के एकमात्र उद्देश्य से निम्नलिखित नयी लाइनों के लिए सर्वेक्षण किये गये हैं। शर्त यह है कि इन

12 LSS/74—4

के और चालू परियोजनाओं के लिए वर्ष प्रतिवर्ष और योजनावधि में समग्र रूप से अतिरिक्त साधनों का नियतन हो :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	टिप्पणी
1.	ढल्ली-सजहारा-जगदलपुर नयीं लाइन . .	प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण किया जा रहा है।
2.	भावनगर-तारापुर	इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण 1974-75 में किये जाने का प्रस्ताव है।
3.	दासगांव-मंगलूर	दासगांव और रत्नागिरि के बीच अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण तथा रत्नागिरि और मंगलूर के बीच खानिक जांच का काम 1974-75 में किये जाने का प्रस्ताव है।
4.	कुमारघाट-अगरतल्ला-सवरूम	अखौरा-अगरतला और कैलाशहर-सवरूम का यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है।
5.	सिलचर-जिरीबाम	इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है।
6.	नंगल डैम-तलवाड़ा	यातायात सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण 1974-75 में किये जाने का प्रस्ताव है।
7.	मालदह-बेलुरघाट	ओल्ड मालदह से बेलुरघाट तक बराता गाजल नयी बड़ी लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है।
8.	डेहरी आनसोन-पिपराडीह	अन्तिम मार्ग-निर्धारण एवं यातायात सर्वेक्षण 1974-75 में किये जाने का प्रस्ताव है।
9.	देवतर-डुमका-रामपुर हाल्ट	इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण 1974-75 के बजट में शामिल कर लिया गया है।
10.	गया-राजगिर	इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण 1974-75 में किये जाने का प्रस्ताव है।

गाजियाबाद में सिगनल वर्कशाप से लोहे की सामग्री और कोयले की चोरी की जांच

*277. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **रेल मंत्री** गाज़ियाबाद में सिगनल वर्कशाप से लोहे की सामग्री और कोयले की चोरी के बारे में 18 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5298 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लचीले इस्पात की चादरों की चोरी की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) क्या प्रशासन द्वारा गाजियाबाद में तीन वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को वहां से स्थानांतरित किया जाएगा ताकि समाजविरोधी और अवांछनीय तत्वों के साथ उनका सम्पर्क न रहे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : इस मामले की अभी जांच हो रही है।

(ग) जी हां।

कैप्रोलैक्टम और डी० एम० टी० का निर्माण करने वाले कारखाने

*278. **श्री मधु लिमये :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नायलोन फिलामेंट धागा/चिप्स और पोलिएस्टर धागा/रेशा बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में काम आने वाले कैप्रोलैक्टम और डी०एम०टी० का निर्माण करने वाले कारखानों में पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि नहीं तो सरकार ने उत्पादन आरम्भ करने/शीघ्र ही पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) जी नहीं।

(ख) इण्डियन पेट्रो-कैमिकल कारपोरेशन लिमिटेड के डी०एम०टी० एकक को प्रतिवर्ष 24,000 मीटरी टन की क्षमता से आयातित पैराजाइलीन, जो डी०एम०टी० के लिए मुख्य कच्चा माल है, के साथ मार्च, 1973 में प्रारम्भ किया गया। विश्वबाजार में पैराजाइलीन की अनुपलब्धता के कारण, यह यूनिट अगस्त, 1973 में बन्द हो गया। सितम्बर, 1972 में चालू इण्डियन पेट्रो-केमिकल के पैराजाइलीन यूनिट से पैराजाइलीन की उपलब्धता के साथ सितम्बर, 1973 में इसे पुनः चालू किया गया। पैराजाइलीन संयंत्र में प्रोपेन गैस कम्प्रैशर के खराब कार्य करने के कारण, डी०एम०टी० के उत्पादन को अभी स्थिर नहीं रखा गया। डी०एम०टी० संयंत्र को जल्दी पुनः चालू करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

मेसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी हाल ही में कैप्रोलैक्टम के प्रतिवर्ष 20,000 मीटरी टन के उत्पादन के लिए एक संयंत्र का निर्माण कर रहा है। उनके संयंत्र में 1974 के मध्य तक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की आशा है। आशा है यह 1976-77 में पूर्ण निर्धारित क्षमता को प्राप्त करेगा।

शाहदरा के निकट रेल गाड़ियों की टक्कर

*280. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 फरवरी, 1974 को शाहदरा दिल्ली के निकट दो रेल गाड़ियों में टक्कर हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके फलस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये तथा आहत हुए और रेलवे को अनुमानतः में कितनी हानि ई;

(ग) क्या इस दुर्घटना के कारण जानने के लिये कोई जांच की गई है, और यदि हां, तो उसका सारांश क्या है; और

(घ) क्या हताहतों को कोई मुआवजा दिया गया है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हाँ।

(ख) इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तथा एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ। इसके अतिरिक्त, 35 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं। रेल सम्पत्ति को लगभग 68,000 रु० की क्षति पहुंचने का अनुमान है।

(ग) रेल संरक्षा के अपर आयुक्त के अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार, जिन्होंने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की यह टक्कर रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई।

(घ) मृतक के आश्रितों तथा घायल व्यक्तियों को अभी तक कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया है फिर भी अनुग्रह के रूप में, कुल मिलाकर 100 रुपये की राशि वितरित की गयी है।

26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली विदेशी रसायनिक फर्मों द्वारा अपना लाभ अन्य वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जाना

2605. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली विदेशी फर्में मुख्यतया भारत में कमाये हुए मुनाफे को प्रसाधन-सामग्री, प्रयोगशाला के रासायनिक पदार्थों, कीटनाशी पदार्थों, पशु-चिकित्सा सम्बन्धी मदों और खाद्य-पदार्थों जैसी वस्तुओं के उत्पादन के लिये गत तीन वर्षों से पूंजी के रूप में लगा रही है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी प्रभुत्व वाली कितनी फर्मों ने इस प्रकार के विविधीकरण का लाभ उठाया है;

(ग) क्या इस विविधीकरण का उद्देश्य उन मामलों में मूल्य नियंत्रण प्रतिबन्धों से बचना है जिनमें 15 प्रतिशत से अधिक मुनाफे की अनुमति नहीं है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन फर्मों से औषधि की प्रत्येक मद के लिये लागत लेखा प्रणाली का प्रयोग करने के लिये करने का है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) औषधों का निर्माण करने वाली कम्पनियों, जिनमें 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी है, और जो अभेषजीय मदों का निर्माण भी करती है। की सूची संलग्न है। इनमें से बहुत सी फर्में औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के लागू होने से पहले भी अभेषजीय मदों का निर्माण करती रही हैं। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत कम्पनियों को औषधियां निर्माण करने की अपनी क्षमता के बारे में अलग अलग हिसाब रखना पड़ता है। विभिन्न औषधियों का निर्माण करने के लिये इस्तेमाल होने वाले संयंत्र तथा उपकरण सदैव अलग अलग नहीं होते। अतः कम्पनियों को प्रत्येक औषधि के लिये अलग अलग हिसाब रखने के लिये कहे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

फर्मों का नाम

मेसर्स ग्रलकली एण्ड कैमिकल कारपोरेशन ग्राफ इंडिया लि०

वीद्यम लिमिटेड

बूट्स कम्पनी लिमिटेड

साइनामिड लिमिटेड

ग्लैक्सो लेबोरेटोरीज लि०

जॉनसन एण्ड जॉनसन ग्राफ इंडिया लि०

मे एण्ड बेकर

फाइजर लिमिटेड

रिचर्डसन एण्ड हिन्दुस्तान लि०

सैन्डोज इंडिया लि०

स्मिथ एण्ड नेफ्यू लि०

सीवा ग्राफ इंडिया लि०

वेयर इंडिया लि०

रोक्टिट एण्ड कोलमैन ग्रॉफ इंडिया लि०

ई० मर्क लि०

चैसबरो पौण्ड्स

डैन्टल प्राडक्ट्स ग्राफ इंडिया लि०

एंगलो थाई कारपोरेशन

बरौस बैलकम एण्ड कं०

Reduction in Quantum of Coal and Kerosene for Cooking Gas Consumers in Delhi

2606. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether the quota of coal and kerosene has been reduced in respect of those who use gas in the capital;

(b) if so, the broad outlines in this regard ; and

(c) the quota of kerosene for gas users and others, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

Casual Labourers in Central Railway

2607. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of casual labourers working in the Central Railway; and

(b) whether Government propose to make them regular and if so, when ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 52918 as on 31-3-1973.

(b) Casual labourers as are found suitable by Screening Committees are already considered for regular posts as and when vacancies arise but the absorbing potential against regular posts is limited.

वर्ष 1974–75 के दौरान जल-परियोजना की स्वीकृति

2608. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चालू वार्षिक योजना में कुछ नई जल-परियोजनाएं शामिल करने की राज्यों की मांग का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निर्माणाधीन अथवा 1974-75 में क्रियान्वित की जा सकने वाली परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : 1974-75 की वार्षिक योजना में नई जल-विद्युत स्कीमों के लिए प्रावधान संसाधनों की उपलब्धता से सुसंगत राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर किया है । 1974-75 की योजना में सम्मिलित सभी परियोजनाएं सामान्यत: स्वीकृत की जा चुकी हैं ।

22 कम्पनियों की प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के बारे में जांच

2609. **श्री एम० कतामुत्तु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा व्यापार प्रतिबन्धात्मक प्रक्रिया आयोग ने नायलन फिलामेंट यार्न का व्यापार करने वाली 22 कम्पनियों और संघों की प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं की जांच करने का निर्णय किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) (क) तथा (ख) : एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने, स्वयं के मन से, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 10(क)(5) के अन्तर्गत, उसकी धारा 37 के अधीन 22 पार्टियों की जांच के लिए, जो नायलोन सूत्र कटाई कर्त्ता और नायलोन सूत्र प्रयोगकर्त्ता हैं, 30-11-73 को एक नोटिस जारी किया था । इनमें से चार नायलोन सूत्र कताई कर्त्ता हैं और शेष 18 कथित

सूत्र के प्रयोग से ग्रस्त उत्पाद के निर्माण हेतु, नायलोन सूत्र के प्रयोगकर्त्ताओं के संगठन और संस्थाएं हैं। कथित नोटिस 9 सितम्बर, 1973 को देश में कार्य कर रही कथित चार कताईकर्त्ताओं और 18 संगठन एवं संस्थाओं के मध्य हुए अनुबन्ध पर आधारित प्रतीत होता है। मामला आयोग के जांच के अधीन है।

कर्नाटक राज्य के दक्षिण कनारा जिले में पंजीकृत कार्यालय वाली कम्पनियां

2610. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **विधि न्याय, और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन कम्पनियों के कर्नाटक राज्य के दक्षिण कनारा जिले में पंजीकृत कार्यालय हैं, उनके नाम क्या हैं और उनकी भुगतान की गई और प्रदत्त शेयर पूंजी तथा आरक्षित निधि कितनी-कितनी है;

(ख) इनमें से कौन सी कम्पनियां प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां हैं; और

(ग) क्या इनमें से किसी कम्पनी पर एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक प्रक्रिया अधिनियम लागू होता है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

अनुमति पत्रों और लाइसेंसों के अधीन हुए उत्पादन का मूल्य

2611. **श्री सोमचन्द्र सोलंकी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967 तक दिये गये अनुमति पत्रों के अधीन हुए उत्पादन का मूल्य इसी वर्ष तक दिये गये लाइसंसों के अधीन हुए उत्पादन के मूल्य से कहीं अधिक है;

(ख) किस प्राधिकारी ने अनुमति/अनापत्ति पत्र जारी किये थे और क्या कुछ अनियमितताएं सरकार के ध्यान में लाई गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पूरे मामले की जांच करेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) निम्नलिखित शर्तों पर औषध उत्पादकों को प्रायः अनुमति/अनापत्ति पत्र जारी किये गये हैं :—

(i) इसके लिए कोई अतिरिक्त खाद्य एवं मशीनरी की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) कोई रायल्टी देय नहीं होगी।

(iii) इस समय प्रयोग में ट्रेड मार्क के अन्तर्गत उत्पादों का विक्रय होगा; और समय-समय पर जनरल इम्पोर्ट पालिसी (सामान्य आयात नीति) में व्यवस्थित छूट के अन्तर्गत मूल कच्चे माल के सम्बन्ध में कोई विशेष छूट नहीं होगी।

अनुमति/अनापत्ति पत्रों के अन्तर्गत उत्पादन के मूल्य को बताना सम्भव नहीं है, जैसा कि लाइसेंस के अन्तर्गत बताया गया है क्योंकि प्रत्येक सूत्रयोग के उत्पादन का ब्यौरा नहीं रखा गया है।

(ख) लाइसेंसिंग कमेटी के निर्णय के आधार पर अनुमति/अनापत्ति पत्र जारी किये गये हैं। सरकार को कोई अनियमितता की सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स ह्योयस्ट द्वारा कीटनाश एन्डोसूफन के लिये तकनीकी जानकारी दिये जाने की पेशकश

2612. **श्री सोमचन्द सोलकी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ह्योयस्ट ने, जो कि विदेशियों द्वारा नियंत्रित फर्म है, 150 टन एनलजिन के एक साथ उत्पादन के बदले में एक कीटनाशक 'एन्डोसूफन' के लिये तकनीकी जानकारी देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या इस कीटनाशी के लिये यह तकनीकी जानकारी एन० सी० एल० पूना के पास उपलब्ध है;

(ग) इस पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कितनी विदेशी मुद्रा विदेशों को जायेगी और एनलजिन की प्रस्तावित लाइसेंस-प्राप्त क्षमता के कारण कम्पनी द्वारा कितनी अस्तियां बनाई जायेंगी; और

(घ) क्या आई० डी० पी० एल० का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में देश की कुल आवश्यकता को पूरा करने के लिये 400 टन एनलजिन बनाने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनावाज खां) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना द्वारा इन्डोसलफान के उत्पादन की प्रौद्योगिकी का भी विकास किया जा रहा है।

(ग) मैसर्स होचेस्ट के आवेदन पत्र में नावलजीन के अतिरिक्त कई अन्य औषधों के उत्पादन की व्यवस्था है। नावलजीन के लिए पूंजी निवेश के आंकड़े अलग से नहीं दिये गये हैं। तथापि, नावलजीन के उत्पादन का मूल्य 2.13 करोड़ रुपया हैं तथा 58,000 रुपये का आयातित कच्चा माल बताया गया है।

(घ) जी हां।

केरल के कजाकुट्टम रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

2613. **श्री बयालार रवि** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कजाकुट्टम रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) कजाकुट्टम रेलवे स्टेशन दक्षिण रेलवे के कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम् सेन्ट्रल मीटर लाइन खण्ड पर स्थित है। इस स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए कोई लिखित अभ्यावेदन नहीं मिला है। लेकिन श्री कमलियास मौरेस, सदस्य विधान सभा, कोतल्लम्, के व्यक्तिगत अनुरोध पर इस स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए एक प्रस्ताव स्थायी

प्रक्रिया के अनुसार मण्डल उपयोगकर्ता परामर्श समिति के समक्ष अनुमोदन के लिये रखा गया था, जिसने ऐसे ही अन्य स्टेशनों की सापेक्ष प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धता पर विचार करने के पश्चात् इसका अनुमोदन नहीं किया । लेकिन रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति के परामर्श से तथा धन उपलब्ध होने पर इस प्रस्ताव को आगामी वर्षों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के प्रश्न पर फिर विचार किया जायेगा ।

कजाकुट्टम रेलवे स्टेशन (केरल) पर यात्रियों के लिए सुविधायें

2614. **श्री वयालार रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कजाकुट्टम रेलवे स्टेशन (केरल) एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जहां उस क्षेत्र के आसपास बहुत से केन्द्रीय और राज्य संस्थान स्थापित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्टेशन के प्लेटफार्म पर छत नहीं है और प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों के लिए वहां बैन्च की व्यवस्था भी नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त स्टेशन पर इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी करेशी) : (क) जी हां ।

(ख) प्लेटफार्म पर छत नहीं है । किन्तु प्रतीक्षालय में और प्लेटफार्म पर 8 बैन्चों की व्यवस्था है ।

(ग) प्लेटफार्म पर छत आदि जैसे यात्री सुविधा के कार्य की व्यवस्था रेलवे उपयोगकर्त्ता सुविधा समिति के परामर्श से की जाती है जो कि सापेक्ष प्राथमिकता और धन की उपलब्धता पर आधारित होती है । तदनुसार कजाकुट्टम स्टेशन के प्लेटफार्म पर छत सम्बन्धी निर्माण कार्य आगामी वर्ष के निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित करने पर विचार किया जायेगा ।

रेलों में विभिन्न श्रेणियों के स्थानों के लिए पात्रता

2615. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या रेल मंत्री दूसरे दर्जे के समाप्त होने पर उत्तर रेलवे और पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों द्वारा प्रथम दर्जे के पास जारी करने हेतु अभ्यावेदन के बारे में 18 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5138 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है ।

अजमेर (पश्चिम रेलवे) में काम करने वाले कर्मचारियों को देय राशि का भुगतान न किया जाना

2616. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अजमेर, पश्चिम रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली देय राशि की सूची प्राप्त हो गई है; और

(ख) उन्हें देय राशि का भुगतान न करने के क्या कारण हैं तथा सरकार ने कर्मचारियों को अविलम्ब भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : ऐसी कोई सूची नहीं मिली है । देय राशि के भुगतान से सम्बन्धित मामले जब कभी प्राप्त होते हैं, उन पर विचार दिया जाता है उन्हें तुरन्त निपटा दिया जाता है ।

बजुआ में काम करने वाले कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की अदायगी

2617. **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पश्चिम रेलवे में बजुआ में काम कर रहे कर्मचारियों से उन्हें मकान किराया भत्ता दिए जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो वहां के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) बजुआ में काम करने वाले रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान 31-7-73 से आगे नहीं किया जा सका क्योंकि बड़ौदा पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की निर्भरता की मुख्य शर्त समाप्त हो गयी ।

उत्तर रेलवे द्वारा पश्चिम रेलवे को दिल्ली में क्वार्टरों का हस्तान्तरण

2618. **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय ने वर्ष 1971 में यह निर्णय किया था कि फारेन ट्रैफिक एकाउण्टस आफिस, वेस्टर्न रेलवे, दिल्ली में काम करने वाले कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित करने के लिए उत्तर रेलवे पश्चिम रेलवे को 23 क्वार्टर हस्तान्तरित करेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच क्वार्टर हस्तान्तरित कर दिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा सरकार ने इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) अब तक पश्चिम रेलवे को 14 क्वार्टर दिये गये हैं । शेष 9 क्वार्टर उपलब्ध होने पर चरणों में हस्तान्तरित किये जायेंगे ।

उत्तर रेलवे के लेखा कर्मचारियों में से "स्टाक बेरीफायरों" का पेनल बनाया जाना

2619. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में "स्टाक वेरीफायरों" का लेखा कर्मचारियों में से पेनल बनाने के लिये नाम मंगवाये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या पेनल को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है और पेनल को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है और पेनल न होने की स्थिति में स्टाक वरीफायरों के रिक्त स्थान कैसे भरे जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ कर्मचारियों से अभ्यावेदन मिलने पर यह विचार किया गया है कि सबहेडों और स्टाक वेरीफायरों के संशोधित वेतनमानों के बारे में निर्णय कर लेने के बाद, जिसमें वेतनमानों की समता का प्रश्न भी शामिल है, पेनल को अन्तिम रूप दिया जाये । इस समय इन पदों को ग्रेड I के उन वरिष्ठतम लिपिकों में से तदर्थ आधार पर भरा जा रहा है । जो इनके लिए आवेदन करते हैं ।

तापीय संयंत्रों को कोयले की सप्लाई

2620. **श्री विश्वनाथ झुंझनवाला :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तापीय बिजली घरों को कोयले की पूरी सप्लाई हो रही है;

(ख) यदि नहीं, तो विभिन्न राज्यों में कोयले के स्टाक की कमी की क्या स्थिति है ;

(ग) क्या कोयले की कमी के परिणामस्वरूप बिजली उत्पादन में कोई कमी रहेगी; और

(घ) यदि हां, तो कितनी और आगामी छः महीनों में इससे कौन-कौन से क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) : विभिन्न विद्युत केन्द्रों की पूर्ण विद्युत जनन आवश्यकता पूरी करने के लिए कोयले की सप्लाई कायम रखने के लिये हर प्रयत्न किया जा रहा है । जबकि कुछ विद्युत केन्द्र में कई बार ऐसे अवसर आए हैं जबकि वहां केवल 1-2 दिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही कोयले का स्टाक रह गया था, कोयले की अनुपलब्धता के कारण एक अथवा दो केन्द्रों को छोड़कर किसी भी विद्युत केन्द्र को न तो बन्द करना पड़ा और न ही उत्पादन पर कोई प्रतिबन्ध लगाना पड़ा ।

तापीय संयंत्रों में कोयले की खपत

2621. **श्री विश्वनाथ झुंझनवाला :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० सी० एस० टी० समिति ने यह अनुमान लगाया है कि यदि ट्राम्बे, धुवारन, अहमदाबाद और बरौनी तापीय संयंत्रों में, ईंधन तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग आरम्भ कर दिया जाये तो 160,000 टन ईंधन तेल की बचत हो सकेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने यह भी कहा है कि प्रशासन में अधिक कुशलता से इन तापीय संयंत्रों में कोयले की खपत भी कम हो सकती है; और

(ग) क्या सरकार ने समिति के सुझाव पर विचार किया है और यदि हां, तो क्या इंधन तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग करने के बारे में कोई योजना तैयार की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी समिति ने उस ईंधन तेल की मात्रा का कोई मूल्यांकन नहीं किया है जिसे ट्राम्बे, धुवारण, अहमदाबाद और बरौनी स्थित ताप विद्युत केन्द्रों को तेल के स्थान पर कोयले का उपयोग करने वाले में परिवर्तन करके अथवा कोयले की खपत में कमी लाने के उपायों द्वारा बचत की जा सकती है । राष्ट्रीय

विज्ञान और तकनीकी समिति ने ऊर्जा संकट पर वर्किंग पेपर तैयार किया है जिसमें एक यह सुझाव दिया गया है कि ईंधन-तेल का उपयोग करने वाले औद्योगिक बायलरों को कोयला जलाने वालों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। कोयले की उपलब्धता तथा उसके विद्युत केन्द्रों तक परिवहन को सुनिश्चित करने के उपरान्त तेल ईंधन की खपत को कम करने के निमित्त एक क्रियात्मक योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक कार्यकारी दल का गठन किया जा चुका है। कार्यकारी दल ने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है। उपर्युक्त सुझाव के अतिरिक्त, स्वतन्त्र रूप से यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित यूनिटों तेल से कोयला फाइरिंग में परिवर्तित की जानी चाहिए:--

विद्युत केन्द्र का नाम	परिवर्तित की जाने वाली यूनिटों की प्रतिष्ठापित क्षमता	
(1) बरौनी (बिहार)	2×15 मै०वा० 2×50 मै०वा०	130 मै०वा०
(2) अहमदाबाद (गुजरात)	4×15 मै०वा० 2×30 मै०वा०	120 मै०वा०
(3) ट्राम्बे (महाराष्ट्र) . .	2×62.5 मै०वा०	125 मै०वा०
(4) धवारण (गुजरात)	4×63.5 मै०वा०	254 मै०वा०

इस पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

Confirmation of Employees of Eastern Railway

2622. **Shri Hukum Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of employees in the Eastern Railway at present who are temporary even after rendering more than five years service; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to make them permanent?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 5174.

(b) A special drive has been instituted for conversion of temporary posts into permanent ones wherever justified and for confirmation of the eligible staff against such posts.

Loss of property suffered by Eastern Railway due to Strike and other Agitations

2623. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the amount of loss to property suffered by the Eastern Railway during the last two years as a result of the strike by Railway employees and other political agitations; and

(b) Government's future scheme and policy to protect Railway property from being damaged?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways: (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) About Rs. 55,000/-.

(b) Ordinarily, the State Police deal with such agitations as maintenance of law and order is their responsibility. However, on such occasions the Railway Protection Force men are also deputed to assist the police and guard railway property.

In addition, sections 122 & 126 of the Indian Railways Act, 1890 have also been amended to provide for more deterrent punishment to offenders. Another section 126-A has been added therein to deal with acts pertaining to wanton destruction of railway track, bridges, station installations and such other railway property prescribing a punishment extending up to 10 years rigorous imprisonment.

Crimes on Central Railway during the last year

2624. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the total number of incidents of crime in the Central Railway registered during the last one year;

(b) the total number of persons arrested in this connection ; and

(c) the number of persons prosecuted and convicted, separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c) A statement is attached.

[*Placed in the Library. See No L.T.—6393/74*]

Passenger trains without chain pulling device on Central Railway

2625. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of passenger trains on the Central Railway in which chain pulling device does not exist;

(b) the reasons for removing the chains from these trains; and

(c) Government's future plan in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) The alarm chain has been blanked off on five passenger trains on the Central Railway on account of its frequent misuse.

(c) General position in regard to the adverse effects of alarm chain pulling on passenger trains is kept under constant review and the alarm chain is blanked off or restored as warranted by circumstances.

Success of visit of Indian Railway Delegation to New York

2626. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state;

(a) the extent of success achieved by the Railway delegation which visited New York recently in connection with taking loan from the International Development Association:

(b) salient features in this regard ; and

(c) the expenditure incurred on this Delegation?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) An agreement for a credit of $80 millions was signed with the International Development Association on 21st December, 1973, as a result of the negotiations held by the Indian Railway delegation in Washington in November, 1973.

(b) The credit is repayable in 50 years with a moratorium on repayment for the first ten years. The credit carries no interest but only a service charge of three-fourths of one per cent per annum.

The credit will finance import of components and raw materials for the manufacture of rolling stock, items for track renewal and bridge works, line capacity works, signalling and electrification schemes and plant and machinery.

(c) An estimated expenditure of Rs. 1.29 lakhs was incurred on the visit of the delegation.

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के लिए रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति का गठन

2627. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीज़न के लिये रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति के सदस्यों के क्या-क्या नाम हैं; और

(ख) उक्त समिति किस तारीख को गठित की गई और इसके निदेश पद क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें सूचना दी गयी है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-6391/74] ।

फिरोजपुर डिवीजन (उत्तर रेलवे) के लिए रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति का गठन

2628. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के फिरोजपुर डिवीज़न के लिये रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;– और

(ख) उक्त समिति किस तारीख को गठित की गई और उसके निदेश पद क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें सूचना दी गयी है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-6392/74] ।

राष्ट्रीय रेल प्रायोक्ता समिति का गठन

2629. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रेल प्रयोक्ता समिति के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ख) यह समिति कब गठित की गई और इसके निदेश पद क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) चालू अवधि 1972-74 के लिए ,राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद् का गठन अभी तक नहीं किया गया है क्योंकि परिषद् को अधिक व्यापक और प्रतिनिधिक स्वरूप प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है ।

मद्रास उर्वरक कारखाने से विस्तार के लिए आवेदन-पत्र

2630. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास उर्वरक कारखाने की क्षमता में वृद्धि करने के लिये सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) सरकार ने एन पी के उर्वरकों के उत्पादन के लिये तीसरे संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के प्रस्ताव का सिद्धान्त रूप में अनुमोदन कर दिया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Survey for Oil Deposits in Madhya Pradesh

2631. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether there are indications of large deposits of oil in Madhya Pradesh ; and

(b) whether Government have conducted any survey in this regard and if so, the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) No, Sir.

(b) Geological mapping in Madhya Pradesh which was started by the Oil & Natural Gas Commission in 1960-61, is being continued to build up the data on palaeogeography and stratigraphy in the more favourable areas fringing Madhya Pradesh.

Irrigation Projects for M.P. in Fifth Plan

2632. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the number of irrrigation projects inclusion of which in the Fifth Five Year Plan has been demanded by the Government of Madhya Pradesh but not agreed to by the Central Government; and

(b) the reasons for not approving these projects ?

The Minister of Irrigation and Power (Shri K.C. Pant) : (a) & (b) The details of the Fifth Plan of Madhya Pradesh have not yet been finalised. The Government of Madhya

Pradesh have proposed 10 new major irrigation projects for the Fifth Plan, but their inclusion would depend upon the availability of funds, clearance of inter State aspects, as well as the techno-economic feasibility of the projects.

भारतीय रेलवे संहिता का उल्लंघन करने के बारे में अखिल रेलवे वाणिज्यिक क्लर्क एसोसिएशन के अभ्यावेदन के बारे में निर्णय

2633. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **रेल** मंत्री भारतीय रेलवे संहिता का उल्लंघन करने के बारे में अखिल भारतीय वाणिज्यिक क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिवेदन के बारे में 10 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6700 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय वाणिज्यिक क्लर्क एसोसिएशन के अभ्यावेदन की जांच इस बीच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो किये गये निर्णय की रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अब सरकार को इनमें कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) यह विनिश्चय किया जा चुका है कि विवादास्पद समाचारपत्रों के पार्सलों का अवप्रभार कर्मचारियों से वसूल न किया जाय ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खराब होने वाली वस्तुओं के लिए मध्य रेलवे में भाड़ा वसूल करना

2634. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **रेल** मंत्री माल पर कम राशि वसूल करने के कारण बकाया राशि और मध्य रेलवे द्वारा खराब होने वाली वस्तुओं पर भाड़ा वसूल करने के बारे में 19 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5041 तथा 20-3-73 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3825 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्धारित राशि से कम प्राप्त हुई राशि को वसूल करने के लिए मध्य रेलवे के मुख्य वाणिज्यक अधीक्षक के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं;

(ख) व्यापारियों से कम प्राप्त हुई राशि को वसूल न करने के क्या कारण हैं;

(ग) कम प्राप्त हुई राशि को व्यापारियों से वसूल करने के बजाय उसे कर्मचारियों के वेतन से ही सदैव वसूल करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस न्यून-राशि घोटाले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से जांच कराने और निम्न वेतनभोगी रेल-कर्मचारियों को बचाने के लिए आदेश देने का सरकार का क्या विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) मध्य रेल प्रशासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश सदाशयी थे और बाद में उन्हें ठीक भी कर दिया गया था ।

(ख) और (ग) वर्तमान नियमों के अनुसार माल की सुपुर्दगी से पहले जिस अवप्रभार का पता चलता है, परेषक अथवा परेषिती से उसकी वसूली केवल माल की सुपुर्दगी के समय करनी होती है । जब कर्मचारी इस अवप्रभार का पता लगाने और माल की सुपुर्दगी के समय उसे वसूल करने में

असफल रहते हैं, केवल तभी उन्हें कमी को पूरा करना पड़ता है । इस प्रभार के भुगतान के लिए कर्मचारी सम्बन्धित पार्टियों से भी आग्रह कर सकते हैं ।

(घ) जी नहीं ।

त्रिपुरा खुदाई स्थल के परियोजना प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

2635. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सतर्कता आयुक्त ने त्रिपुरा खुदाई स्थल के परियोजना प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये त्रिपुरा का दौरा किया; और

(ख) यदि हां, तो उनकी जांच के क्या निष्कर्ष निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) आयोग के त्रिपुरा, प्रायोजना अधिकारी के विरुद्ध कुछ आरोपों की जांच करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के सर्तकता अधिकारी त्रिपुरा गये । उनके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट आयोग के अध्यक्ष के विचाराधीन है ।

योजना मंत्री का कुछ तेल उत्पादक देशों का दौरा

2636. **श्री एस० पी० सामन्त :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना मंत्री श्री डी० पी० धर की तेल उत्पादक देशों की हाल ही की यात्रा कहां तक सफल रही है; और

(ख) क्या तेल के बारे में बातचीत करने के लिये ही वह वहां गये थे ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) योजना मंत्री ने ईराक और भारत के आपसी हितों के कई मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए ईराक का दौरा किया था जिसमें भारत को अशोधित तेल की सप्लाई का मामला भी शामिल था । इस अवस्था में विचार-विमर्श ब्यौरे देना जनहित में नहीं है ।

बड़े व्यापार गृहों से व्यक्तिगत उद्यमों का अलग किया जाना

2637. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बड़े व्यापार गृहों से व्यक्तिगत उद्यमों को अलग करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : इस उद्देश्य के अध्ययन के लिए गठित आन्तरिक सरकारी समूह ने एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के संशोधन के विधान, जिससे कि केन्द्रीय सरकार को, उचित मामलों में, बड़े औद्योगिक गृहों के नियंत्रण से राष्ट्रीय महत्व की कम्पनियों को, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के परामर्श के अलग करने को आवश्यक शक्तियां प्रदत्त की जा सकें, सुझाव दिया है । सुझाव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

Meeting of Consultative Committee During Intersession period

2638. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the meetings of the consultative Committees attached to the various Ministries are held as a rule, at least once after every session of Parliament;

(b) whether no meeting of the Consultative Committee attached to the Railway Ministry has been held between the ninth and tenth Sessions of Parliament;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the action taken by Government to check such recurrences ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways: (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) & (b) Yes.

(c) & (d) It was not found feasible to hold the Consultative Committee meeting during the brief intersession period between the last week of December, 1973 and third week of February, 1974 owing to preoccupation of the Minister for Railways in connection with staff agitations and meetings with Trade Union leaders as also the work relating to the preparation of the Railway Budget for 1974-75. However, every effort is being made to hold these meetings regularly.

Expenditure on Power Development Programme

2639. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the expenditure on power development programmes in the previous five year plans was for more than allocations but achievements fell short of the targets ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken to achieve the targets set under the Fifth Five Year Plan ?

The Minister of Irrigation and Power (Shri K.C. Pant) : (a) Except in the First Plan, the actual expenditure on power development programmes has exceeded the planned outlay in all the Plan periods. There have been shortfalls in the achievement of physical targets in all the Plan periods.

(b) The main reasons for these are: (i) increase in the costs of projects due to escalation of prices of materials, plants and equipment; (ii) increase in labour costs; (iii) effects of the devaluation of the Rupee in 1966; (iv) inadequate investigation and deficiencies in project preparation, specially in respect of Hydro-Electric Projects; (v) non-availability of essential construction materials and funds at the appropriate time; (vi) labour troubles; (vii) delays in obtaining plants and equipment; and (viii) organisational and management weaknesses.

(c) The following steps are being taken to ensure achievement of the targets set for the Fifth Plan:

(1) The proposals for restructuring of the electricity industry are being finalised, so as to remove organisational and management weaknesses.

(2) Steps are being taken to ensure adequate and timely availability of funds and other materials inputs for power projects.

(3) The greater indigenous availability of plants and equipment would remove uncertainties associated with large scale imports.

(4) Where indigenous capability or availability of plants and equipment or inputs is not adequate, it is proposed to make timely imports.

(5) Effective monitoring and evaluation arrangements are being introduced at all levels, so as to improve management functions and remove likely bottlenecks in time.

निर्वाचनों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली आरम्भ करना

2640. **श्री पी०एम० मेहता :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लोक सभा तथा विधान सभाओं के निर्वाचनों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली आरम्भ करके निर्वाचन-प्रक्रिया में एक प्रमुख सुधार करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में अन्तिम निर्णय संभवतः कब तक कर लिया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबन्ध में चालू सत्र के दौरान कोई विधेयक पुरःस्थापित करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ?

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसर्स होयस्ट से औद्योगिक लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र

2641. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स होयस्ट ने हाल ही में औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनके आवेदन-पत्रों पर विचार करने में कुछ रियायत बरती गई है और भारतीय क्षेत्र के हितों की उपेक्षा की गई है ; और

(ख) क्या इससे पहले ही से एक बड़े गृह के एकाधिपत्य में वृद्धि नहीं हो जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । मैसस होयस्ट फार्मास्यूटिकल्स लि०, बम्बई ने औषधियों एंव भेषजों की विभिन्न मदों जिन में कुक्कुटादि एंव पशुओं के लिये वैक्सीन भी शामिल है के निर्माण हेतु औद्योगिक लाइसेंसों के लिये विभिन्न आवदन-पत्र भेजे हैं ।

(ख) और (ग) जी नहीं । आवेदन पत्रों पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है और उन अनुमतियों की अवहेलना किये बगैर जो एम आर टी पी ऐक्ट के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

बिजली के संकट को दूर करने के लिए बिजली उद्योग के संगठनात्मक ढांचे को युक्तिसंगत, पुर्नगठित तथा सुदृढ़ करना

2642. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में बिजली से भारी संकट को दूर करने के लिए बिजली सप्लाई उद्योग के संगठानात्मक ढांचे को विभिन्न स्तरों पर युक्तिसंगत, पुनर्गठित तथा सुदृढ़ करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो चौथी योजना में बिजली संबन्धी लक्ष्यों में गिरावट पर चिन्तत होते हुए आयोग ने समस्याओं के समझने के उद्देश्य से पिछले कार्यकरण का विस्तृत अध्ययन करने का सुझाव दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) क्या योजना आयोग यह अनुभव करता है कि पांचवीं योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति अधिकतम आयोजन डिजाइन बनाने, निवेश करने तथा क्रियान्विति तरीकों में सुधार करने पर ही निर्भर करती है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) विद्युत् परियोजनाओं के कार्यान्वियन में शीघ्रता लाने तथा विद्युत् संयंत्रों तथा प्रणालियों को प्रचालन दक्षता को समुन्नत करने दोनों के संबन्ध में कार्य निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से विद्युत् प्रदाय उद्योग को पुनर्रचना तथा उसके वैज्ञानिक पुनर्गठन पर भारत सरकार सक्रियता से विचार कर रही है ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर में निर्दिष्ट प्रस्तावों को पिछले कार्य निष्पादन में कमियों के पाए जाने के कारणों के अध्ययन करने के उपरान्त तैयार किये गये हैं।

(ग) इस प्रश्न पर विभिन्न अन्तः विभागीय बैठकों में विचार-विमर्श किया गया था तथा इस संबन्ध में ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं जिन पर केन्द्रीय सरकार सक्रिय रूप में विचार कर रही है । उनको अन्तिम रूप देने तथा कार्यान्वित करने से पूर्व, उन पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जायगा ।

(घ) जी, हां ।

कच्चे तेल के भंडार बनाने के लिए संभावित दस वर्षीय योजना

2643. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कच्चे तेल के भंडार बनाने के लिये "दस वर्षीय" संभावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) इसके लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि नियत की गई हैं ;

(ग) तेल के मूल्यों में हुई वर्तमान वृद्धि को देखते हुए क्या सरकार यह स्वीकार करेगी कि नियत की गई उक्त राशि कच्चे तेल संबन्धी आवश्यकता के लिये पर्याप्त होगी; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में मुख्य विवरण क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) विशेषज्ञों के एक भारतीय रूसी दल ने सितम्बर, 1971 में प्रथम पंच वर्षीय अवधि के लिये कार्य का एक यर्थाथ कार्यक्रम और बाद की पंच वर्षीय अवधि के लिये कार्य का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया था। प्रथम 5 वर्षीय योजना कार्यक्रम को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पंच वर्षीय योजना कार्यक्रम के साथ उपयुक्त रूप से जोड़ा गया है और बाद के 5 वर्षों के लिये प्रक्षेप बनाये गये हैं। पंच वर्षीय योजना के दौरान 70 मिलियन मीटरी टन के और बाद के पांच वर्षों में 132 मिलियन मीटरी टन के प्राप्य भंडारों का स्थापित किया जाना पांचवीं योजना की मुख्य बातें हैं।

(ख), (ग) और (घ) इस समय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिये पांचवीं पंच वर्षीय योजना के लिये 697.42 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। 1978-79 तक प्रतिवर्ष 8.42 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल के उत्पादन की वार्षिक दर प्राप्त करने के लिये इसे काफी समझा गया है। यदि बम्बई हाई पर हाल ही की खोज की वाणिज्यिक संभाव्यत स्थापित हो गई तो इस क्षेत्र के शीघ्र समुपयोजन के लिये और राशियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस संरचना के बारे में और सूचना उपलब्ध होने के पश्चात् ही ब्यौरे तैयार किये जा सकते हैं।

26 प्रतिशत से अधिक विदेशी ईक्विटी वाली विदेशी औषध फर्मों का पूंजीनिवेश

2644. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशी औषध फर्मों (26 प्रतिशत से अधिक विदेशी ईक्विटी) ने कितनी पूंजी लगाई तथा कुल कितनी बिक्री की तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के अनुसार अनेक औषधियों (बल्क ड्रग्स) में उन्होंने कुल कितनी पूंजी लगाई ;

(ख) क्या यह सच है कि अनुमति पत्रों, सी०ओ०वी० लाइसेंसों तथा विविधीकरण जैसी सुविधाओं के लिये विदेशी फर्मों द्वारा दिये जाने वाले आवेदनपत्रों की अविलम्ब जांच-पड़ताल की जाती ह; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे भारतीय औषध उद्योग को खुली छूट दिये जाने पर विचार करेगी जिनका अनेक औषधियों के उत्पादन के लिये अनेक औषधियों में बिक्री का लगभग 39 प्रतिशत पूंजी निवेश है, तथा ऐसी विदेशी फर्मों पर भूलभूत उत्पादन तथा अन्य सुविधाओं के लिये प्रतिबन्ध लगाएगी जिनका अनेक औषधियों में पूंजी निवेश उनकी बिक्री का लगभग 60 प्रतिशत है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) एक विवरण पत्र, जिसमें औषधों एवं भेषजों का निर्माण करने वाली उन फर्मों, जिनमें 26% से अधिक विदेशी साम्य पूंजी है, के नाम, उनकी वर्तमान साम्य पूंजी तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उन की विक्री के बारे में उल्लेख है, संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया / देखिये संख्या एल०टी०—6393/73] प्रपुंज औषधों में उन के निवेश के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) 1966 से मंत्रालय द्वारा कोई अनुमति पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं। विविधीकरण सरकार की नीति, जो समय समय पर लागू हो, द्वारा नियमित किया जाता है। सी०ओ०वी० या अन्य औद्योगिक लाइसेंस देने के लिये विदेशी फर्मों के आवेदन पत्रों की अविलम्ब जांच पड़ताल करने में कोई तरजीह नहीं दी जाती है।

(ग) भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देने तथा विदेशी फर्मों के कार्यकरण को नियमित करने के लिये उठाये कदमों का उल्लेख 27 नवम्बर, 1973 के लोक सभा के ता० प्रश्न संख्या 227 के उत्तर में दिया गया है ।

औषध तथा भेषज विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन

2645. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या सरकार को औषध तथा भेषज विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस. तारीख को प्राप्त हुआ ;

(ग) विशेषज्ञ दल के क्या निष्कर्ष हैं तथा उसने क्या-क्या सिफारिश की हैं; और

(घ) उक्त प्रतिवेदनों को संसद् के समक्ष कब पेश किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) शायद, 24 प्रपुंज औषध की संरचना लागत की जांच के लिये औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो अध्यक्ष की अध्यक्षता में संगठित कार्यकारी दल के बारे में हवाला है । दल की रिपोर्ट, चार भागों में, अप्रैल और अक्तूबर 1972 के बीच में प्राप्त हुई थी ।

(ग) और (घ) दल की सिफारिशें अभी तक विचाराधीन है ।

कोयले के लदान में लगाये गये नैमितिक श्रमिक

2646. **श्री सी० के० जाहिर शरीफः** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कोयले तथा वैगनों के समय पर उपलब्ध न होने के कारण कोयले के लदान में लगे श्रमिकों की अपेक्षा करते रहना पड़ता है और उनका समय व्यर्थ होता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार नैमितिक श्रमिकों को पूरा सप्ताह काम तथा पूरे ही सप्ताह की मंजूरी देने की व्यवस्था करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे के लिये एक यूनियन

2647. **श्री भोगेन्द्र झा :**

मौलाना इसहाक सम्भली :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में केवल एक यूनियन रखने संबन्धी सरकार के निर्णय पर केन्द्रीय कर्मचारी संघो की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) यूनियन को मान्यता देने के लिये रखे गये प्रस्तावित मानदंड क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) रेल मंत्री ने आल इंडिया रेलवेमैन्स फैड्रेशन और नेशनल फेड्रेशन आफ इण्डियन रेलवेमैन तथा चार केन्द्रीय श्रम संगठनों के नेताओं

के साथ श्रमिक संबन्धों पर 4-2-1974 को जो सम्मेलन किया था उसमें यह ग्राम राय बनी थी कि रेलों में केवल एक ही यूनियन होनी चाहिये जो इतनी लोकप्रिय और व्यापक हो कि रेल कर्मचारियों की सभी' कोटियों और शिल्पों का प्रतिनिधित्व करे।

बेसिक औषधियों के उत्पादन को बढ़ाने की योजना

2648. **श्री बसन्त साठे :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन रक्षक बैसिक औषधियों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिये उनका उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) देश में प्रपुंज औषधों का वर्तमान वार्षिक देशीय उत्पादन लगभग 50 करोड़ के मूल्य का है। जिसमें पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 200 करोड़ रुपये तक वृद्धि करने का प्रस्ताव है। सरकारी क्षेत्र के औषध उत्पादन को बढ़ाने के लिए पांचवीं पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मंत्रालय द्वारा औषध उद्योग के संगठनों के साथ विचार विमर्श किये गये जिससे गैर-सरकारी क्षेत्र के कम्पनियां आवश्यक औद्योगिक लाइसेंसों आदि के उपयोग के साथ आगे आ सके। उत्पादन की बड़ी हुई मात्रा पर्याप्त मात्रा में औषधों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर औषध उपलब्ध करने को सुनिश्चित करने के लिए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत औषधों के मूल्यों को नियंत्रित किया जाता है।

ईरान द्वारा भारत की अपेक्षा पाकिस्तान को सस्ती दर पर अशोधित तेल की बिक्री

2649. **श्री बेकारिया :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान द्वारा भारत को जिस दर पर अशोधित तेल दिया जा रहा है, पाकिस्तान को उसकी सप्लाई इससे कम दर पर की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने ईरान का ध्यान इस ओर दिलाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पाकिस्तान को ईरान से अशोधित तेल की पूर्ति के लिए शर्तों के बारे में सरकार को कोई सही सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे के भावी कार्यकरण पर तेल संकट के प्रभाव का रेलवे प्रशासन द्वारा अध्ययन

2650. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने रेलवे के भावी कार्यकरण पर तेल संकट के प्रभाव का अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिचालन के किन क्षेत्रों में परिवर्तनों की आवश्यकता है ; और

(ग) कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव डाले बिना ये परिवर्तन कब लागू किए जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित परिवर्तन इस प्रकार हैं :—(i) पुराने भाप इंजनों का उपयोग बनाये रखना ; और (ii) बिजली कर्षण का तेजी से विस्तार।

(ग) इन प्रस्तावों का क्रियान्वयन शुरू हो गया है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी।

Indian and Foreign Pharmaceutical Companies and their Production

2651. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the names of the prominent Indian and foreign pharmaceutical companies in the country ; and

(b) the value (in crores of rupees) of the drugs manufactured during the last three years by the Indian as well as the foreign pharmaceutical companies, year-wise separately ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) and (b) Information relating to firms with foreign equity exceeding 26 per cent and manufacturing drugs and pharmaceuticals is being furnished in reply to Lok Sabha Unstarred question No. 2644 dated the 12th March, 1974.

Information in regard to some Indian pharmaceutical com panies is furnished in the attached statement.

STATEMENT

	Turnover		
	Rs. crores		
	1970	1971	1972
East India Pharmaceuticals Works Ltd.	4.41	5.15	NA
Ranbaxy Laboratories Ltd . .	1.28	1.71	2.40
Alembic Chemical Works Ltd. . .	13.61	15.23	16.17
Unichem Laboratories Ltd. . .	3.89	4.95	5.93
	1969-70	1970-71	1971-72
Bengal Immunity Co.	2.71	3.16	NA
	1970-71	1971-72	
Standard Pharmaceuticals .	3.63	3.81	4.72
Deys Medical Stores Ltd. .	5.04	5.65	5.24
Sarabhai M. Chemicals Ltd.	3.24	3.24	3.84
	1969-70	1970-71	1971-72
Sarabhai Chemicals .	19.08	24.75	27.62
	1970-71	1971-72	1972-73

वैगनों की कमी के कारण पटसन और कोयले का जमा हो जाना

2652. **श्री एम० सुदर्शन :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगनों की कमी के कारण विभिन्न केन्द्रों पर पटसन और कोयला जमा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। पहले तो जूट उद्योग में लम्बी हड़ताल होने फिर पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कर्मचारियों के आन्दोलनों और 'नियमानुसार काम' करने के आन्दोलन के कारण जूट की ढुलाई नहीं की जा सकी थी। कोयले के लदान पर खासकर बंगाल-बिहार के कोयला क्षेत्रों में हड़तालों, कर्मचारी आन्दोलनों 'धीरे काम करो' बन्दों, बिजली बन्द हो जाने, पटरी पर धरना देने आदि जैसे विभिन्न कारणों से बुरा प्रभाव पड़ा, जिससे गाड़ियों के आने-जाने में अक्सर बाधा पड़ती रही और माल डिब्बों की उपलब्धता में कृत्रिम अभाव उत्पन्न हो गया।

(ख) यदि काम की सामान्य स्थिति हो जाये, तो रेलों को जूट तथा कोयला यातायात की ढुलाई करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मध्य प्रदेश में मंजूर की गई लघु परियोजनाएं

2653. **श्री राम भगत पासवान :**
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने मध्य प्रदेश राज्य में 'लघु परियोजनाओं के लिए 3 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की मुख्य बात क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 28 फरवरी, 1974 तक मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की 14 लघु परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इन स्कीमों में 122 गांवों के विद्युतीकरण तथा 472 पम्पसेंटों का उर्जन और 148 लघु उद्योगों को बिजली की सप्लाई करना निहित है। इन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया / देखिये संख्या एल०टी० 6395/74]

Lawyers Conference held on 18th and 19th February, 1974

2654. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari**: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Lawyers Conference held in Vigyan Bhawan, New Delhi on the 18th and 19th February 1974 had sought certain facilities from Government ;

(b) whether Government are formulating any plan to educate the common citizens of fundamentals of the law; and

(c) whether this will help to reduce the corruption prevalent in the police ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs: (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

दक्षिण पूर्व रेलवे में लोको-मैनों के लिए 10 घंटों की ड्यूटी :

2655. **श्री वी० मायावन :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में लोको-मैनों के लिये 10 घंटे की ड्यूटी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके अन्तर्गत कितनी गाड़ियां आती हैं ; और

(ग) अखिल भारतीय स्तर पर नये काम के घंटे कब तक लागू कर दिये जाएंगें ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) लोको रनिंग कर्मचारियों के लिए 10 घंटा ड्यूटी का कार्यान्वयन दक्षिण-पूर्व रेलवे में 1 दिसम्बर, 1973 को शुरू किया था। तब से सभी डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों और 9 सवारी गाड़ियों में यह व्यवस्था की जा चुकी है। सात चुने हुए खंडों पर चलने वाली माल-गाड़ियों में भी यह व्यवस्था हो चुकी हैं।

अन्य रेलें भी इसी प्रकार की कार्रवाई कर रही हैं।

चौथी योजना में बिहार के लिए सिंचाई परियोजनाएं

2656. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजनावधि में बिहार के लिए कितनी सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ करने का निर्णय किया गया था ;

(ख) इनमें क्या प्रगति हुई है ;

(ग) इन परियोजनाओं में यदि विलम्ब हुआ है या यदि वे पूरी नहीं की गई है या यदि वे आरम्भ नहीं की गई हैं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) राज्य सरकार के उत्साह के अभाव में कितनी ऐसी परियोजनाएं आरम्भ नहीं हुई हैं या उनमें विलम्ब हुआ है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) चौथी योजना अवधि के दौरान, एक वृहत तथा 10 मध्यम नई स्वीकृत सिंचाई स्कीमों का कार्यान्वयन आरम्भ किया गया था। इन नई मध्यम स्कीमों में से दो का चौथी योजना अवधि के दौरान पूर्ण होने की संभावना है। तथा अन्य निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। शेष सभी मध्यम स्कीमें पांचवीं योजना अवधि के दौरान पूर्ण की जानी प्रत्याशित हैं। वृहत स्कीम (बागमती परियोजना) पर कार्य छठी योजना तक चालू रहना प्रत्याशित है।

(ग) और (घ) यह सूचित किया गया है कि इन परियोजनाओं को पूरा करने में देरी के मुख्य कारण भू-अर्जन में कठिनाइयां तथा आवश्यक निवेशों की कमी है।

बाणसागर परियोजना करार को कार्यान्वित करना

2657. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाणसागर परियोजना करार को क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या संबन्धित राज्यों में उक्त परियोजना के पानी के वितरण की कोई समयसारणी बनाई गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबन्ध में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सोन जल के बटवारे पर राज्यों के मध्य हुए समझौते की रोशनी में संशोधित परियोजना प्रस्तावों को मध्य प्रदेश सरकार से प्रतीक्षा है।

(ख) से (ग) राज्य इस बात पर सहमत हो गए हैं कि भारत सरकार सोन नदी के व्यापक जल वैज्ञानिक तथा निकटवर्ती गंगा के उपलब्ध जल को लिफ्ट द्वारा समुपयोजन करने की संभाव्यता के अध्ययन करने के लिए एक विशेष नदी आयोग गठित करे।

जयन्ती जनता एक्सप्रेस के लिए चित्रों का चयन

2658. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयन्ती जनता एक्सप्रेस के लिये मधुवनी चित्रों के चयन के लिये कोई चयन समिति बनाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो चयन के लिये क्या कसौटी अपनाई गई थी ;

(ग) क्या ये चित्र सीधे कलाकारों से खरीदे गये थे या ठेकेदारों के माध्यम से खरीदे गये थे ; और

(घ) यदि ठेकेदारों के माध्यम से खरीदे गये थे उन ठेकेदारों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) मूल मधुवनी लोक कला-चित्रों का एक सैट खरीदा गया था जो बिहार राज्य के वाणिज्य केन्द्र में उपलब्ध था और इसका चयन रेलवे बोर्ड कार्यालय में किया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्डालको को बिजली की सप्लाई

2659. **श्री डी० डी० देसाई** :
श्री पी० गंगा देव :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्डालको को विद्युत की सप्लाई रोक दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका अन्य उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) हिन्डालको को अपना उत्पादन बनाए रखने के लिए ऊर्जा के और कौन से स्रोत सुझाए जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कम्पनी के एल्यूमिनियम प्रगालकों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से विद्युत की सप्लाई बन्द कर दी गई है। गढ़ाई संयंत्र के लिए बिजली की सप्लाई 7.5 मैगावाट के बजाय 5 मैगावाट के कम स्तर पर जारी है। अतः एल्यूमिनियम का उत्पादन इस समय सम्पूर्ण रूप से, रेणुसागर बिजली कम्पनी से बिजली की सप्लाई पर आधारित है जो कि हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कम्पनी की सहायक कम्पनी है। प्रगालकों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से बिजली की सप्लाई बन्द हो जाने के कारण एल्यूमिनियम का उत्पादन 150 प्रतिदिन तक कम हो गया है। इससे एल्यूमिनियम का उपयोग करने वाले विभिन्न उद्योगों के लिए देश में एल्यूमिनियम की उपलब्धता में तदनुरूप कमी आ गई है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् उत्तर प्रदेश में बिजली की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है।

टैक्सियों और आटोरिक्शा मालिकों की सहकारिताओं को पेट्रोल पम्प अलाट करना

2660. **श्री डी०डी० देसाई :**

श्री श्री किशन मोदी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कम्पनी टैक्सी और आटोरिक्शा मालिकों की सहकारिताओं को, केवल उन्हीं के प्रयोग के लिये, पैट्रोल पम्प अलाट करेगी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इससे क्या लाभ होंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आटोमोटिव ईंधनों की 30 किलो लिटर प्रति मास से कम न होने वाली अनुमानित बिक्री के अधीन टैक्सी और आटोरिक्शा मालिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तियों के रूप में या सरकारी समितियों/संघों के रूप में भारतीय तेल निगम का उन्हें फुटकर बिक्री के पैट्रोल पम्पों के आवंटन करने का विचार है। इससे टैक्सी/आटोरिक्शा संघ समर्थ हो जाएंगें कि वे पैट्रोलियम उत्पादों की निरन्तर और सुनिश्चित सप्लाई अपने ग्राहकगण को कर सकेंगे। उत्पादों की दरों, मात्रा और गुण भी ग्राहकों के लिए सुनिश्चित्त की जाती है। दूसरी ओर इस प्रकार के व्यापारियों के आवंटन की मार्फत एक श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली गाड़ियों की बड़ी संख्या की सुनिश्चित बिक्री का लाभ भारतीय तेल निगम का है।

मैसर्स सेन्डोज तथा अन्य कम्पनियों द्वारा फार्म्यूलेशन का बिना लाइसेंस उत्पादन

2662. **श्री मालजी भाई पारमार :**

श्री के० एस० चावड़ा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सेन्डोज, में एंड बेकर स्मिथ क्लिन और फ्रेंच लेबोरेटरीज द्वारा उद्योग विकास और विनियमन, अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस लिये बिना कई फार्म्यूलेशनज का उत्पादन किया जा रहा है ;

"(ख) यदि हां, तो किन-किन मदों का उत्पादन किया जा रहा है और गत तीन वर्षों में उनका वर्ष वार उत्पादन क्या था ; और

(ग) सरकार का इन दोषी फर्मो के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) मैसर्स सण्डोज इंडिया लि०, मैसर्स में एंड वेकर लि० और मैसर्स स्मिथ क्लाइन एंड फ्रेंच लि० सरकार की अनुमति के आधार पर बहुत से सूत्र भोगों का निर्माण कर रहे हैं। किन्तु वे सरकारी विशिष्ट अनुमति के बिना किसी मद का निर्माण कर रहे हैं इसका पता किया जा रहा और सूचना सभा पटल पर रखी जायगी।

पांचवीं योजना में केरल में सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं स्थापित करना

2663. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**
श्री सी०एच० मोहम्मद कोया :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोई नई सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं केरल में आरम्भ करेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) केरल को पांचवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। बहरहाल, प्रस्तावित नई सिंचाई और विद्युत परियोजना जिनके लिए अपेक्षित रिपोर्ट और प्राक्कलन अभी तक केरल सरकार द्वारा केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग को भेजी गई हैं, की मुख्य विशेषताएं नीचे दी जाती हैं :--

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	लाभ
1. वानासुरसागर	1137.10	23,870 हैक्टेयर
2. तिरूनेल्ली	650.00	8,900 हैक्टेयर
3. कारापुजा	389.00	9,370 हैक्टेयर
4. पेरियार घाटी (इद्दिक्को)	1650.00	32,780 हैक्टेयर
5. वामनपुरम	747.28	20,000 हैक्टेयर
6. अट्टा	476.00	7,280 हैक्टेयर
7. नोलापुजा	290.00	8,500 हैक्टेयर
8. मन्जत	318.00	4,860 हैक्टेयर
9. थोन्दर	299.00	6,070 हैक्टेयर

1	2	3	4
10.	इदामलायार . .	1439.00	57,400 हैक्टेयर
11.	केरल भवानी .	1224.70	32,300 हैक्टेयर श्रौर 100 मेगावाट प्रतिस्ठापित
12.	मननथोड़ो .	1612.00	14,170 हैक्टेयर श्रौर 200 मेगावाट प्रति-स्ठापित
13.	पन्डियार-पुन्नापुजा जल-विद्युत परियोजना . .	1122.00	70 मेगावाट प्रति स्ठापित
14.	कक्कड़ (साबिरिगिरि टेलरेस) जल-विद्युत परियोजना	1568.00	60 मेगावाट प्रतिस्ठापित
15.	इदिक्को जल-विद्युत परियोजना चरण-3 .	410.00	चरण-एक बिजली घर में 100 भार श्रनु-पात पर 48 मेगावाट की श्रतिरिक्त वास्त-विक क्षमता

योजना में इन स्कीमों को शामिल करना इनकी तकनीकी, श्रार्थिक संभाव्यता तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

केरल को कोयला भेजने के लिए उपलब्ध रेलवे वैगन

2664. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान केरल को कोयला भेजने के लिये कितने रेलवे वैगन उपलब्ध कराये गये; श्रौर

(ख) उक्त श्रवधि में केरल ने कोयले की ढुलाई के लिये कितने रेलवे वैगनों की मांग की थी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री : (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1973-74 के दौरान (फरवरी तक) केरल के लिये कोयले श्रौर कोक के 216 माल डिब्बे श्राबंटित किये गये।

(ख) इसी श्रवधि में केरल के लिए, सभी कोयला-क्षेत्रों से, कोयले तथा कोक के 510 माल-डिब्बों की मांग की गई।

केरल के प्रति एक लाख व्यक्तियों पर रेलवे लाइन की लम्बाई

2665. **श्रीमती भार्गवी तनकम्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में प्रति एक लाख व्यक्तियों पर रेलवे लाइन की लम्बाई कितनी है श्रौर इसकी श्रखिल भारतीय श्रौसत के मुकाबले स्थिति क्या है ?

„रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : केरल राज्य में एक लाख की आबादी के पीछे 4.17 मार्ग किलोमीटर रेलवे लाइन है जबकि इसी की तुलना में अखिल भारतीय औसत 11.01 मार्ग किलोमीटर की है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा 1973-74 के दौरान केरल के लिए स्वीकृत परियोजनाएं

2666. **श्रीमती भार्गवी तनकम्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केरल के लिये कितनी परियोजनाएं मंजूर की गई हैं; और

(ख) केरल राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के सुधार के लिये 1973-74 के दौरान मंजूर परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान फरवरी, 1974 तक केरल राज्य बिजली बोर्ड की चार स्कीमें स्वीकृत की हैं। इन स्कीमों में 116 ग्रामों के विद्युतीकरण तथा 2280 पम्पों के ऊर्जन के लिए 139,255 लाख रुपये की ऋण सहायता निहित है। ये सारी स्कीमें विकसित क्षेत्रों से ही सम्बद्ध हैं।

(ख) केरल राज्य बिजली बोर्ड ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विशेष रूप से कम विकसित क्षेत्र के लिए केवल एक स्कीम ही प्रायोजित की है। निगम इस स्कीम पर विचार कर रहा है।

रेलवे के गार्डों को अपने नए वेतनमानों पर असन्तोष

2667. **श्री नारायणचन्द पराशर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के गार्डों ने सरकार से अपने नये वेतनमानों के बारे अपना असंतोष प्रकट किया है और इस मामले पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गार्डों के मामले पर कोई विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सरकार ने रेल कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनमानों के सम्बन्ध में तीसरे वेतन आयोग की सिफारशों को मोटे तौर पर स्वीकार करने का निर्णय किया है। तदनुसार इस निर्णय के आधार पर गार्डों की कोटि के संशोधित वेतनमान अधिसूचित कर दिये गये हैं। जिन वेतनमानों की सिफारिश की गई है उनसे किसी तरह के विचलन से चाहे वह दूसरे विभागों के साथ समानता के आधार पर अथवा उसी विभाग में दूसरी कोटियों के साथ समानता के आधार पर क्यों न किया जाए, व्यापक प्रतिक्रिया होगी।

पेट्रोल और अन्य उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

2668. **श्री मधु लिमये** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पेट्रोल तथा अन्य उत्पादों के मूल्यों में और वृद्धि करने का निर्णय, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के चुनावों की दृष्टि से फिलहाल स्थगित किया गया था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : जी नहीं।

Implementation of Irrigation projects

2669. **Shri M.C. Daga:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the names of irrigation projects under consideration of Government, the implementation of which is likely to result in growing of more food-grains;

(b) whether any time bound programme has been chalked out therefor; and

(c) if so, the main features thereof ?

The Minister of Irrigation and Power (Shri K.C. Pant): (a) to (c). In the Fifth Plan, besides taking up a number of new schemes, work is proposed to be continued on 75 Major and 155 Medium Irrigation Schemes spilling over from the Fourth Plan. An outlay of Rs. 2401 crores is proposed in the Fifth Plan and it is expected that 64 Major and all the 155 Medium continuing schemes would then be completed and an additional irrigation potential of 6.2 m.ha. would be developed.

Emphasis is also being laid on command area development to accelerate the utilisation of created irrigation potential and to secure the maximum agricultural production through full utilization of the available water. A provision of Rs. 216.63 crores has been made for this purpose in the public sector in the draft Fifth Plan. In addition, Rs. 210 crores is expected to be available from institutional sources.

Reduction in Number of Vehicles with Government Departments in view of Oil Situation

2670. **Shri M.C. Daga:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the names of the Government Departments where the number of cars, jeeps, and other vehicles has been reduced and the use of which has been minimised during the month of January and February, 1974 keeping in view the shortage of oil; and

(b) the broad features of circulars and notifications issued by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b) It is presumed that by "Government Departments" the Hon'ble member means "Government Departments of Central Ministries of the Government of India". The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

नागपुर के रेल कर्मचारियों को अनाज की सप्लाई

2671. **श्री एम० कतामुतु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में रेल कर्मचारियों को राशन की दुकानों से 12 किलो अनाज दिया जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो अनाज की उचित दरों पर नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) खाद्य आन्दोलन के सिलसिले में 19 दिसम्बर से 28 दिसम्बर, 1973 तक की अवधि के के लिये नागपुर के कितने कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है ; और

(घ) कुछ का वेतन काटने और कुछ का न काटने में किये गये भेदभाव के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। प्रति व्यस्क प्रति मास केवल सात किलोग्राम अनाज सप्लाई किया जा रहा है।

(ख) राज्य सरकार के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया गया था क्योंकि सर्वसाधारण को जिसमें रेल कर्मचारी भी शामिल है, अनाज और अन्य अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है।

(ग) 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धान्त पर 6550 ।

(घ) जिन कर्मचारियों ने 19-12-73 से 28-12-73 तक की अवधि में किसी आन्दोलन में भाग लिया था, उन्हें 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांन्त पर इस अवधि का वेतन नहीं दिया गया और इस मामले में कोई भेव-भाव नहीं बरता गया।

दक्षिणी पेट्रो-रसायनिक, उद्योग निगम को कुड्डालोर में उर्वरक संयंत्र लगाने की अनुमति

2672. **श्री एम० कतामुत्तु :**
श्री सेझियान :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी पेट्रो-रसायनिक उद्योग निगम, तुतीकोरिन ने कुड्डालोर में उर्वरक संयंत्र लगाने की अनुमति के लिए आवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुमति दे दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

पेट्रोलयम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जा रहा है।

प्रत्येक रेलवे द्वारा बेचे गये स्क्रैपत्ये की मात्रा और उनका मूल्य

2673. **श्री एस० एन० मिश्र:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का स्क्रैप बेचा गया ; और

(ख) उक्त बिक्रय किस ढंग से किया गया ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण संलग्न है। (**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6395574**)

(ख) रेलों की अपनी जरूरतों को पूरा करने और दूसरे सरकारी विभागों के साथ किये गये करारों का पालन करने के बाद बेचे जाने के लिये जितना स्क्रैप उपलब्ध होता है वह खुले टेंडरों द्वारा अथवा आवधिक नीलामी के जरिये बेच दिया जाता है।

काम के घंटों के समायोजन द्वारा ईंधन तथा विद्युत की बचत

2674. **श्री पी०ए० सामिनाथन** :

श्री पी० एम० मेहता :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गर्मी तथा सर्दी में काम के घंटों के समायोजन द्वारा ईंधन और विद्युत में बचत की संभावना की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत **मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) और (ख) जी, हां। ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में देश में कार्य समय का समुचित रूप से समंजन करके ईंधन तथा विद्युत में बचत करने की संभावना की जांच की जा चुकी है। कारखानों तथा अन्य संस्थानों के कार्य-समय का समंजन और भारों के पुनःस्थापन से पीक विद्युत आवश्यकताओं में बचत पर प्रभाव पड़ा है । बहरहाल, ग्रीष्म और शीत ऋतु में कार्य-समय के संमजन से कोई महत्वपूर्ण बचत संभव नहीं है।

रेल कर्मचारियों को उचित दर की दुकानों से राशन दिलाने का प्रस्ताव

2675. **श्री भोगेन्द्र झा** :

श्री सी० जनार्दनन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के साथ केन्द्रीय श्रमिक संघ की बैठक में ए० आई ० टी० यू० सी० ने सरकार को सुझाव दिया था कि वह रेल कर्मचारियों को प्रत्येक राज्य में उचित दर की दुकानों से राशन दिलायें, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है और उसकी मुख्य बातें क्या हैं। -

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) रेल कर्मचारियों सहित आम जनता को खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करना प्रमुख रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में देश में उचित मूल्य की दुकानें खोली गयी हैं। फिर भी, रेल प्रशासन रेल कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समितियां स्थापित करने और उनका संचालन करने के लिये रेल कर्मचारियों को प्रोत्साहन देते हैं। इन समितियों की सुव्यवस्थित वृद्धि हेतु विभिन्न सुविधाएं एवं रियायतें प्रदान की जाती हैं। सामान्यतः उन स्टेशनों पर जहां 300 या उससे अधिक रेल कर्मचारी एक साथ रहते हैं, उचित मूल्यों की दुकानों की व्यवस्था की जाती है जिनका संचालन रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये रेल कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समितियों या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत दुकानदारों के माध्यम से किया जाता है। फिर भी रेल कर्मचारियों के लिए उचित मूल्य की और अधिक दुकानें राज्य सरकारों द्वारा खुलवाने के उद्देश्य से इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

तेल की खोज के लिए 'कांटिनेंटल शैल्फ' का सर्वेक्षण

2676. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने देश को 'फासिल' तेल में आत्म-निर्भर बनाने के लिए देश के तट के साथ-साथ 'कांटिनेंटल शैल्फ'का उचित सर्वेक्षण और खोज करने हेतु क्या उपाय सुझाये हैं ;

(ख) सुझाय गए उपायों पर क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी; और

(ग) समुद्री भू-सर्वेक्षण विंग को सुदृढ़ करने और अर्ध-हिमालय क्षेत्र के सर्वेक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए गए ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) देश को तेल में आत्म निर्भर बनाने के लिए इस प्रकार के किन्हीं उपायों का प्रस्ताव नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अपने मेराइन भूगर्भीय खण्ड को सुदृढ़ करने तथा उप-हिमालय क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिये भारतीय भूगर्भीय संस्था द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :—

(i) मेराइन भूविज्ञान यूनिट, जिस की 1965 में स्थापना की गयी थी, का इस समय 9 भूवैज्ञानिकों द्वारा व्यवस्था की जाती है; यूनिट का विस्तार किया जा रहा है। और भारतीय भूगर्भीय संस्था ने मेराइन भूगर्भीय कार्य के लिये एक जहाज प्राप्त करने की कार्यवाही भी की है ।

(ii) भारतीय भूगभीर्य संस्था द्वारा विभिन्न मंडलीय कार्यालयों से हिमाचल तथा उप-हिमालय क्षेत्रों के भूगर्भीय चित्रण भी करवाये जा रहे हैं। इस के अतिरिक्त हिमालय क्षेत्र में किये जा रहे कार्य में तेजी लाने तथा उस का लाभदायक संश्लेषण सुनिश्चित करने के लिये हिमालय भूविज्ञान प्रभाग की स्थापना की गई है ।

जहां तक कच्चे तेल की खोज का प्रश्न है, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने हिमालय क्षेत्र के भागों में भूगर्भीय एवं भूभौतिकीय सर्वेक्षण किये हैं।

शोलापुर डिवीजन को मध्य रेलवे जोन में शामिल करना

2677. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शौलापुर डिवीजन को मध्य रेलवे जोन में शामिल करने की मांग का अध्ययन करने के लिये बनाई गई समिति की कोई बैठक हुई है और वह किसी निष्कर्ष पर पहुंची है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर कोई निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) समिति ने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

इस्पात संयंत्रों के लिए रेल के पर्याप्त माल डिब्बे

2678. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात संयंत्रों पर जमा हुए इस्पात के भण्डारों को उठाने के लिये इन संयंत्रों को पर्याप्त रेल के माल डिब्बों की व्यवस्था करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) इन इस्पात संयंत्रों को सामान्य रूप से सामूहिक रेल-परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हाल के महीनों में, विशेष रूप से अगस्त और दिसम्बर, 1973 में, कर्मचारी आन्दोलनों की बाढ़, अचानक हड़ताल, बन्द, 'धीरे काम करो' कर्षण और संचार उपस्कर की चोरी आदि के कारण, विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में गाड़ी परिचालन पर गम्भीर प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप इस्पात के सामान का कुछ भूतल स्टाक इकट्ठा हो गया। इन रुकावटों के बावजूद, जो अभी तक चल रही हैं, रेलें इस्पात कारखानों से यथासंभव अधिक से अधिक तैयार माल की ढुलाई का प्रयास कर रही हैं।

(ख) यदि गाड़ियां सामान्य ढंग से चलती रहें और उपयुक्त कारणों से उनके संचालन में कोई रुकावट न आये तो इस्पात कारखानों के यातायात की ढुलाई में रेलों को कोई कठिनाई नहीं होगी। स्थिति के सामान्य होने में कितनी देर लगेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि काम की स्थिति फिर कब सामान्य होती है।

रेल पटरी को सुदृढ़ बनाकर कोयले की खपत में बचत करना

2679. **श्री डी० पी० जदेवा :**

श्री अरविन्द एस० पटेल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन समाचारों की जांच की है कि रेल पटरी को सुदृढ़ बनाकर 15 प्रतिशत ईंधन बचाया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ; और

(ग) सरकार इस पर क्या कार्यवाही करेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) प्रारम्भिक अध्ययनों से मालूम हुआ है कि लम्बी ढली हुई पटरियों वाले रेल पथ पर रिकार्ड किया गया कर्षण प्रतिरोध लगभग 16 प्रतिशत कम रहा है। इसके फलस्वरूप ईंधन में कुछ किफायत हो सकती है।

(ख) और (ग) : भारतीय रेलों ने ट्रंक मार्गों पर रेल-पथ संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए, रेल-पथ के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें पटरियों की ढलाई शामिल है।

एकाधिकार गृह द्वारा नये उपक्रम की स्थापना के बारे में एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग का निर्णय

2680. **श्री सी० के० चन्द्रपन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग ने निर्णय किया है कि जनता का कोई व्यक्ति यदि एकाधिकार गृह द्वारा नये उपक्रम की स्थापना का विरोध करता है तो वह प्रस्तावित परियोजना संबंधी सारे दस्तावेज प्राप्त करने का हकदार नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस निर्णय पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) : एक मामले, में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 22 (3) (ख) के अन्तर्गत दो प्रतिद्वन्दियों ने आयोग के समक्ष यह प्रार्थना करते हुए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये थे कि कतिपय प्रलेख आवेदक कम्पनी या आयोग द्वारा उनको दिया जाए। इन आवेदन-पत्रों में आयोग ने 11 फरवरी, 1974 को एक आदेश पारित किया था, जिसमें साथ साथ एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 37, 18, और 60 के सांविधिक उपबन्धों में सूचना/प्रलेखों के प्रगट करने पर प्रतिबन्धनों को लागू करने पर प्रमुखता दी।

पझासी परियोजना और थानिरमूक्कोम परियोजना का निर्माण

2681. **श्री सी० के० चन्द्रपन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनानौर जिले में पाझासो परियोजना और एल्लेपो जिले में थानिरमूक्कोम परियोजना में धन की कमी के कारण बहुत धीमी गति से काम हो रहा है ;

(ख) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और इस समय उक्त परियोजनाओं का निर्णय किस अवस्था में हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं पर निर्णय कार्य कब आरम्भ हुआ और उस समय इन पर कितनी धन राशि खर्च करने का अनुमान था और इस समय इन परियोजनाओं पर कितनी पुनरीक्षित धन-राशि व्यय करने का अनुमान है और इन में से प्रत्येक योजना पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : केरल सरकार ने 1961–62 में पझासी परियोजना का निर्माण शुरू किया था, जबकि थन्नुरमुक्कम नियामक का निर्माण 1958 में आरम्भ किया था। आरम्भ में इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्रमशः 4.42 करोड़ तथा 1.50 करोड़ रु० थी। केरल सरकार द्वारा किये गये कम प्रावधानों के परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं पर धीमी गति से प्रगति हो रही है। अब इन परियोजनाओं के संशोधित प्राक्कलन क्रमशः 14.62 करोड़ रुपये तथा 4.58 करोड़ रुपये हैं। 1973–74 के अंत तक इन परियोजनाओं पर क्रमशः 4.34 करोड़ रुपये तथा 2.60 करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है।

पझासी परियोजना पर, बराज पर लगभग तिहाई कार्य तथा नहर का लगभग चौथाई कार्य अब तक किया जा चुका है, और इस परियोजना के पांचवीं योजना के अन्त तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। थन्निरमुक्कम नियामक के द्वितीय चरण के 1974 के मध्य तक पूर्ण हो जाने की संभावना है, और 1974 के अंत तक काफर बांध के तृतीय चरण के पूर्ण हो जाने पर लाभ प्राप्त होने की आशा है। संपूर्ण परियोजना के 1977–78 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

ग्रालावाकोड्डे डिवीजन (दक्षिण रेलवे) के रेलवे कर्मचारियों द्वारा मकान निर्माण के लिए ग्रावेदन

2682. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के ग्रलावाकोड्डे डिवीज़न में कितने रेलवे कर्मचारियों ने मकान बनाने के लिये, भूमि खरीदने के लिये ऋण लेने हेतु ग्रावेदन पत्र दिये ; ग्रौर

(ख) कितने मामलों में ऋण मंजूर किये गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 13

(ख) 8

ग्रोलावाक्कोड क्षेत्र (दक्षिण रेलवे) में रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

2683. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कोयले की कमी तथा लोको कर्मचारियों ग्रौर ग्रन्य हड़तालों के कारण ग्रोलावाक्कोड क्षेत्र (दक्षिण रेलवे) में कितनी रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं ;

(ख) इस बीच कितनी रेलगाड़ियों को पुनः चलाया गया है; ग्रौर

(ग) शेष रेलगाड़ियों को पुनः कब तक चलाया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रद्द की जाने वाली गाड़ियों की संख्या घटती-बढती रहती हैं किन्तु समूचे वर्ष में औसतन 9 जोड़ी गाड़ियां प्रतिदिन रद्द की गई।

(ख) सभी गाड़ियों का चलना फिर शुरू हो गया है सिवाय 23 जोड़ी गाड़ियों के, जो ग्रभी भी रद्द पड़ी हैं।

(ग) रेलों पर रेल इंजनों के लिये कोयले की सप्लाई की स्थिति ज्यों-ज्यों सुधरती जायेगी, रद्द पड़ी शेष गाड़ियां उत्तरोत्तर चलायी जायेंगी।

ग्ररकोनम से कोचीन तक दोहरी रेलवे लाइन बिछाना

2684. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय ने ग्ररकोनम से कोचीन तक दोहरी लाइन बिछाने का निर्णय किया था;

(ख) क्या इस मार्ग के तमिलनाडु के भाग में दोहरी रेलवे लाइन बिछा दी गई है; ग्रौर

(ग) इस मार्ग के केरल के भाग में दोहरी लाइन बिछाने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) स्थिति इस प्रकार है :—

(i) **तमिलनाडु :** 383 किलोमीटर तक दोहरी लाइन पहले ही उपलब्ध है। 46 किलोमीटर में दोहरी लाइन बिछाने का काम हो रहा है ग्रौर ग्राशा है, यह काम दिसम्बर, 1974 तक पूरा हो जायेगा। इरुगुर ग्रौर पोद्दनूर के बीच के इकहरी लाइन वाले भाग में दोहरी लाइन बिछाना ग्रावश्यक नहीं समझा जाता।

(ii) **केरल :** 45 किलोमीटर तक दोहरी लाइन पहले ही उपलब्ध है। 18 किलोमीटर में दोहरी लाइन बिछाने का काम हो रहा है ग्रौर ग्राशा है, यह काम दिसम्बर, 1974 तक पूरा हो जायेगा। खण्ड के शेष भाग में दोहरी लाइन बिछाने के लिए कोई निश्चित तारीख निर्धारित नहीं की गयी है।

ईंधन तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग

2685. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ईंधन तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग करने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कौन-कौन से एकक कोयले पर आधारित हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, नहीं,

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निम्नलिखित यूनिटों को कोयले से चलने वाली यूनिटों में बदलने का प्रस्ताव है :

बिजली घर का नाम	उन यूनिटों की प्रतिस्थापित क्षमता जिन्हें परिवर्तित किया जाना है। (मैगावाट)
(1) बरौनी (बिहार)	2 × 15 मै० वा० 2 × 50 मै० वा० } 130 मैगावाट
(2) अहमदाबाद (गुजरात)	4 × 15 मै० वा० 2 × 30 मै० वा० } 120 मैगावाट
(3) ट्राम्बे (महाराष्ट्र)	2 × 62.5 मै० वा० 125 मैगावाट (2 × 62.5 मै० वा० + 1 × 150 मे० वा० में कोयले से प्रचालन के परिवर्तन के लिए। कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।
(4) धुवरण (गुजरात)	4 × 63.5 मै० वा० 254 मैगावाट

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए धनराशि

2686. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए पर्याप्त उपबंध किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा और विद्युतीकरण के लिए शेष कितने गांव रह जाएंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपने ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए 950 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया था ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं । इसके अलावा 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' के अन्तर्गत ग्राम विद्युतीकरण निगम के जरिए 275 करोड़ रुपये दिये जाने की संभावना है ।

(ग) देश में 5,66,878 ग्राम हैं । पांचवीं योजना के अन्त तक 2.85 लाख ग्राम विद्युतीकरण करना आयोजित है । इस प्रकार 3.09 लाख ग्राम विद्युतीकरण के बिना रहेंगे ।

कलकत्ता के लिए तीसरा बड़ा स्टेशन

2687. **श्री ए० के० एम० इसहाक**

श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर रोज कितनी यात्री रेलगाड़ियां आती हैं तथा जाती हैं और दिल्ली तथा बम्बई के दो बड़े स्टेशनों पर ऐसी कितनी रेलगाड़ियां आती तथा जाती हैं ;

(ख) क्या कलकत्ता के वर्तमान बड़े रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को कम करने के लिए एक तीसरा बड़ा स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितना व्यय आयेगा ;

(घ) इस उद्देश्य के लिए बनाए जाने वाले स्टेशन का नाम क्या होगा; और

(ङ) इस स्टेशन पर कितनी यात्री रेलगाड़ियां आयेंगी तथा यहां से जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) से (घ) निम्नलिखित सर्वेक्षण किये जा रहे हैं :—

(1) हावड़ा और सियालदह मण्डलों में उपनगरी और गैर-उपनगरी यातायात को संभालने के लिए अपेक्षित खण्डीय और पर्यन्त सुविधाओं के लिए तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण, पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों में पार्सल यातायात के लिए पर्यन्त सुविधाएं, हावड़ा में दक्षिण पूर्व रेलवे की उपनगरीय गाड़ियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं तथा हावड़ा और सियालदह से माल यातायात के विसर्जन के लिए सुविधाएं हाबड़ा स्टेशन से संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की गयी है और निम्नलिखित निर्माण कार्यों को 1974-75 के बजट में चरण 1 के रूप में शामिल किया गया है जिसकी लागत 1.48 करोड़ रुपये है ।

(i) सामान्य भण्डार और सिगनल कारखाने के ढांचे को हावड़ा में खड़ा करना और इसे हटाकर बेलूर ले जाना ।

(ii) बैलूर स्क्रैप यार्ड का पुर्नस्थापन और इसे हटाकर डाकूनि ले जाना। इससे हावड़ा में पर्यन्त सुविधाओं से अधिक विस्तार के लिये स्थान मिलेगा।

(2) कलकत्ता (दक्षिण पूर्व रेलवे) में उपनगरी पर्यन्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण। जिन सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है उनके बारे में कुछ कहना अभी समय से बहुत पहले होगा। क्योंकि ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) इस स्थिति में कुछ बनाया नहीं जा सकता।

विवरण

आने जाने वाली गाड़ियों की दैनिक संख्या

स्टेशन का नाम	गाड़ियों की संख्या		
	आने वाली	जाने वाली	
हावड़ा	169	169	इनमें सप्ताह में एक बार, दो बार और तीन बार चलने वाली गाड़ियां भी शामिल हैं।
सियालदह	199	199	
दिल्ली बड़ी लाइन	69	70	
दिल्ली मीटर लाइन	13	13	
नयी दिल्ली	67	67	
बम्बई बी०टी० (दादर सहित)	346	346	
बम्बई सेन्ट्रल (दादर सहित)	22	30	
बम्बई (चर्च गेट)	245	237	

पश्चिमी बंगाल में सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं की प्रगति

2688. **श्री ए० के० एन० इसहाक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं की प्रगति बहुत धीमी रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाओं ने

प्रत्याशित समय की अपेक्षा कुछ अधिक समय लिया है। यह मुख्यतः धन की कमी, लागतों में वृद्धि, निर्माण सामग्रियों का अभाव और उपस्कर की प्राप्ति में देरी के कारण हुआ है। निर्माणाधीन परियोजनाएं अब क्रियान्वयन की प्रौढ़ावस्था में हैं और इन परियोजनाओं के निर्माण की गति में तेजी लाने हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को निर्धारण करने के लिए समिति

2689. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों को निर्धारित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इसकी अन्य मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) सरकार ने पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्यांकन की जांच और रिपोर्ट के लिए मूल्यांकन समिति गठित करने का निर्णय किया है। समिति का अभी औपचारिक रूप से गठन किया जाना है।

माल गाड़ियों को रद्द करने के कारण वाणिज्यिक माल का परिवहन अस्त व्यस्त होना

2690. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान कोयले और वैगनों की कमी के कारण उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलवे में अनेक मालगाड़ियां रद्द करने के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक माल का परिवहन अस्त व्यस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) केवल पूर्वोत्तर रेलवे पर कई बार दूरसंचार कर्मचारियों, रेल इंजन अनुरक्षण कर्मचारियों, सवारी और मालडिब्बा कर्मचारियों और लोको रनिंग स्टाफ, स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों द्वारा आन्दोलनों के कारण मालगाड़ियों के संचलन पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ा और मालगाड़ियां रद्द करनी पड़ीं जिसका फल यह हुआ कि रेल इंजनों के वास्ते कोयले से लदे मालडिब्बे भी स्थानान्तरण स्थलों से रेलों पर विभिन्न रेल इंजन शेडों को न भेजे जा सके।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उर्वरक उद्योग के सहकारी क्षेत्रीय विकास के लिए योजना

2691. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उद्योग के सहकारी क्षेत्रीय विकास के लिये कोई योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) यद्यपि इस समय इस प्रकार की कोई योजना नहीं है, देश में प्रौद्योगिकीय-आर्थिक, मांग तथा अन्य संबंधित विचारों के संदर्भ में उर्वरक क्षमता का विकास किया जाता है । ऐसी क्षमता के विकास की योजना बनाते समय राज्य सरकारों और अभिकरणों के यदि कोई विचार हों तो उन्हें भी ध्यान में रखा जाता है ।

भारत में ड्रिलिंग रिगों का निर्माण

2692. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुमानिया रिगों का मुख्य सप्लायर है जिसका प्रयोग विभिन्न तटवर्ती स्थानों पर खुदाई के लिए किया जा रहा है;

(ख) क्या यथाशीघ्र नए तेल क्षेत्रों का पता लगाने में सुविधाएं प्राप्त करने हेतु प्राथमिक आधार पर भारत में ड्रिलिंग रिगों का निर्माण करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत को इस बारे में सहायता देने की पेशकश की है तथा उनकी समझौते की शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) रिगों की कुछ क्षमता के लिए रूस के साथ एच० ई० सी० रांची के वर्तमान सहयोग को छोड़कर कोई और अन्य देश व्यधन रिगों के निर्माण करने में भारत की मदद करने के लिए अब तक आगे नहीं बढ़ा है ।

विदेशों से भारतीय रेलवे में प्रयोग हेतु सामान और मशीनों की खरीद

2693. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों से भारतीय रेलवे में प्रयोग किये जाने हेतु सामान और मशीनों की खरीद के ब्यौरे के बारे में जांच के लिए एक निकाय स्थापित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार को निकाय का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ; और

(ग) प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे को अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) विदेशों से भारतीय रेलों में इस्तेमाल के लिए सामान और मशीनों की खरीद के ब्यौरे की जांच के लिए एक निकाय स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) में दिये गये उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

Crimes on Railway Registered during the last three months

2694. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the incidence of thefts, dacoities and murders committed in the Indian Railways during the three months upto 31st January, 1974 and the number of persons arrested in this connection;

(b) whether such cases are on the increase in the Railways; and,

(c) if so, the main reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Late arrival of Up and Down Trains at Patna Junction

2695. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of Up and Down passenger trains arriving daily at Patna Junction Station;

(b) the number of trains which arrived in time and of those which arrived late during the months of November and December, 1973 and January, 1974; and

(c) The main reasons for their late running and the measures being taken by Government to ensure their running in time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) A total of 66 trains are scheduled to arrive daily at Patna Junction station.

(b) The total number of trains arriving Patna Junction right time in November, 1973, December, 1973 and January, 1974 has been 814, 710 and 801 respectively. The corresponding figures for the trains arriving late are 541, 640 and 640 respectively.

(c) The main reasons for late arrival of trains at Patna Junction have been disturbed law and order conditions, public demonstrations, various staff agitations, alarm chain pullings, disconnection of hose-pipes etc.

A close watch is, howevei, kept on running of the trains and all avoidable detentions are taken up for corrective action including punitive action taken against staff at fault to effect improvement in the punctuality.

Introduction of more Rajdhani Express Trains to cover more Cities

2696. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government propose to run more "Rajdhani Express" trains to cover more cities; and

(b) if so, the salient features of the proposal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) At present there is no proposal to run more Rajdhani Express trains.

(b) Does not arise.

वर्ष 1973 में भारतीय तेल निगम की अधिक बिक्री

2697. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1973 में भारतीय तेल निगम की बिक्री अधिक रही है; और

(ख) यदि हां, तो निगम को वर्ष 1972 और 1973 में कितना लाभ हुआ ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय तेल निगम की बिक्री तथा मुनाफों के ब्यौरे वित्तीय वर्ष वार तैयार किये जाते हैं । अतः सूचना वित्तीय वर्ष के आधार पर दी जा रही है । पिछले वर्ष की तुलना में 1972–73 में निगम की बिक्री अधिक थी ।

(ख) मूल्यह्रास, व्याज तथा कराधान के लिये व्यवस्था करने से पहले पिछले वर्ष में 53.42 करोड़ रुपये की तुलना में 1972–73 के दौरान 66.32 करोड़ रुपये का कुल लाभ हुआ । कर के पश्चात शुद्ध लाभ इस प्रकार था :—

1972–73	1971–72
22.17 करोड़ रुपये	31.94 करोड़ रुपये

नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता और इन्चेक टायर लिमिटेड, कलकत्ता का निवेश-ढांचा

2698. **श्री रानेन सेन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1973 को नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता और इन्चेक टायर लिमिटेड, कलकत्ता का निवेश ढांचा क्या था ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता और इन्चेक टायर लिमिटेड, कलकत्ता के तुलन-पत्रों के अनुसार क्रमशः 31 दिसम्बर, 1972 और 30 जून, 1973 तक, उन की परिसम्पत्तियों के प्रस्तुत ढांचे की निवेश संरचना, अनुलग्न विवरण-पत्र में दी जाती है ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

	नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता	इन्चेक टायर्स लिमिटेड, कलकत्ता
	31-12-1972 तक	30-6-1973 तक
1. आवधिक परिसम्पत्ति	173.20	288.52
2. तालिकाएं	176.76	302.92
3. निवेश		
(क) सरकारी आरक्षित . . .	0.01	—

	नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता	इन्चेक टायर्स लिमिटेड, कलकत्ता
(ख) अन्य आरक्षित . .	0.49	
(ग) निगमित निकाय		
1. केप्सिल (एजेन्सीज) लिमिटेड	0.10	—
2. इन्चेक टायर्स लिमिटेड . . .	36.31	—
4. ऋण और अग्रिम धन . .	52.55	24.49
5. रोकड़ एवं बैंक शेष . .	34.90	46.40
6. अन्य वर्तमान परिसम्पत्ति (सन्ड्री ऋणदाता)	99.85	47.76
कुल परिसम्पत्ति	574.17	710.09

नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स (लिमिटेड) कलकत्ता के कार्यकरण की जांच

2699. **श्री रानेन सेन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता के कार्यकरण की 1972 में कोई जांच की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(4) के अन्तर्गत, इस कम्पनी की लेखा-वहियों का एक निरीक्षण किया गया था ।

(ख) इस निरीक्षण रिपोर्ट से कुछ उल्लक्षण, जैसे, कच्चे माल के उधार, एक कम्पनी को प्राकृतिक रबड़ की बिक्री तथा इसके पश्चात इसी की पुन: खरीद, बिना टेन्डर आमन्त्रित किये माल की खरीद, तथा कम्पनी के लाभों में अवनति, प्रकाश में आये ।

(ग) यह निर्णय करने की दृष्टि से कि क्या, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233क के अन्तर्गत विशिष्ट लेखा-परीक्षा के आदेश देने चाहिएं, इन उल्लक्षणों की बाबत कम्पनी से स्पष्टीकरण मांगा गया था । कम्पनी ने एक लिखित उत्तर भेजा व इस विषय में सुनवाई भी हुई थी । लिखित अभ्यावेदन व सुनवाई पर किये गये प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के पश्चात, कम्पनी विधि बोर्ड ने विशिष्ट लेखा-परीक्षा न किये जाने का निर्णय किया

खराब माल डिब्बों की संख्या और उनकी मरम्मत

2700. **श्री रानेन सेन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत बड़ी संख्या में माल डिब्बे-खराब हो गये हैं और वे विभिन्न रेलवे वर्कशापों और स्टेशनों पर खड़े हैं जिसके परिणामस्वरूप रेलवे में चलने वाले माल डिब्बों की कमी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो खराब माल डिब्बों की मरम्मत और नये माल डिब्बों के निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं, खराब माल डिब्बों की कुल संख्या न्यूनतम अनुमत संख्या के आस-पास ही है ।

(ख) खराब माल डिब्बों की मरम्मत के लिए आवश्यक व्यवस्था पहले से ही मौजूद है । रेलों के संचालन में माल डिब्बों में खराबी आ जाना एक आम बात है । धन की उपलब्धता, उत्पादन क्षमता और यातायात की जरूरतों को देखते हुए नये माल डिब्बों का भी निर्माण किया जा रहा है ।

पश्चिमी बंगाल को बिजली की सप्लाई

2701. **श्री रानेन सेन :**

श्री समर गुह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों में सप्लाई की जा रही बिजली अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में बिजली की उपलब्धता इसकी मांग से कम होने के कारण, उद्योगों तथा अन्य सैक्टरों की बिजली की सप्लाई पर पाबन्दियां लगाई हुई हैं । राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता मांग के अनुसार नहीं बढ़ी है और संयंत्र भी बड़ी धीमी गति से उपलब्ध हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप बिजली में कमी आ गई है । संथालडीह में 120 मेगावाट की नयी उत्पादन यूनिट के स्थिरीकरण, पांचवीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल प्रणाली में उत्पादन क्षमता के आवर्धन तथा संयंत्रों के प्रचालन में सुधार से विद्युत स्थिति काफी हद तक सुधर जाएगी । पांचवीं योजना अवधि के दौरान राज्य में 768 मेगावाट तक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता चालू करना प्रस्तावित है । निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि उन्हें अनुसूची के अनुसार चालू किया जा सके ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण की जांच के लिये समिति

2702. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक समिति अथवा आयोग नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उस की रचना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Detachment of Bogies from Dehradun Express at New Delhi

2703. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether some bogies of Dehradun Express are detached at New Delhi Station; and

(b) if so, what difficulty Government have to allow these bogies to remain in the train upto Delhi Station ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, but an equal number of coaches of different classes are also attached.

(b) Attaching and detaching of these coaches at Delhi Station is not feasible due to shunting difficulties in the heavy morning and evening grouping periods and lack of adequate stabling facilities at Delhi.

Issue of woollen over-coats to Guards on Western Railway

2704. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether in some sections of the Western Railway, issuing of woollen over-coats to the Guards has been discontinued;

(b) if so, the names of the areas where the issue of over-coats has been discontinued; and

(c) the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) Ratlam Division; Bhavnagar Division; Rajkot Division; Ajmer Division except Madar; Jaipur Division except Madar to Rewari section and north and west of this line; Kota Division except Bharatpur-Bayana section.

(c) As per the Revised Dress Regulations of the Railway Board, over-coats are to be supplied in 'Winter only' and 'Very cold' areas. As the places mentioned in part (b) do not fall under either, supply of woollen over-coats is not admissible.

उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मनीपुर में चुनाव प्रत्याशियों से पैट्रोल की खपत में कमी करने के लिये अपील

2705. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोल की कमी को ध्यान में रखते हुए उनके मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मनीपुर में विधान सभाओं के निर्वाचन में प्रत्याशियों से पैट्रोल की न्यूनतम खपत करने की अपील की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी प्रत्याशी से कोई निश्चित उत्तर प्राप्त हुआ है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हावड़ा और वाल्टेयर के बीच विद्युत् गाड़ी

2706. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा और वाल्टेयर के बीच विद्युत् से चलने वाली यात्री गाड़ियां चलाने की योजना है; यदि हां, तो कब से; और

(ख) क्या देश में बिजली की भारी कमी को देखते हुए बिजली की बचत करने हेतु विद्युत गाड़ियों को न चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हावड़ा-खड़गपुर खण्ड पहले से ही विद्युतीकृत है और इस खण्ड पर यात्री गाड़ियां भी चल रही हैं । जहां तक खड़गपुर और वाल्तेरू के बीच बाकी बचे हुए खण्ड का संबंध है, इस समय इसे विद्युतीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

उड़ीसा में द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत 'टेस्ट रिलीफ' कार्यों पर किया गया व्यय

2707. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बालासोर मयूर-भंज जिलों में इस समय द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई 'टेस्ट रिलीफ' कार्य चल रहा है और यदि हां, तो कितने व्यक्ति और कहां पर काम पर लगाये गये हैं; और

(ख) सितम्बर, 1973 से दिसम्बर, 1973 के बीच इन कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य सरकार ने सूचना दी है कि सिंचाई को पुनः चालू करने के लिए नहर में दरारों को बन्द करने में परीक्षण राहत कार्यों और बालासोर मयूरभंज जिलों में बाढ़ तथा शारीय तटबंधों में दरारों को बन्द करने के कार्यों पर एक हजार व्यक्तियों को लगाया गया है । सितम्बर से दिसम्बर, 1973 तक कुल 7.03 लाख रुपये खर्च किये गये थे ।

उड़ीसा में उद्योगों को बिजली की सप्लाई

2708. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में उद्योगों को दी जाने वाली बिजली में कटौती की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इससे उद्योग कहां तक प्रभावित हुए हैं ; और

(ग) उद्योगों को बिजली सप्लाई की मात्रा निश्चित करने की क्या कसौटी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समय उड़ीसा में बिजली में कोई कटौती नहीं की जा रही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अशोधित तेल का क्रय मूल्य

2709. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा अशोधित तेल किस मूल्य पर खरीदा जाता है, इसको साफ करने के बाद उसकी क्या लागत बैठती है और सरकार द्वारा उस पर कितना शुल्क लगाया जाता है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : कच्चे तेल की कोई मानक क्रय दर नहीं है । एफ०ओ०बी० मूल्य क्वालिटी सप्लाई के स्रोत तथा वे प्रबन्ध/करार, जिनके अंतर्गत आयात किया जाता है, पर निर्भर है । कच्चे तेल के देशीय उत्पादकों को वह विक्रय मूल्य प्राप्त होता है जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है । शोधित किये जाने के बाद कच्चे तेल से कई उत्पाद प्राप्त होते हैं । क्योंकि इस में संयुक्त उत्पादन होता है, प्रत्येक उत्पाद की उत्पादन लागत का निर्धारण करना संभव नहीं है । शोधनशालाओं को विभिन्न उत्पादों के लिये सी०आई०एफ० मूल्यों की इजाजत दी जाती है ताकि उन के समस्त कार्यों की लागत पूरी करने के पश्चात् उन्हें कुछ समग्र रूप से अतिरिक्त राशि दी जा सके । विभिन्न उत्पादों के आयात/उत्पादन शुल्कों की विभिन्न दरें हैं ।

पेराक्साईलीन संयंत्र के कम्प्रेशर में दोष

2710. **श्री रण बहादुर सिंह :**

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम जर्मनी के निर्माता पेराक्साईलीन संयंत्र के अत्याधुनिक कम्प्रेशर के दोषों के दूर करने में असफल रहे हैं, जिससे पैट्रो-रसायन उत्पादन कार्यक्रम में गड़बड़ हो गई है और कोयली पैट्रो-रसायन उद्योग समूह की 28 करोड़ रुपये की एरोमेटिक परियोजना को काफी हानि हुई है ;

(ख) क्या कम्प्रेशर में यह गड़बड़ बार-बार हो रही है और एरोमैटिक परियोजना के अन्य एककों के कार्यकरण पर भी इसका गम्भीर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने डी०एम०टी० की मांगों की पूर्ति के लिये क्या उपाय किये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) पैरा जाइलीन संयंत्र का प्रोपेन कम्प्रैशर जो कि हवाई जहाज द्वारा पश्चिम जर्मनी में निर्माताओं के पास भेजा गया था, मरम्मत हो जाने के पश्चात् 25-2-74 को स्थल पर फिर प्राप्त कर लिया गया था तथा अब पुनः चालू कर दिया गया है। पैरा जाइलीन संयंत्र के चालू हो जाने से, डी०एम०टी० यूनिट में भी शीघ्र ही उत्पादन पुनः शुरू हो जायेगा।

इसी बीच, उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिये डी०एम०टी० का अधिक से अधिक आयात किये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

बोदरा, पश्चिम बंगाल में तेल के लिये छिद्रण कार्य

2711. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोदरा, पश्चिम बंगाल, में तेल के लिये छिद्रण के सम्बन्ध में कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है; और

(ख) बोदरा में छिद्रण के सम्बन्ध में इस समय क्या सम्भावनायें हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में अन्वेषी व्यधन पर 31-3-1973 तक 292.54 लाख रुपये की रकम खर्च की जा चुकी है। इस कूप को 5,000 मीटर की गहराई तक खोदे जाने का लक्ष्य था किन्तु तकनीकी कठिनाइयों के कारण व्यधन कार्य 4197.5 मीटर की गहराई से ज्यादा नहीं किया जा सका। व्यधन किए गए कुओं से प्राप्त अनुकूल परिणामों के कारण बोदरा संरचना का अगला अन्वेषण व्यधन कार्य की कोई योजना निकट भविष्य में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तैयार नहीं की गई है।

हावड़ा स्टेशन पर आकस्मिक श्रमिकों को मिलने वाली मजूरी की दरों पर काम करने वाले कुली

2712. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय-समय पर दी गई अस्थायी मंजूरी के अन्तर्गत हावड़ा स्टेशन पर कुछ व्यक्ति आकस्मिक श्रमिकों को मिलने वाली मजूरी की दरों पर कुली के रूप में काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कुली कितने वर्षों से इन दरों पर काम कर रहा है; और

(ग) क्या उन्हें "प्रति स्थापक" के रूप में खपाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हावड़ा और सियालदह स्टेशनों को नया रूप देना

2713. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान हावड़ा और सियालदह दो बड़े स्टेशनों पर काफी भीड़ रहती है; और

(ख) मंत्रालय ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हावड़ा और सियालदह स्टेशनों को नया रूप देने का क्या कार्यक्रम बनाया है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित सर्वेक्षण किये जा रहे हैं :—

(1) हावड़ा और सियालदह मण्डलों में उपनगरीय तथा अनुपनगरीय यातायात को सम्भालने के लिए अपेक्षित खण्डीय और टर्मिनल सुविधाओं, पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व रेलों के पार्सल यातायात के लिए टर्मिनल सुविधाओं, हवड़ा में दक्षिण -पूर्व रेलवे की उपनगरीय गाड़ियों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं और हावड़ा एवं सियालदह से माल यातायात के विसर्जन हेतु सुविधाओं के लिए तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण। हावड़ा स्टेशन से सम्बन्धित सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच हो गयी है और निम्नलिखित निर्माण कार्य 1974-75 के बजट में चरण 1 के रूप में सम्मिलित किये गये हैं :—

(i) हावड़ा के सामान्य भण्डार एवं सिगनल कारखाने के ढांचों के बदलाव और उनका बेलूर में स्थानान्तरण।

(ii) बेलूर स्कैप यार्ड के ढांचों का बदलाव और उसका दानकुनि में स्थानान्तरण। इन निर्माण कार्यों से हावड़ा में टर्मिनल सुविधाओं का और विस्तार करने के लिए स्थान उपलब्ध हो जायेगा जिसे अनुवर्ती चरणों में किया जाना है।

(2) कलकत्ता (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में उपनगरीय टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

Late Running of Trains in Eastern Zone

2714. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a large number of trains running in the Eastern Zone reach their destinations very late;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the measures taken by Government to run these trains in time and the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) The punctuality performance of the trains in the Eastern Zone has not been satisfactory of late due to various factors like staff agitations, alarm chain pulling, disconnection of hose-pipes, public agitations and bandhs etc.

(c) The running of trains is closely watched at various levels and avoidable detentions are taken up for corrective action including punitive action taken against staff at fault to effect an improvement in the punctuality.

Late Running of passenger and shuttle trains between Patna and Arrah

2715. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the employees of Patna Secretariat and other offices there have to encounter difficulties because of late running of passenger and shuttle trains between Arrah and Patna while the fast trains running on the main line from and to Delhi and Calcutta are in operation ;

(b) whether they are often compelled to board the fast trains and to pull chains at all stations between Patna and Arrah for unboarding them ;

(c) whether he had received any representation in this regard during the last three months from any Member of Parliament; and

(d) if so, the main features thereof and the action taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) The punctuality of 387/388 Arrah Patna Passengers which serve the office workers travelling between Arrah and Patna has been quite satisfactory during the last three months and the running of these trains is generally not affected by Mail/Express trains. Some of the passengers, however, choose to travel by Mail/Express trains and stop the trains by pulling the alarm chain at places where they are not scheduled to halt.

(c) & (d) A representation, in this regard has also been received from a Member of Parliament, the position in respect of which is indicated above.

रेल कर्मचारियों को सशस्त्र सेनाओं और सीमा सुरक्षा दल के समान राशन और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

2716. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग को भी सशस्त्र सेनाओं और सीमा सुरक्षा दल की तरह आवश्यक सेवा माना जाता है ;

(ख) क्या सशस्त्र सेनाओं और सीमा सुरक्षा दल को राशन और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में विशेष प्राथमिकता दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे कर्मचारियों के लिए भी सशस्त्र सेनाओं और सीमा सुरक्षा दल की तरह आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के प्रबंध किए जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलवे विभाग बिल्कुल उसी आधार पर नहीं है जिस आधार पर सशस्त्र सेनाएं और सीमा सुरक्षा दल है ।

(ख) सशस्त्र सेनाएं अपने भोजनालय और राशन की सप्लाई की व्यवस्था स्वयं करती हैं । इसलिए उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए खाद्यान्न का आवंटन सीधे सेन्ट्रल पूल से किया जाता है ।

जहां तक सीमा सुरक्षा दल का संबंध है, कुछ क्षेत्रों में केवल अराजपत्रित कर्मचारी ही आवश्यक वस्तुएं अतिसीमित मात्रा में निर्धारित मूल्य पर प्राप्त कर रहे हैं । अन्य क्षेत्रों में उन्हें नागरिकों के समान ही माना जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पुनरीक्षित वेतनमानों, 1973 में वेतन निर्धारित करने में असमानता

2717. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनरीक्षित वेतनमानों, 1973 में वेतन निर्धारित करने में, जहां वर्तमान वेतनमानों में मंहगाई भत्ता स्लैब बदलता है बहुत अधिक असमानता रहती है ;

(ख) क्या कर्मचारियों से कहा गया है कि वे या तो, 1 जनवरी, 1973 से पुनरीक्षित वेतनमान ले लें अथवा अपनी आगामी वेतन वृद्धि की तिथि से ;

(ग) क्या अपनी आगामी वेतन वृद्धि की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान लेने वाले कर्मचारी को वर्तमान वेतनमान में मूल वेतन के 5 प्रतिशत का लाभ जो न्यूनतम 15 रुपये अथवा अधिकतम 50 रुपये तक हो सकता है, नहीं मिलता है जिसके परिणामस्वरूप बहुत हानि और वेतन निर्धारण में भारी असमानता रहती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या असमानता दूर करने के लिए सरकार का विचार 1 जनवरी, 1973 से पुनरीक्षित वेतनमानों के लिये विकल्प देने वालों तथा अपनी आगामी वेतन वृद्धि की तिथि से ऐसा विकल्प देने वालों के साथ समान व्यवहार करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1-1-1973 से पहले मंहगाई भत्ते की जो सोपान प्रणाली लागू थी उसके अंतर्गत 210--399 रुपये तक की वेतन श्रेणी के क्रमिक सोपानों के बीच महंगाई भत्ते की दर 12 रुपये से लेकर 33 रुपये तक भिन्न-भिन्न थी । चूंकि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप वेतन निर्धारण के विशेष फार्मूले के अनुसार संशोधित मान में वेतन का निर्धारण वर्तमान परिलब्धियों, जिनमें मंहगाई भत्ता, मंहगाई वेतन और अन्तरिम राहत शामिल हैं, के आधार पर करना अपेक्षित है। इसलिए इस प्रकार के सोपानों में उच्चतर मंहगाई भत्ता पाने वाले व्यक्ति उन व्यक्तियों की तुलना में तदनुरूपी ऊंची दर पर वेतन पाने के हकदार हैं जो इस तरह के सोपानों में निम्नतर मंहगाई भत्ता पा रहे थे ।

(ख) रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1973 के नियम 5 के अधीन रेल कर्मचारी 1-1-1973 से, अथवा उस तारीख से, जिससे वह अपने विद्यमान वेतन-मान में अगली वेतन-वृद्धि अथवा पश्चात्-वर्ती कोई वेतन वृद्धि अर्जित करता है अथवा अपना पद रिक्त करता है अथवा उस वेतन-मान में वेतन लेना छोड़ता है, संशोधित वेतन-मान का चयन कर सकता है ।

(ग) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो कर्मचारी विद्यमान वेतन-मान में अगली अथवा पश्चात्वर्ती कोई वेतन-वृद्धि अर्जित करने के बाद संशोधित वेतन-मान का चयन करता है, संशोधित वेतनमान में उसका वेतन मूल नियमों के अनुसार निर्धारित करना होगा, न कि उस विशेष वेतन-निर्धारण फार्मूले के अनुसार जिसकी सिफारिश आयोग ने उन व्यक्तियों के लिए की है जो इसके कार्यान्वयन की तारीख से संशोधित वेतन-मान का चयन करते हैं । मूल नियमों के अनुसार संशोधित वेतन-मान में वेतन के निर्धारण के लिए केवल चयन की तारीख वाले दिन के मूल वेतन को ही लेखे में लिया जा सकता है । लेकिन सरकार ने इस सिफारिश में सुधार करके यह व्यवस्था की है कि इस तरह के मामलों में चयन की तारीख वाले दिन ऐसे कर्मचारी के न केवल मूल वेतन को बल्कि 1-1-1973 से पहले लागू दरों के अनुसार उस मूल वेतन से संबंधित मंहगाई वेतन, मंहगाई भत्ते और अंतरिम राहत को भी संशोधित वेतन-मान में उसका वेतन निर्धारित करते समय गिना जाये ।

(घ) संयुक्त वार्ता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा कुछ असंगतियों पर विचार करने के लिए स्थापित की गयी समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस मामले पर आगे विचार किया जायेगा ।

औषध उद्योग के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने के लिये औद्योगिक विकास मंत्रालय के साथ परामर्श

2718. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास मंत्रालय ने "उद्योगों के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत, 1973-74" पत्रिका में प्रकाशित औषध और फार्मास्यूटिकल्स संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत तय करते समय उनके मंत्रालय से परामर्श किया था ; और

(ख) क्या उनमें भारतीय सेक्टर के लिये अधिकतम अंश को सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत उपायों का उल्लेख नहीं है और उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) औषध उद्योग की वर्तमान स्थिति संबंधी सूचना मार्ग निर्देशक सिद्धांतों में निहित है और भावी संभावनाओं में यथा उल्लिखित कुछ मदों की अतिरिक्त क्षमता उस में शामिल है । मार्ग निर्देशक सिद्धांतों में यह भी सुझाव दिया हुआ है कि उनके प्रस्तावों को तैयार करने से पूर्व ठेकेदारों को सलाह दी है कि वे पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तकनीकी विकास महानिदेशक आदि से मार्गदर्शन में सहायता लें । इच्छुक ठेकेदारों के लिए अनिवार्य सूचना प्रस्तुत करने की दृष्टि से मार्ग निर्देशक सिद्धांतों को तैयार किया गया है । समय-समय पर लागू सरकारी नीति के अनुसार इस प्रकार के ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं के लिए सरकार की अनुमति या लाइसेंस देने का निर्णय किया जाएगा ।

मैसर्स फाइजर्स के विस्तार के प्रस्ताव

2719. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स फाइजर्स के पूंजी-इजरा, जिसके लिये 1960 में सहमति दी गई थी; के विस्तार प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या पूंजी-इजरा के लिये भी इसकी स्वीकृति 1968 में दी गई थी; यदि हां, तो कितनी राशि के लिये और पूंजी-इजरा में इस वृद्धि की अनुमति कितने विस्तार के लिये दी गई है ;

(ग) क्या 1970 में अपनियोजन (भारतीय साम्य पूंजी को 25% से 40% तक बढ़ाने) संबंधी आदेश कार्यान्वित कर दिये गये हैं; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि मैसर्स फाइजर्स ने (1) निर्यात-बन्धक, (2) अपनियोजन, (3) तकनीकी निदेशालय के महानिदेशक द्वारा आक्सी-टेट्रा साइक्लाइन के लिये विशिष्ट सीमित संयंत्र की वास्तविक जांच आदि के संबंध में लाइसेंसिंग समिति के किन्ही निर्णयों का उल्लघंन किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) मैसर्स डयूक्स (प्राइवेट) लि० (फाइवर लि० में परिवर्तित) को मैसर्स फाइजर कारपोरेशन पनामा को अभिदत करने हेतु 10-6-1960 को सहमति दी गई । कम्पनी जिसकी प्रदत्त शाम्य पूंजी 75 लाख रुपये की

थी समस्त पूंजी मैसर्स फाइजर कारपोरेशन पनामा द्वारा रखी गई, को 25% की सीमा तक भारतीय साझेदारी जो निम्न प्रकार है, के पुरस्थापन करने के लिए 191 लाख रुपये की पूंजी के जारी होने के समय में 27-10-1965 को सहमति दी गई :—

(i) फाइजर कारपोरेशन पनामा को 10/- रुपये प्रतिशेयर की दर से शाम्य शेयर के रूप में 125 लाख रुपये।

(ii) प्रथम बार भारतीय जनता को विवरणिका के माध्यम से प्रत्येक शेयर 15 रुपये के प्रीमियम पर 10 रुपये प्रति शेयर की दर से साम्य शेयरों के रूप में 66 लाख रुपये । इस सहमति से कार्यान्वित किया गया इसका मुख्य उद्देश्य जैसा कि कम्पनी के आवेदन पत्र में दिया गया है, बम्बई एकक पावर वर्क्स बुलंदर को व्याने में बदलने के लिए कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उनका नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण करना तथा मूलभूत उत्पादन कार्यों के कुछ भागों के अनुमोदित विस्तार करना है। प्रत्येक 2 शेयर धारका बोनस शेयर देने की दर से 132.91 लाख रुपये के मूल्य के बोनस शेयर जारी करने की सहमति 13-6-1968 को कम्पनी को दी गई। 3 दिसम्बर, 1970 को कम्पनी को भारतीय साझेदारी पर सरकार का अनापत्ति पत्र जारी किया गया जिसको भारतीय क्षेत्र के नये पूंजी के रुपये 5 वर्ष अर्थात् 10 जून, 1975 तक स्थगित किया जा रहा है । वर्तमान 25% से 40% तक बढ़ाया जाना था।

टेट्रासाइक्लीन के उत्पादन के सम्बन्ध में मैसर्स फाइजर द्वारा निर्यात बांड के निष्पादन का प्रश्न अभी विचाराधीन है। पार्टी द्वारा स्थापित किये गये संयंत्र के वास्तविक जांच विकास के महानिदेशालय द्वारा की गई है ।

मैसर्स होचेस्ट को जारी किये गये लाइसेंस

2720. **श्री के० एस० चावड़ा :**

श्री सोम चन्द सोलंकी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स होचेस्ट को गत तीन वर्षों के दौरान जारी किये गये औद्योगिक और पूंजीगत उपकरणों और कच्चे माल के आयात के लिये जारी किये गये लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तीन महीनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उन्हें 'एनलजिन' के लिये उनके उत्पादन पर आधारित अग्रिम रिलीज आर्डर दिया गया है;

(ग) क्या किसी अन्य फर्म को भी 'एनलजिन' का अग्रिम कोटा दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) क्या इससे (एनलजिन) तैयार करने वाले छोटे एकक तथा सरकारी क्षेत्र में स्थित आई० डी० पी० एल० जो इससे मिलते जुलते उत्पाद की बिक्री कम मूल्य पर करता है, के हितों के प्रभावित होने की सम्भावना नहीं है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) एक विवरण संलग्न है। **(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल.टी.**—6396/74)

(ख) फ्लू, डेनजू, बुखार आदि की बहुत घटनाओं के कारण नवलजीन और वैरलमन की बढ़ती हुई मांग,को ध्यान में रखकर मैसर्स होचेस्ट को दिसम्बर 1973 में 1973-74 के चौथे क्वार्टर के दौरान उनकी हकदारी के स्थान पर उनको एनलजिन के केवल 5 टन अग्रिम आवंटित किए गए थे।

(ग) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स को सलाह दी गई थी कि ऐसे आवंटन के लिए किसी अन्य पार्टी द्वारा अनुरोध किए जाने पर उनको अग्रिम आवंटन के लिए किसी अन्य पार्टी ने आवेदन नहीं दिया है।

(घ) चूंकि अग्रिम आवंटन होचेस्ट के अन्तरवर्ती क्वार्टर के दौरान हकदारी के स्थान पर किया गया था इस लिए लघु उद्योग एकक तथा आई० डी० पी० एल० की इच्छाओं को ग्रस्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

Cancellation of 84 Up and 83 DN Passenger Trains between Agra and Kota

2721. **Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of Railways be pleased to state

(a) whether the 84 UP and 83 DN passenger trains operating between Agra and Kota had to be cancelled recently due to shortage of coal ;

(b) whether the cancellation of these passenger trains could have been avoided; and

(c) the loss Railways suffered on this account ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes. Between Bayana and Kota.

(b) No.

(c) Rs. 219,000/- from 1st November 73 to 28th February 74.

बम्बई में हुई विद्युत् विषयक विचार गोष्ठी

2722. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री पी० एम० मेहता :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1974 में बम्बई में विद्युत् विषय पर चार दिवसीय विचार-गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय किए गए; और

(ग) क्या उक्त विचार गोष्ठी में किन्हीं विदेशियों ने भी भाग लिया था?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) द्वारा पूना में 15 से 18 फरवरी, 1974 तक विद्युत् पर चार दिन की एक राष्ट्रीय गोष्ठी की गई थी।

(ख) विद्युत् विकास, दीर्घकालीन आयोजन, योजनाओं की क्रियान्विति, अनुसंधान व विकास तथा संरचनात्मक और प्रबन्ध समस्याओं के संबंध में निष्कर्ष निकाले गए तथा सिफारिशें की गईं।

(ग) विश्व ऊर्जा सम्मेलन के अध्यक्ष के एक प्रतिनिधि तथा बंगलादेश के अभियंताओं ने गोष्ठी में भाग लिया था।

रेलवे तथा दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम के बीच मतभेद

2723. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्द्रप्रस्थ तापीय बिजली घर में कोयले की स्थिति के बारे में रेलवे तथा दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या रेलवे को कहा गया है कि दिल्ली के बिजली घरों के लिये कोयला ले जाने हेतु अधिक वैगन उपलब्ध किये जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ताप बिजली घरों को कोयले की ढुलाई स्थायी संयोजन समिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाती है। रेलें दिल्ली के बिजली घरों सहित सभी बिजली घरों के लिए कोयले के लदान एवं उनकी ढुलाई को सर्वाधिक महत्व देती है।

दक्षिण रेलवे में कोयले की कमी

2724. **श्री आर० पी० स्वामीनाथन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कमी के कारण दक्षिण रेलवे को काफी नुकसान उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या 12 फरवरी, 1974 को दक्षिण रेलवे के पास केवल तीन दिन का कोयले का स्टाक था ;

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) उसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) रेलों के लिए भाप, कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए कोयला, उत्पादन प्राधिकरणों और इस्पात एवम् खान मंत्रालय के साथ घनिष्ट तालमेल स्थापित किया जा रहा है। यदि संचलन की सामान्य स्थिति बनी रहे तो 6-7 दिन के स्तर पर कोयले का स्टाक तैयार रखना सम्भव हो सकेगा।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रखी जायेगी।

तेल के प्रयोग में मितव्ययता के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

2725. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के प्रयोग में मितव्ययता लाने के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये गये हैं;

(ख) क्या इस बारे में मंत्रालय और योजना आयोग के बीच कोई मतभेद है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) तेल के संकट को दृष्टि में रखते हुए इसके प्रयोग के बारे में देश को स्पष्ट मार्गदर्शन देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) भट्टी के तेल पर स्थाई समिति ने तेल के प्रयोग में प्रभावी मितव्ययता के लिए मार्गसूचक बातों के विकास हेतु एक उप-समिति गठन की है। एन० पी० सी० जैसे तकनीकी निकायों को इस ग्रुप से सम्बन्ध किया गया है। कुछ उद्योगों ने स्वयं ईन्धन तेल की मितव्ययता हेतु साधनों का विकास किया है तथा इन बातों की अन्य उद्योगों को भी सिफारिश की जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उटता।

(घ) इस कार्य हेतु तकनीकी विकास के महानिदेशक एवं सचिव की अध्यक्षता में एक स्थाई समिति का गठन किया गया है। यह समिति इस सम्बन्ध में उपयुक्त मार्गदर्शन के तरीकों की खोज करके उद्योगों को बतलाएगी।

कलकत्ता और मद्रास की उपनगरीय गाड़ियों में अत्यधिक भीड़

2726. श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कलकत्ता और मद्रास में चलने वाली उपनगरीय गाड़ियों में अत्यधिक यातायात और भीड़ रहती है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उपनगरीय गाड़ियों में प्रतिदिन यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को राहत और आराम पहुचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) मद्रास और कलकत्ता में यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाइन क्षमता, पर्यन्त क्षमता, चल स्टाक आदि के रूप में अपेक्षित साधनों की उपलब्धता के अनुरूप अतिरिक्त उपनगरीय गाड़ियां चलाई जाती हैं।

गुजरात में तेल क्षेत्रों में खुदाई का कार्य स्थगित करना

2727. **श्री पी० जी० भावलंकर :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात में अब तक प्रयोग में लाये जा रहे कुछ तेल क्षेत्रों में खुदाई तथा अन्य कार्य स्थगित कर दिया है अथवा स्थायी तौर पर बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके बन्द होने के कारण कितनी हानि हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद और बम्बई के बीच वातानुकूलित डीलक्स एक्सप्रैस गाड़ी पुनः चलाने का प्रस्ताव

2728. **श्री पी० जी० मावलंकर :**

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद और बम्बई के बीच वातानुकूलित डीलक्स एक्सप्रेस गाड़ी पुनः चलाने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब और कितने-कितने समय पश्चात् ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उटता।

(ग) यातायात सम्बन्धी औचित्य एवं अतिरिक्त वातानुकुलित रेलों के अभाव के कारण।

†रेलवे के लिए बिजली घरों की स्थापना के लिये विदेशी तकनीकी सहायता

2729. **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के लिये बिजली-घरों की स्थापना हेतु कोई विदेशी तकनीकी सहायता मांगी गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों ने उक्त सहायता की पेशकश की है ; और

(ग) क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के विचार भी प्राप्त कर लिये गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में कमीशन के आधार पर काम कर रहे बैरे

2730. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या फ्रंटियर मेल के बैरे रेलवे में कमीशन के आधार पर काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या ये बैरे रेलवे में गत 7 वर्षों से कमीशन बैरे के रूप में काम कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो बिक्री पर उनके कमीशन की दर क्या है ;

(घ) क्या इन बैरों को आवास और निशुल्क पास जैसी वे सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जो रेलवे के अन्य कर्मचारियों को मिलती हैं ; यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन्हें अधिक लाभ और सुविधाएं प्रदान करने का है ; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) फ्रंटियर मेल के कुछ बैरे कमीशन के आधार पर काम कर रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) कमीशन पर काम करने वाले बैरों के कमीशन की दर कुल बिक्री की 10 प्रतिशत है।

(घ) कमीशन पर काम करने वाले बैरे रेल कर्मचारी नहीं हैं, इसलिये वे आवास, निःशुल्क पास आदि जैसी सुविधाओं के पात्र नहीं हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों के भारी संख्या में काम पर न आने के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे में गाड़ियों का रद्द किया जाना

2731. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र डिवीज़न में सहायक स्टेशन मास्टरों के भारी संख्या में काम पर न आने के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे में 8 फरवरी, 1974 को अनेक गाड़ियां रद्द कर दी गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कारण से कितनी गाड़ियां रद्द की गईं और वे कितने समय तक रद्द रहीं ; और

(ग) जनवरी और फरवरी, 1974 में गाड़ियां रद्द किये जाने के कारण रेलवे को ल िकतनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहमम्द शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 4-2-74 से 8-2-74 तक सहायक स्टेशन मास्टरों की सामूहिक अनुपस्थिति के कारण आंध्र मंडल में 14 जोड़ी सवारी गाड़ियां रद्द की गयीं थीं।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गाड़ियों का समय पर चलना

2732. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या देश के विभिन्न भागों में बहुत-सी गाड़ियां निर्धारित समय पर नहीं चल रहीं हैं, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : पिछले कुछ समय में गाड़ियों का समय पालन, खासकर पूर्वी और उत्तरी भाग में, संतोषजनक नहीं रहा। इनके समय पालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के मुख्य कारण ये हैं :--कर्मचारियों तथा जनता द्वारा किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के एक के बाद एक आन्दोलन, बिजली की कटौतियां, लाइनों की टूट-फूट, दूर संचार तारों की चोरी जिसके परिणामस्वरूप सिगनल और दूर संचार व्यवस्था ठप्प हो जाना, कोयले की कठिन स्थिति, खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं में वृद्धि आदि।

पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ के डीज़ल के ड्रमों का गणेश चीनी मिल के अहाते के अन्दर जब्त किया जाना

2733. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ के डीज़ल के ड्रमों को गोरखपुर जिले में गणेश चीनी मिल, आनन्दनगर के अहाते के अन्दर जब्त किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो संबंधित अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी हां, आपको फरेंदा की स्थानीय पुलिस ने गणेश शुगर फैक्टरी, आनन्दनगर के परिसर में पूर्वोत्तर रेलवे के लगभग 2,000 रु० के मूल्य के डीजल तेल के 10 ड्रम रेलवे ट्रैक्टर पर पकड़े थे। पांच व्यक्ति मौके पर गिरफ्तार किए गए और एक ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411 और अनिवार्य पण्य अधिनियम की धारा 2/7 के अधीन दो मामले दर्ज किए गये और पुलिस इनकी जांच-पड़ताल कर रही है। इस मामलें के अन्तर्गत तीन रेल कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध आगे की विभागीय जांच जारी है।

भारत में तेल क्षेत्र

2735. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितने तेल क्षेत्र हैं; और

(ख) उनके मंत्रालय से भारत के ज्ञात तेल क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) भारत में ढूंढ़े गये तेल क्षेत्रों की कुल संख्या 33 है। इसमें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के 25, आयल इंडिया के 3 और आसाम आयल कम्पनी के 5 तेल क्षेत्र शामिल हैं।

(ख) उनके क्षेत्रों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग तथा ग्रायल इंडिया के क्षेत्रों में व्यवधन तथा उत्पादन संबंधी कार्यों को तेज किया जा रहा है। देश में ग्रासाम ग्रायल कम्पनी के 5 तेल क्षेत्र सबसे पुराने हैं ग्रौर उनके उत्पादन में कमी हो रही है।

नाभा जाने वाले एक टैंकर से जबरन डीज़ल तेल का वितरण

2736. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **पैट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीज़ल तेल से भरे नाभा जाने वाले एक टेंकर को किसानों ने, जिनके पास खाली कनस्तर थे, 13 फरवरी, 1974 को रास्ते में रोक लिया तथा ड्राइवर को इसके वितरण के लिये पेट्रोल पम्प पर ले जाने के लिये विवश किया ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) ग्रौर (ख) यह बतलाया गया है कि ऐस्सो ने हाई स्पीड डीज़ल आयल वाली एक टैंक लारी अपने परिमाला डिपो से नाभा भेजी थी। मार्ग में किसी दूसरे पैट्रोल पम्प पर एकत्रित किसानों की बड़ी भीड़ ने उस टैंक लारी को रोक लिया था ग्रौर उन्होंने प्रार्थना की थी कि वह डीज़ल उनको बांट दिया जाये क्योंकि वो लोग लम्बी अवधि से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जिला प्राधिकारी शीघ्र उस स्थल पर पहुंचे ग्रौर उन्होंने यह उचित समझा कि ऐस्सो के स्थानीय पेट्रोल पम्प से डीज़ल आयल प्रतीक्षा करने वाले किसानों से उसका मूल्य लेकर उनमें बांट दिया जाए। तत्पश्चात् एक टैंक ट्रक नाभा भिजवाने की व्यवस्था की गई थी।

मट्टी-तेल की कमी का डबलरोटी के उत्पादन पर प्रभाव

2737. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **पैट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी-तेल की कमी के कारण दिल्ली जैसे लगभग बड़े शहरों में डबलरोटी आसानी से उपलब्ध नहीं है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहन नवाज खां) : (क) ग्रौर (ख) जनवरी, फरवरी, मार्च, 1974 के दौरान सभी उद्योगों के संबंध में मिट्टी के तेल की सप्लाई पर 10 प्रतिशत की दक्षता-कटौती लागू की गई है। आशा की जाती है कि अच्छे संरचनात्मक कार्यों तथा उत्पादों पर प्रभाव डाले बिना, ईंधन के प्रयोग में मितव्यता से यह बचत प्राप्त की जा सकेगी।

Setting up of Fertilizer plants in Co-operative sector in Fifth Plan

2738. **Shri Jagannath Mishra:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Government are considering any proposal to set up fertilizer factories in the co-operative sector during the Fifth Five Year Plan ; and

(b) if so, the State-wise information in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Yes, Sir.

(b) (i) **Maharashtra:** A letter of intent has been issued in favour of Maharashtra Co-operative Fertilisers and Chemicals for an ammonia, soda ash and ammonium chloride-complex at Tarapore.

(ii) **U.P.:** Issue of letter of intent in favour of Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd. for an ammonia/urea plant at Phulpur has been approved.

(iii) **Gujarat :** Proposals have been received for a phosphoric acid and NPK plant at Kandla.

आसाम में अशोधित तेल परिष्करण संयंत्र की स्थापना

2739. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी**: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में एक अशोधित तेल परिष्करण संयंत्र की स्थापना की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा यह कब से चालू हो जायेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कच्चा तेल अनुकूलित करने के लिये 3.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मोरन में एक अशोधित तेल अनुकूलन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसकी रुपांकित क्षमता प्रतिवर्ष 1.25 मिलियन मीटरी टन की दर से अशोधित तेल अनुकूलित करने की होगी। इस परियोजना के 1976 के प्रारम्भ में पूर्ण हो जाने की आशा है।

रतनगढ़ में पैदल चलने वालों के लिये उपरी पुल

2740. **डा० कर्ण सिंह**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रतनगढ़ में पैदल चलने वालों के लिये उपरीपुल के निर्माण के लिये राजस्थान सरकार अपना अंश देने के लिये सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो लोगों की कठिनाइयां दूर करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) रतनगढ़ यार्ड में पैदल चलने वालों के लिये ऊपरी पुल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, रतनगढ़ यार्ड में वर्तमान समपार सं० सी/191 के स्थान पर सड़क के नीचे पुल बनाने के लिये एक प्रस्ताव है। राज्य सरकार/स्थानीय नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा सड़क के नीचे पुल बनाने के लिये अपने हिस्से की लागत वहन करने की स्वीकृति अभी तक नहीं भेजी गयी है। यह मामला अभी रतनगढ़ नगरपालिका प्राधिकारी के पास रखा हुआ है।

रूस से मिट्टी के तेल का आयात तथा राज्यों को इसका वितरण

2741. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मिट्टी के तेल की कमी को पूरा करने के लिये रूस से कितना मिट्टी का तेल आयात किया गया ;

(ख) बिभिन्न राज्यों को इसका वितरण किस प्रकार किया गया ; और

(ग) क्या रूस से और अधिक मिट्टी का तेल आयात किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शह नवाज खां) (क) से (ग) भारतीय तेल निगम ने 1974 के दौरान केवल 1 मिलियन मी० टन मिट्टी के तेल के आयात करने के संबंध में रूसी सप्लाई कर्त्ताओं के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किये हैं।

अन्य बातों के साथ -साथ मिट्टी के तेल का कोटा उत्पाद की कुल उपलब्धता पर आधारित है तथा आयातित उत्पादों का कोई प्रथक आवंटन नहीं किया गया।

राज्यों में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

2742. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजनों के 20,000 दुर्बल क्षेत्रों (डविंडल्ड एरियाज) में बिजली लगाने के लिये 1971 में आरम्भ की गई केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित-हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की विशेष योजना पर राज्यों की प्रतिक्रिया अत्यधिक असन्तोषजनक रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के पास यह मामला उठाया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) दिसम्बर 1971 में भारत सरकार ने पहले से विद्युतीकृत ग्रामों को निकटवर्ती हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम के माध्यम से राज्य बिजली बोर्डों को रियायती ऋण सहायता देने को एक स्कीम प्रारंभ की है। 1971-72 और 1972-73 के दौरान इस स्कीम को अच्छा प्रोत्साहन मिला। बहरहाल, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रगति धीमी रही।

(ख) ऋण सहायता प्राप्त करने की पूर्व-शर्तों में से एक शर्त यह है कि बोर्ड बिजली ऊर्जा खपत प्रभारों के भुगतान के संबंध में संबंधित स्थानीय निकायों से आश्वासन प्राप्त करें। यह शर्त कई मामलों में पूरी नहीं की गई है।

(ग) जी, हां। स्कीमों में तेजी लाने के उद्देश्य से यह मामला हाल ही में संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है। उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

भाप तथा डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण करने में आत्मनिर्भरता

2743. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाप तथा डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण करने के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या देश में बिजली से चलने वाले इंजनों का भी निर्माण किया जा रहा है और यदि हां, तो वर्ष 1973 के दौरान ऐसे कितने इंजनों का निर्माण किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) चितरंजन रेल इंजन कारखाना और डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी ऐसे दो उत्पादन यूनिट हैं जिनमें रेलों के लिये इंजनों का निर्माण किया जाता है। इन उत्पादन यूनिटों में उत्पादन द्वारा भाप और डीजल रेल इंजनों की आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं।

(ख) चितरंजन रेल इंजन कारखानें में बिजली रेल इंजनों का भी निर्माण किया जाता है और आशा है कि 1973-74 में 43 बिजली रेल इंजनों का उत्पादन होगा।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तृतीय श्रेणी की शायिकाओं और चैयरों वाली अधिक वातानुकूलित गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव

2744. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तृतीय श्रेणी की शायिकायों और चेयरों वाली अधिक वातानुकूलित गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) क्या इस बारे में कोई योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में अपर कृष्णा नदी परियोजना को पूरा करने के लिये सहायता

2745. **श्री पी० आर० शिनय :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई आयोग ने यह सिफारिश की है कि पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी करने वाली बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र तथा कुशलता के साथ पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार को राज्य को बिशेष धन देकर सहायता करनी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य में अपर कृष्णा नदी परियोजना शीघ्र तथा कुशलता के साथ पूरी करने के लिये राज्य को क्या सहायता दी गई है अथवा देने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) सिंचाई आयोग ने सिफारिश की थी कि जब कोई सिंचाई स्कीम इतनी बड़ी हो कि उसके लिये राज्य के अपने योजना

संसाधनों से समुचित वित्त व्यवस्था न हो सके तो स्कीम के लिये विशेष वित्तीय प्रबंध करने हेतु राज्य को केन्द्रीय सरकार से बातचीत करनी चाहिये।

इस समय, सिंचाई परियोजनाएं राज्य योजनाओं का भाग हैं और राज्य योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशेष विकास शीर्ष या परियोजना से संबंध नहीं होती। पांचवी योजना के दौरान राज्यों के मध्य केन्द्रीय सहायता के वितरण को नियंत्रित करने के सिद्धान्तों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। राज्य की पांचवी योजना में अपर कृष्णा परियोजना के लिये परिव्यय को भी अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

भारत द्वारा फारस की खाड़ी के देशों के साथ संयुक्त उपक्रम से मिलने वाले रुस्तम अशोधित तेल में से अपने भाग की बिक्री बन्द करना

2746. **श्री पीलू मोदी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने फारस की खाड़ी के देशों के साथ संयुक्त उपक्रम से मिलाने वाले रुस्तम अशोधित तेल में से अपने भाग की बिक्री बन्द करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इससे भारत में तेल शोधक कारखानों के लिये कितना अतिरिक्त तेल उपलब्ध होगा ; और

(ग) फारस की खाड़ी में तेल की खुदाई में लगे भारत के अन्य सहयोगियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1974 में भारत में परिष्करण के लिये उपलब्ध रुस्तम अशोधित तेल की मात्रा लगभग 0.52 मिलियन मी० टन होगी।

(ग) फारस की खाड़ी के उद्यम में लगे भारत के सहयोगियों को इससे कोई संबंध नहीं है कि भारत अपने अशोधित तेल के अंश का कैसे और कहां निपटाता है।

Construction work on Farraka Barrage

2747. **Shri Hukam Chand Kachwai:**

Shri Shanker Rao Savant:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Government have deferred the construction work on the Farraka Barrage for the time being;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the time by which it is expected to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Shri Siddheshwar Prasad):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Work on the Farakka Barrage has been completed. The Feeder Canal is in an advanced stage of execution and is expected to be made ready for operation by monsoon 1974.

ब्रैडी एंड कम्पनी, बम्बई

2748. **श्री शंकर राव बासन्त :** क्या **विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मंत्री** "डी एण्ड कम्पनी, बम्बई" के प्रबधंकों पर आरोपों से संबंधित 20 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1398 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71, 1971–72 ग्रौर 1972–73 में ब्रैण्डी एण्ड कम्पनी का ग्रानुषंगिक व्यय कितना हुग्रा :

(ख) क्या कम्पनी ने इस बात के बावजूद ऋण दिये हैं कि कम्पनी के सभी ग्रन्तर्नियमों के ग्रनुसार ऋण देने की ग्रनुमति नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के ऋणों की राशि कितनी है, ये ऋण किन-किन व्यक्तियों को मिले हैं तथा ग्रब तक ऋण की कितनी राशि समय पर वापिस मिल चुकी है ; ग्रौर

(घ) कम्पनी के ग्रौर कुप्रबन्धों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुग्रा) : (क) डब्ल्यु एच० ब्रैडी एण्ड कम्पनी द्वारा किये गये "प्रासंगिक व्यय" निम्न प्रकार है :—

	रु०
31-12-1970 की वर्ष समाप्ति	1,49,459.16
31-12-1971 की वर्ष समाप्ति	2,00,544.00

31-12-72 की वर्ष समाप्ति तक के अलग आंकड़े जैसा कि ये प्रासंगिक व्यय "विविध व्यय" में सम्मिलित नहीं किये जाते हैं ग्रौर कानून में भी अलग आंकड़े प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, अतः प्राप्य नहीं है ।

(ख) हमारी सूचना के अनुसार, कम्पनी धन उधार देने में सशक्त है ।

(ग) कम्पनी के 31-12-1972 तक के तुलन-पत्र के अनुसार, उसके ऋण सुरक्षित ग्रौर असुरक्षित —93,05,000 रुपये थे। 31-12-1971 तक 99,70,000 रुपये थे। 31-12-1971 तक ऋण के मुख्य प्राप्तिकर्त्ता के नाम अधिशेष (ब्याज सहित) निम्नांकित हैं :—

	रु०
1. मेसर्स गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड	37,30,000
2. मैसर्स शक्ति ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	—
3. मैसर्स सरस्वति कमर्शियल ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	—
4. श्री के० एच० चौकसी	18,25,000
5. श्री वी० पी० रूंगटा	—
6. वी० एम० चौकसी एण्ड कप्पनी	37,50,000
7. श्री एन० ग्रार० ग्रग्रवाल	6,65,000

यह सूचना कि कौनसा ऋण, समय पर प्राप्त हुग्रा है, प्राप्य नहीं है ।

(घ) कम्पनी विधि बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 (i) के अन्तर्गत, कम्पनी के निदेशक मंडल में 2 जनवरी, 1973 से 3 वर्ष की अवधि के लिए दो निदेशक नियुक्त किये हैं।

वर्ष 1973-74 के दौरान भाखड़ा कम्पलेक्स से बिजली का उत्पादन

2749. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 के दौरान गोबिंद सागर में जल का स्तर सामान्य था ;

(ख) वर्ष 1973-74 के दौरान भाखड़ा कम्पलेक्स में बिजली का कुल उत्पादन कितना हुआ; और

(ग) इस बिजली का राज्य-वार वितरण तथा उपयोग के आंकड़े क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जून 1973 से मार्च 1974 तक की अवधि के दौरान गोविंद सागर में जल स्तर सामान्य से काफी अधिक रहे।

(ख) अप्रैल 1973 से मार्च 1974 की अवधि के दौरान भाखड़ा कम्पलेक्स में कुल ऊर्जा उत्पादन के लगभग 5800 जो डब्लू एच होने की संभावना है।

(ग) अप्रैल 1973 से फरवरी 1974 तक की अवधि के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का वास्तविक राज्य-वार वितरण और समुपयोजन का विवरण संलग्न है।

विवरण

अप्रैल, 1973 से फरवरी, 1974 तक भाखड़ा कम्पलेक्स ऊर्जा उतादन का राज्यवार वितरण तथा समपयोजन

राज्य	ऊर्जा का विवरण तथा समुपयोजन जी डब्ल्यू एच में
पंजाब	1469.92
हरियाणा	1279.62
राजस्थान	489.59
चण्डीगढ़	123.32
हिमाचल प्रदेश	126.27
नांगल फर्टीलाइजर फैक्ट्री	995.87
दिल्ली	396.56
जम्मू व कश्मीर	65.89
भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड	90.82
उत्तर प्रदेश	135.08
हानियां	189.47
कुल	5362.21

नोट : 1 जी डब्ल्यू एच-1 मिलियन के डब्ल्यू एच

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अमरीकन सर्वेक्षण जहाज की प्राप्ति

2750. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग भारतीय तट दूर क्षेत्रों का गहन भूकम्पीय सर्वेक्षण करने के लिये किसी अमरिकी फर्म से आगामी वर्ष के प्रारम्भ में एक सर्वेक्षण जहाज खरीदेगा ;

(ख) इस जहाज का मूल्य कितना है तथा भुगतान किस रूप में किया जायेगा ; और

(ग) क्या रूस अथवा किसी पूर्व यूरोपीय देश से ऐसा जहाज लेने का कोई प्रयास किया गया था यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पैट्रोलिय और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) पूरे उपकरणों सहित जहाज की कीमत 40,91,476,15 यू० एस० डालर है जिसका भुगतान चरणों में, ठेके की तिथि से जहाज की प्राप्ति के समय तक किया जायेगा। इस कीमत में (i) (सैस्मिक केबिल डेप्थ कंट्रोलर सिस्टम) के पेटेंट (एकस्वकृत) प्राप्त वालों को दी जाने वाली रायल्टी और (ii) एबीएस के प्रमाणीकरण के लिये जहाज के निर्माण के दौरान निरीक्षण हेतु विकल्प के लिये 22,500,00 यू० एस० डालर का प्राक्कलन भुगतान शामिल नहीं होगा।

(ग) जहाज मैसर्स भूकम्पीय अन्वेषण अन्तर्राष्ट्रीय एस ए (यू० एस० ए०) से विश्व भर में टेंडर संबंधी पूछताछ के विरुद्ध आयोग द्वारा प्राप्त न्यूनतम स्वीकार्य टेंडर के आधार पर प्राप्त किया जा रहा है। विश्व भर से टेंडर मंगाए गये थे किन्तु जहाज के लिये किसी पूर्वी यूरोपीय देश से कोई कोटेशन प्राप्त नहीं हुआ था और रूस प्राधिकारियों ने कम से कम 1978 तक अपेक्षित जहाज की पूर्ति के लिये असमर्थता प्रकट की है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों तथा ग्रामीण सहकारी समितियों की स्थापना

2751. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :**

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण में तीव्रता लाने के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों तथा ग्रामीण सहकारी समितियों की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्रों और समितियों की राज्यवार सूची क्या है ; और

(ग) वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा उक्त केन्द्रों तथा सहकारी समितियों को कितना ऋण दिया गया ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पांच ग्राम बिजली सहकारी समिनियां स्थापित की हैं। इन सहकारिताओं का ब्यौरा तथा उनको 1972-73 और 1973-74 के दौरान दिये गये ऋणों की राशियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

निगम ने कोई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित नहीं किया है।

विवरण

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत सहकारी समिति स्कीमों का विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	सहकारी समिति का नाम	1972-73 के दौरान बांटी गई ऋण राशि (लाख रुपये में)	1973-74
1.	गुजरात . .	कोडीनर ग्राम बिजली सहकारी समिति लिमिटेड	20.000	10.000
2.	कर्नाटक .	हुकेरी तालुक ग्राम बिजली सहकारी समिति लि०	15.000	40.000
3.	आंध्र प्रदेश .	सिरसिला ग्राम बिजली सहकारी समिति लि०	55.000	40.370
4.	महाराष्ट्र	मुला प्रवरा ग्राम बिजली सहकारी समिति लि०	5.000	49.120
5.	उत्तर प्रदेश .	सहकारी बिजली सप्लाई समिति लि० लखनऊ	50.558	35.000
		कुल	145.558	174.490

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद तथा नदी बेसिन आयोग की स्थापना

2752. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् तथा नदी बेसिन आयोग की स्थापना करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : देश के सीमित जल संसाधनों की अधिकतम समुपयोजन करने के उद्देश्य से, एक राष्ट्रीय जल नीति का विकास करने जल की आवश्यकताओं और उपलब्ध जल के सम्पूर्ण राष्ट्रीय हितों में विभिन्न उपयोगों के लिये लाभकारी तथा समान आवंटन का लगातार मूल्यांकन करने तथा जल विवादों को शीघ्रता से निपटाने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् के गठन करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। मास्टर योजना तैयार करने तथा जल का सर्वोत्तम उपयोग सुझाने के लिये राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की सहायता के लिये नदी आयोगों का गठन भी प्रस्तावित था। प्रथम कदम के रूप में, संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधनों के लिये राज्यों को सुझाव दिया गया था। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् के गठन तथा इसके अभिकरण के जरिये विवादों के निपटारे के प्रस्तावों का सामान्य रूप से समर्थन किया गया था। जबकि कुछ राज्यों ने संशोधनों के विरोध में विचार प्रकट किये हैं, अधिकांश राज्यों ने यह महसूस किया है कि संशोधनों को केवल अन्तर्राज्यीय नदी जल में विवादों तक ही सीमित रखना चाहिये तथा जल के उपयोग व नियंत्रण के संबंध

में राज्यों की वर्तमान शक्तियां पहले की तरह जारी रहनी चाहिये। राज्य सरकारों द्वारा अभिव्यक्त के प्रकाश में इस मामले का और अध्ययन किया जा रहा है। यह बताना संभव नहीं है कि प्रस्तावों को निश्चित रूप से कब तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों द्वारा डीजल इंजनों का खराब किया जाना

2753. **श्री एस० ए० मरुगन्नतम:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोको कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों ने जिन डिजल इंजनों को चलाया था, उसे उन्होंने खराब कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Proposal to open passenger assistance booth at Ratlam Railway Station

2754. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government propose to open Passenger Assistance Booth at Ratlam Railway station; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :(a) No. However, separate Reservation Booths have been provided on each Broad Gauge platform at Ratlam railway station to assist passengers in getting reserved accommodation in trains.

(b) Does not arise.

Police Raids on Petrol Pumps to Check Adulteration

2755. **Shri Phool Chand Verma:**

Shri Chandra Bhal Mani Tewari:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether the Delhi Police raided several petrol pumps on the 4th February, 1974 to check adulteration of Kerosene oil with petrol;

(b) the action taken against the offenders; and

(c) the number of raids conducted for such checks during the last three years and the number of those against whom action has been taken and the nature of the action taken ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): No such raid on Petrol Pumps was conducted on 4-2-1974.

(b) Does not arise.

(c) During the last 3 years i.e. 1971, 1972 and 1973, one case of adulteration of petrol with solvent oil was registered by the Police at Punjabi Bagh on 14-11-1973 in which two persons were arrested. This case is pending trial in the court.

Opening of Guna-Maksi Railway Line

2756. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the time by which Guna-Maksi Railway line in Madhya Pradesh will be opened to passenger traffic; and

(b) the salient features in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) Two sections of the line, covering a length of 132.21 kms. have been completed. The work on the remaining portion of 61.27 kms. long portion is in progress. The entire line is likely to be completed and opened to passenger traffic sometime in 1975-76, subject to availability of adequate funds.

Oil Drilling in Assam and Arunachal Pradesh

2757. **Shri Phool Chand Verma:**

Shri Lambodar Baliyar:

Will the Ministry of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Government propose to expand drilling operations and production of oil in Assam and Arunachal Pradesh; and

(b) if so, the main features in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes, Sir.

(b) The Oil and Natural Gas Commission has drawn up a programme of work for the Fifth Five Year Plan which includes a large volume of exploration work and intensification of production of crude oil and Natural gas in Assam Arakan Basin. It plans to put in 18 Party years of seismic and 5 Party years of gravity magnetic field surveys, besides geological mapping; to drill 172 exploratory and development wells with a total depth of 0.74 million metres; and to step up the production from the present rate of 0.4 million tonnes per year to 2.57 million tonnes per year by the end of 1978-79.

Oil India Limited has also intensified its exploration operations and has drawn up a seven year programme (1973-79) to meet the growing needs of the country. As a part of this it would be drilling 16 wells in the coming years in Dum Duma area of Assam and Ningru area of Arunachal Pradesh with a total depth of 192,500 ft. (equivalent to about 58,712 metres).

Translation of Constitution of India and Central Laws in Regional Languages

2758. **Shri. M.S. Purty:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have given full liberty to the State Governments in the matter of translation of the Constitution and the Central Laws in their respective regional languages to make them understandable by the common masses; and

(b) if so, the names of the States which have not translated them into their regional languages so far and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) and (b) Translations of the Constitution in various regional languages were initially prepared by the Official Language (Legislative) Commission and sent to the concerned State Governments for comments, if any. After the comments were received, further discussions were held by the Members of the Commission representing the relevant languages, with the concerned State Government officials and the translations have been finalised by the Commission in the light of the decision taken after such discussions.

Translations of Central Acts in regional languages are prepared by the agencies of the State Governments appointed for the purpose and finalised by the Official Language (Legislation) Commission in consultation with the State Governments concerned. The standard legal terminology evolved by the Official Language (Legislative) Commission for use, as far as possible, in all the Indian Languages, is adopted by the State Government agencies in the translations of Central Acts in the regional languages. Where, however, there are expressions in common use in a particular regional language to denote particular legal concepts, which are different from those evolved by the Commission to denote such legal concepts, the expression in common use are adopted in the translations in order to ensure that the translations are understood by the vast majority of the People who use that language.

The Constitution of India has been translated in Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Tamil and Telugu. Action has also been initiated to print these translations. The translation of the Constitution into Urdu has been prepared and is expected to be finalised shortly. The translation of the Constitution in Kashmiri is also under preparation.

The work of translation of Central Acts in the regional languages, except Kannada and Kashmiri, is proceeding satisfactorily. The Governments of Karnataka and Jammu & Kashmir have been requested to make the necessary arrangements for the translation of Central Acts in Kannada and Kashmiri respectively.

Every effort is made to make the translations as simply and precise as possible.

इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा दूसरा उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की संभाव्यता

2759. **श्री रामसहाय पांडे :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड को ईंधन अथवा तेल कोयला गैसिकरण प्रक्रिया पर आधारित दूसरा उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की संभावना की जांच करने के लिये कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या संभाव्यता प्रतिवेदन पेश किया जा चुका है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) कुछ समय पहले इंडियन एक्सप्लोसिव लि० ने उपयुक्त स्थान पर सामग्री के रूप में ईंधन तेल तथा कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने में रुचि दिखाई थी। कम्पनी को सलाह दी गई थी कि सरकार के विचार के लिये अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत करें। इस संबंध में औपचारिक प्रस्ताव अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

कम्पनी अधिनियम, 1956 में परिवर्तन करने सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

'2760. **श्री बसन्त साठे :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 में कुछ परिवर्तन करने के लिये इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकान्टेंट्स आफ इंडिया ने सरकार से विशेषज्ञ समिति गठित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) हां श्रीमान् जी। इंस्टीट्यूट ने कम्पनियों से अपेक्षित बहुत से वित्तीय विवरण-पत्रों के प्रगट करने की संरचना, विषय सूची और रूप के संबंध में, परिवर्तन की आवश्यकता के विशेष संदर्भ में सम्पूर्ण, "निगमित विधान" की विस्तृत और व्यापक संवीक्षा सम्पन्न करने के लिये विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति का सुझाव दिया है। इंस्टीट्यूट का सुझाव अंकित कर लिया गया है।

रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एसोसियेशन, उत्तर रेलवे द्वारा वेतनमानों में समानता की मांग

2761. **श्री बसन्त साठे :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एसोसिएशन ने औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल जैसे केन्द्रीय सुरक्षा बलों के वेतन मानों को समान करने की मांग की हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग पर क्या विचार किया जा रहा है; और

(ग) इस मामले में, यदि कोई निर्णय किया गया है, तो क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने मोटे तौर पर केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनमानों के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। आयोग ने रेलवे सुरक्षा दल की ओर से आयोग को दिये गए अभ्यावेदनों सहित सभी संबंधित तथ्यों पर विचार करने के बाद इस दल के कर्मचारियों के लिये सुधरे हुए वेतनमानों की सिफारिश की है। इस समय इन सिफारिशों पर कार्यवाई की जा रही है।

तेल की सप्लाई न होने के कारण महाराष्ट्र की छोटी कागज मिलों का बन्द होना

2762. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ईंधन तेल सप्लाई न होने के कारण महाराष्ट्र में छोटी कागज मिलें या तो बन्द हो गयी हैं अथवा उनके बन्द होने का खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) कागज की अत्याधिक कमी को ध्यान में रखते हुये कागज मिलों को बन्द होने से बचाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) इस समय तेल कम्पनियां समस्त उद्योगों के, विगत माल उठाने के आधार पर, 90% आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। आशा की जाती है कि भट्टी के तेल के प्रयोग में मितव्ययता अपनाने तथा उत्पादन पर प्रभाव डाले बिना उन्नत दक्षता द्वारा 10% की बचत की जा सकती है। भट्टी के तेल की सप्लाई को इस रूप में कि इससे औद्योगिक उत्पादन में अवरोध उत्पन्न न हो विनियमित करने के लिये तकनीकी विकास के महा-निदेशक तथा सचिव की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति की स्थापना की गई है।

केरल में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

2763. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने पर विचार करेगी;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार को कोट्टयम ज़िला विकास परिषद् से कोई ज्ञापन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) सरकार ने पहले से ही सरकारी क्षेत्र में पांच नई उर्वरक प्रायोजनाओं की स्थापना करने के लिये सैद्धांतिक रूप से मान लिया है। इन्हें मथुरा, पानीपत, भटिन्डा ,पारादीप और ट्राम्बे में लगाने का प्रस्ताव किया गया है। केरल समेत अन्य उचित स्थानों पर अतिरिक्त क्षमता की स्थापना करने के प्रश्न पर साधनों की स्थिति और अन्य संबद्ध तथ्यों के संदर्भ में उचित समय पर पुनर्विचार किया जायेगा।

(ख) सरकार को इस प्रकार के किसी ज्ञापन की जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कन्नानूर (दक्षिण रेलवे) के निकट एझीमाला पर हाल्टिंग प्वाइंट को समाप्त करना

2764. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में कन्नानूर के निकट एझीमाला स्टेशन पर यात्री गाड़ी संख्या 515, 516 तथा 62 का हाल्टिंग प्वाइंट हाल ही में समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार एझीमाला स्टेशन पर फिर से हाल्टिंग प्वाइंट बनाने हेतु कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) नं० 515 डाउन/516 अप कालीकट-मेंगलूर तथा 62 अप कासरगोड-शेरुवण्णूर सवारी गाड़ियों को अभी भी एलिमला में ठहराया जाना निश्चित है। लेकिन कोयले की कमी के कारण ये गाड़ियां फिलहाल अस्थायी तौर पर रद्द की हुई हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नायलान धागा बनाने वाली परियोजनाओं की स्थापना

2766. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नायलान धागा बनाने वाली जिन परियोजनाओं को आशय पत्र और लाइसेंस जारी किये गए हैं, क्या सरकार ने उनमें से कुछ की स्थापना की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किये गए निर्णय की मोटी रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या सरकार चित्तूर जिले में औद्योगिक रूप से पिछड़े तिरुपति की प्रस्तावित परियोजना पर विशेष रूप से विचार करेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) विभिन्न संबंधित तथ्यों को मध्यनज़र रखते हुये कुछ महत्वपूर्ण कार्यों जैसे देश में नायलोन धागे के सम्पूर्ण विकास तथा नायलोन संयंत्रों के विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात की आवश्यकताओं की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

फारेन ट्रेफिक एकाउन्टस आफिस, दिल्ली (पश्चिम रेलवे) में काम करने वाले कर्मचारियों को पास सुविधा

2767. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे दिल्ली में काम कर रहे अपने कर्मचारियों को मुख्यालय से होकर गुज़रने के लिये पास (पास क्रोसिंग एच० क्यू०) जारी कर रही है जबकि पश्चिम रेलवे यही सुविधा फारेन ट्रेफिक एकाउन्टस आफिस, दिल्ली के कर्मचारियों को नहीं दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस विषमता को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) यह सच है कि उत्तर रेलवे द्वारा अपने दिल्ली स्थित कर्मचारियों को मुख्यालय पारगमन पास जारी किये जा रहे हैं। इस तरह के पास पश्चिम रेलवे द्वारा भी अपने कर्मचारियों को दिये जाते हैं बशर्ते पास मांगते समय संबंधित कर्मचारी तर्कसंगत स्पष्टीकरण दे सकें कि वह क्यों ऐसा पास लेना चाहता है।

उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा पांडेचूरी के लिये स्वीकृत विद्युत परियोजनायें

2768 **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर 1973 से फरवरी, 1974 के दौरान उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा पांडेचेरी संघ शासित क्षेत्र में किन्हीं विद्युत् परियोजनाओं को स्थगित करने का बचन दिया गया था उन्हें शुरू किया गया था अथवा उनका शिलान्यास किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार व्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और ये परियोजनाएं कब तक चालू हो जायेंगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है। ये सभी परियोजनाएं योजना आयोग द्वारा स्वीकृत और पांचवीं पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित हो चुकी है।

विवरण

राज्य	विद्युत् परियोजना	जिस तारिख को शिलान्यास रखा गया अथवा कार्य का उद्घाटन किया गया।	अनुमानित लागत लाख रुपयों में	जिस समय तक परियोजना के चालू होने को संभावना है
उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज ताप विद्युत् केन्द्र विस्तार चरण 5, 110 मैगावाट	10-1-1974	1929	1976-77
	हरदुआगंज ताप विद्युत् केन्द्र विस्तार चरण-6, 110 मैगावाट	10-1-1974	2259	1976-77
	ओब्रा ताप विद्युत् केन्द्र विस्तार चरण-दो 600 मैगावाट	16-1-1974	8989	1976-77
	ओब्रा ताप विद्युत् केन्द्र विस्तार चरण-तीन, 400 मैगावाट	16-1-1974	6800	1976-77
	नरोरा परमाणु विद्युत् केन्द्र 470 मैगावाट	13-1-1974	20990	1981-82
उड़ीसा	रेंगली बहुद्देश्यीय परियोजना चरण-एक 2× 50 मैगावाट	23-12-1973	5792.68	**
पांडिचेरी	कुछ नहीं			

**बांध और आनुषंगिक कार्यों का पांचवीं योजना के अन्त तक और विद्युत् यूनिटों की छटी योजना के प्रथम वर्ष तक चालू करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

रेलवे में कोयला वैगनों की कमी

2769. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उत्पादकों और प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए रेलवे के पास कोयला वेगनों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) कोयला ढुलाई के लिए माल डिब्बों की कमी जैसी कोई बात नहीं है। मालडिब्बों की उपलब्धता पर जब-तब बिजली में कटौती और जन-आन्दोलन, आकस्मिक हड़तालें "धीरे काम करो" आन्दोलन; राजनीति प्रेरित बंध, रेलपथ पर धरना देकर गाड़ियों के आवागमन को रोकना, लाइन की टूट-फूट आदि असंगत कारणों का प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप कोयला उत्पादन और उसका परिवहन दोनों प्रभावित हुए।

(ग) संचलन की सामान्य स्थिति में रेलों को कोयला-ढुलई की मांगें पूरी करने में किसी प्रकार की दिक्कत न होगी।

Complaints made by Food Inspectors against food stuff vendors at Stations on Bikaner and Jodhpur Divisions (Northern Railway)

2770. **Shri Panna Lal Barupal:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the number of foodstuff vendors of various railway stations on Bikaner and Jodhpur Divisions of Northern Railway who have been fined and the number of those the validity period of whose licences have been curtailed and the number of such licence holders who have been awarded both the penalties concurrently on the complaints made by the Food Inspectors ;

(b) whether the passengers who purchased and eat foodstuff sold by them have made any complaints against the vendors; and

(c) if not, the reasons for which the vendors have been punished just on Food Inspectors' complaints ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) (i) The number of foodstuff vendors at various stations on Bikaner and Jodhpur Division of Northern Railway who have been fined in respect of Food Adulteration is 8.

(ii) The number of those, the validity period of whose licences has been cutailed is 3.

(iii) The number of those who have been awarded both penalties under (i) and (ii) above concurrently is 3.

(b) Yes.

(c) Vendors have been punished not merely on the Food Inspector's report but on the basis of declaration by the Public Analysts that samples of food were adulterated.

चौथी और पांचवीं योजनाओं में औषध उत्पादन का लक्ष्य

2771. **श्री एम० एस० संजीवीराव : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र के कारखाने में औषधियों के उत्पादन का लक्ष्य क्या है; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था और क्या उसे प्राप्त कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में वर्ष 1978-79 तक प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपये के मूल्य के सूत्रयोगों की कुल बिक्री की परिकल्पना है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान सूत्रयोगों का मूल्य लगभग 370 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है।

(ख) चौथी योजना के लिए औषधों के उत्पादन का लक्ष्य 250 करोड़ रुपये का था जो लक्ष्य से आगे बढ़ गया है।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं द्वारा अर्जित लाभ/हानि

2772. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मुख्य तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं से, राज्यवार कुल कितनी हानि हुई, और

(ख) हानि और लाभ के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सिंचाई परियोजनाओं की अभिकल्पना कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये की जाती है तथा ऐसी परियोजनाओं के आर्थिक पहलूओं का मूल्यांकन, लाभ-लागत अनुपात के आधार पर किया जाता है। सामान्यतः आरम्भ की गई सभी परियोजनाओं के लागत-लाभ अनुपात अनुकूल रहे हैं। बहरहाल, राज्य सरकारों द्वारा ली जाने वाली कम जल-दरों, परियोजनाओं के निर्माण तथा अनुरक्षण की बढ़ती हुई लागतों तथा निर्मित्त शक्यता के न्यून समुपयोजन के कारण सरकार को प्राप्त राजस्व व्यय से लगातार कम होता गया है और इसी संदर्भ में ही सरकारी राजस्व को हानि हुई है। सिंचाई परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ यह हानि बढ़ती गई तथा 1967-68 में यह हानि 565.9 करोड़ रुपये थी। राज्यवार ब्यौरा उपाबन्ध में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6397/74]

Converstion of Express Train Running between Bilaspur and Katni-Bina into a Passenger Train

2773. **Shri Lambodar Baliyar:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for which the express train running between Bilaspur and Katni-Bina has been converted into a passenger train; and

(b) whether Government are aware that people are facing great difficulties as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b): 35 Dn/36Up Bhopal-Bilaspur Express-cum-Passengers trains have been converted into passenger trains on Katni-Bina section with effect from 1-11-1973 with a view to providing a day time passenger train for the convenience of passengers on the Katni-Bina Section.

काम के घंटों के समायोजन द्वारा ईंधन तथा विद्युत् की बचत

2674. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**

श्री पी० एम० मेहता :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गर्मी तथा सर्दी में काम के घण्टों के समायोजन द्वारा ईंधन और विद्युत् में बचत की संभावना की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किये गए हैं।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। ग्रीष्म तथा शीन ऋतु में देश में कार्य समय का समुचित रूप से समंजन करके ईंधन तथा विद्युत् में बचत करने की संभावना की जांच की जा चुकी है। कारखानों तथा अन्य संस्थानों के कार्य-समय का समंजन और भारों के पुनर्स्थापिन से पीक विद्युत् आवश्यकताओं में बचत पर प्रभाव पड़ा है। बहरहाल, ग्रीष्म और शीत ऋतु में कार्य-समय के समंजन से कोई महत्वपूर्ण बचत संभव नहीं है।

धर्मनगर से अगरतला तक रेल लाइन का निर्माण

2775. **श्री दशरथ देव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में धर्मनगर से अगरतला तक रेल लाइन के निर्माण में सर्वेक्षण की प्रगति क्या है;

(ख) क्या इस कार्य को शीघ्र आरम्भ करने के लिये सरकार ने कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) धर्मनगर अगरतला मीटर लाइन के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं और रिपोर्टें विचाराधीन हैं। लेकिन धर्मनगर से कुमारघाट तक एक नयी मीटर लाइन बनाने का विनिश्चय किया गया है। उत्तर पूर्व परिषद् से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये उसको दिये गए धन में से इसका खर्च वहन करने का अनुरोध किया गया है। कुमारघाट से अगरतला तक के शेष भाग को पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में किसी समय हाथ में लिया जायेगा बशर्ते कि धन के अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध हों।

मतदान की आयु में कमी करना

2776. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का एक प्रतिनिधिमण्डल मतदान की आयु में कमी करने की अपनी मांग पर जोर देने के लिये भारत के राष्ट्रपति से मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तुत प्रश्न की विषय-वस्तु, अर्थात् मतदान की आयु में कमी करना पहले से ही सरकार के विचाराधीन है और उस पर अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

12LSS/74—9

मिट्टी के तेल की बिक्री सम्बन्धी घोटाले का पता लगाना

2777. **श्री यमना प्रसाद मण्डल :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1974 में दिल्ली में मिट्टी के तेल की बिक्री संबंधी किसी घोटाले का पता लगा था; और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि शाहदरा पुलिस द्वारा एक आदमी मिट्टी के तेल को चोर बाजार में बेचते हुये दिनांक 30 जनवरी, 1974 को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 850 लिटर मिट्टी का तेल पकड़ा गया था। इस मामले की जांच की जा रही है।

नेफ्था पर आधारित उर्वरकों के सम्बन्ध में भारत द्वारा अमरीका का सहयोग प्राप्त किया जाना

2778. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नेफ्था पर आधारित उर्वरकों के स्थान पर कोयले पर आधारित उर्वरकों का उत्पादन के लिये अमरीका से प्रौद्योगिकी सहयोग देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गैर सरकारी क्षेत्रों द्वारा बिजली घरों की स्थापना

2779. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :**

श्री ई० वी० विखे पाटिल :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुए गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को अपने बिजली घर बनाने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने गैर सरकारी कारखानों के आवेदन बकाया पड़े हैं; और

(ग) उन्हें अनुमति में विलम्ब देने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) विद्युत् उत्पादन तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए संयुक्त रूप से वाष्प का समुपयोजन करके अथवा उपोत्पाद ईंधन या ऊष्मा के उपयोग से, कुल ऊर्जा कन्सेष्ट को अपना कर जहां ईंधन में पर्याप्त किफायत संभव है, केवल ऐसे असाधार-मामलों में ही निजी क्षेत्र में उपक्रमों को स्वयं अपने कैप्टिव विद्युत् संयंत्रों को प्रतिष्ठापित करने की अनुमति दी जा रही है। केप्टिव विद्युत् संयंत्र की स्थापना के ऐसे प्रत्येक मामले पर उसकी अपनी विशेषताओं के आधार पर विचार किया जाता है।

कैप्टिव विद्युत् जनन संयंत्रों के प्रतिष्ठापन के लिए अभी हाल में प्राप्त इस प्रकार के चार आवेदन पत्रों पर इस मंत्रालय में कार्यवाही की जा रही है।

पानीहाटी क्षेत्र और सियालदह क्षेत्र में रेलवे भूमि का बेघर लोगों में वितरण

2780. **श्री समर गुह** : क्या रेलमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कई आवेदनों सहित पश्चिम बंगाल में 24 परगना के पानीहाटी क्षेत्र में रेलवे की बेकार भूमि के बेघर लोगों में घर बनाने के लिये ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह रेलवे भूमि 50 वर्ष से बेकार पड़ी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस भूमि को बेघर लोगों में वितरण के लिये काम में लायेगी और

(घ) क्या पूर्वी रेलवे के सियालदह क्षेत्र प्राधिकारी को भी इसी प्रकार के आवेदन दिये गये हैं और यदि हां, तो सरकार ने बेकार रेलवे भूमि के वितरण के लिए क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) भूमि मुक्ति आंन्दोलन समिति, सुभाषनगर, डाकघर सुक्चर, ज़िला 24-परगना, पश्चिमी बंगाल से एक अभ्यावेदन और 24-परगना ज़िला के खारदह क्षेत्र के भूमिहीन लोगों से बड़ी संख्या में याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। यह भूमि एक परिव्यक्त ईंट-भट्ठे की भूमि है जिसका उपयोग इस समय रेलवे द्वारा रेल पथ डिपो के रूप में किया जा रहा ह । भूमिहीन लोंगो मैं इस भूमि को बांटने का प्रश्न नहीं उठता ।

तेल की खोज का विस्तार तथा उसके लिये सोवियत सहायता

2781. **श्री समर गुह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने देश में नये तेल क्षेत्रों की खोज तेज करने के लिये विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उस बारे में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने सोवियत संघ के साथ इस बारे में कोई करार किया है;

(घ) यदि हां, तो उनकी शर्तें आदि क्या हैं;

(ङ) तेल की खोज के बारे में पहले से हाथ में ली गई योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

(च) अब तक निकले परिणाम अथवा निकट भविष्य की सम्भावनाऐं क्या हैं; और

(छ) देश के भीतर, तटीय क्षेत्रों में या तट-दूर क्षेत्रों में तेल के सम्भावी क्षेत्रों का विवरण क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पांचवी पंच वर्षीय योजना के लिए कार्यों की जो योजना बनाई है उसमें भूमि तथा महाद्वीपी कगार क्षेत्रों में एक बड़ी मात्रा में अन्वेषण कार्य करने की परिकल्पना है। इस योजना के अनुसार आयोग का वर्ष 1978–79 तक वर्तमान 4.11 मिलियन टन प्रतिवर्ष तेल के उत्पादन को 9.00 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने की आशा है । इसमें आयल इंडिया लि० तथा असम आयल कम्पनी के लगभग 3 मिलियन टन प्रति वर्ष के उत्पादन को सम्मिलित करते हुए वर्ष, 1978–79 तक 12 मिलियन टन प्रति वर्ष का कुल देशीय उत्पादन होने की आशा है।

(ग) और (घ) : भारत के सरकारी क्षेत्र में तेल-अन्वेषण, विकास एवं उत्पादन कार्य हेतु रूस का बराबर सहयोग रहा है तथा हाल के समझौते के अनुसार रूस ने, उपकरणों, मशीनों अतिरिक्त पुर्जे और सामान की सप्लाई तथा तकनीकी सहायतार्थ रूसी विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध करने और रूस में भारतीय विशेषज्ञों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने हेतु लपने सहयोग में और तीव्रता लाने के बारे में अपनी सहमति व्यक्त की है।

(ङ) से (छ) : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने देश का लगभग सभी भूमि पर जहां पर आशापूर्ण तलछटी घाटियां विद्यमान है तथा अनेक महाद्वीपी क्षेत्रों में अन्वेषी सर्वेक्षण कार्य, आरम्भ कर दिया है। परिणाम स्वरूप बहुत सी संभाव्य हाईड्रोकार्बन-युक्त संरचनायें छांटी गई है। परिक्षण के बाद 25 संरचनाएं तेल-युक्त तथा 6 संरचनाऐं गैस-युक्त पाई गई हैं। इन क्षेत्रों में उत्पादन से पहले 108.66 मिलियन टन कच्चा तेल तथा लगभग 25,000 मिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस के कुल प्राप्य भंडार थे। आयोग ने वर्ष 1973 के अन्त तक कुल 30.24 मिलियन टन खनिज तेल का उत्पादन और 2,642.17 मिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस का विक्रय किया । पांचवी पंच वर्षीय योजना की अवधि के अन्तर्गत आयोग के कुल 34.12 मिलियन टन खनिज तेल उत्पादन करने की आशा है।

अपतटीय क्षेत्रों में इस समय बम्बई हाई संरचना पर, जहां पर तेल प्राप्त होने के संकेत मिले हैं, व्यघन-कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय महाद्वीपी कगार क्षेत्रों के तेल अन्वेषण कार्य को बढ़ाने के लिए, कुछ विदेशी पार्टियों के साथ विचार-विमर्श प्रगति पर है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा समुद्री भू-भौतिकी सर्वेक्षण कार्य हेतु अमेरिका को एक भूकंपीय जहाज सप्लाई करने के लिए आर्डर दे दिया गया है।

ज्वाइंट स्टाक' कम्पनियों और उनकी प्रदत्त पूंजी

2782. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी 'ज्वाइंट स्टाक' कम्पनियां कितनी हैं और वर्ष 1973 के अन्त तक उनकी प्रदत्त पूंजी की कुल राशि कितनी थी; और

(ख) वर्ष 1973 के अन्त में बड़े औद्योगिक गृहों ने सरकारी उपक्रमों में प्रदत्त पूंजी की कुल कितनी राशि लगाई हुई थी?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) 31-3-1973 तक, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, पंजीकृत शेयर द्वारा लिमिटेड, 5345.1 करोड़ रु० की कुल प्रदत्त पूंजी से युक्त 34873 कम्पनियां थी। इनमें से, 6841 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां और 28032 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां थीं। उनकी प्रदत्त पूंजी क्रमशः 2059.0 करोड़ रुपये और 3286.1 करोड़ रुपये थी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों के कार्यकरण को विनियमित करने का प्रस्ताव

2783. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों के कार्यकरण को विनियमित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : सरकार ने 1973 में औद्योगिक नीति का पुनरीक्षण किया है और इसके परिणामस्वरूप औषध एवं भेषज उद्योग को उद्योगों की उस सूची में शामिल किया गया है जिन में विदेशी फर्में तथा विदेशी कम्पनियों की सहायक फर्में एवं शाखाएं सहभागिता की हकदार हैं। उनके निवेश संबंधी आवेदन-पत्रों पर विदेशी साम्य पूंजी में कमी किये जाने के निर्देश-चिन्हों के अनुसार विचार किया जायेगा और तकनीकी पहलुओं निर्यात संभाव्यताओं आदि के संदर्भ में उनकी जांच की जाएगी इस बात को सुनिश्चित करने के लिये, कि इस प्रकार की मदें विदेशों से, जिन में संस्थाएं शामिल हैं, ऊंचे दामों पर न खरीदी जाए, औषधियों तथा मध्यवर्ती पदार्थों का आयात बड़े पैमाने पर राज्य व्यापार निगम की मार्फत सरणीबद्ध किये जाने से नियमित किया जाता है। बड़े बड़े यूनिटों की तुलना में एक करोड़ रुपये से कम की बिक्री करने वाली छोटी कम्पनियों को अधिक कच्चे माल के आयात करने की इजाजत दी जाती है। इस उपाय से छोटे पैमाने के क्षेत्र स्थापित किये जाने में सहायता मिलेगी। सूत्रयोगों के निर्माण के लिये औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किये जाने के लिये विदेशी कम्पनियों के आवेदन पत्र, जब तक कि उन में प्रपज औषधियों के उत्पादन के प्रस्ताव न हों सामान्य रूप से स्वीकार नहीं किये जाने प्रपुज औषधों के उत्पादन के काफी भाग को अ-सम्मिलित निर्माताओं को सप्लाई करने के लिये भी सामान्य रूप से उन्हें बाध्य किया जाता है इस से भी भारतीय क्षेत्र की वृद्धि किये जाने में सहायता मिलेगी।

कोसी परियोजना की अनुमानित लागत में संशोधन

2784. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी परियोजना पर मूलतः कितनी लागत का अनुमान लगाया गया था; और

(ख) अनुमानित लागत को कितनी बार संशोधित किया गया, अन्तिम रूप से लागत का क्या अनुमान है तथा परियोजना को लागत में संशोधन के क्या कारण थे।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) आरम्भ में कोसी परियोजना की अनुमानित लागत 44.76 करोड़ रुपये थी।

(ख) राज्य सरकार ने प्राक्कलन में चार बार वृद्धि करने का प्रस्ताव किया था परन्तु अभी तक कोई संशोधित प्राक्कलन स्वीकृत नहीं किए गए हैं।

अद्यतन संशोधित प्राक्कलन (1972) 111.64 करोड़ रुपये है। परियोजना की अनुमानित लागत में संशोधन के मुख्य कारण ये हैं :

1. इस अवधि में सामग्रियों, भूमि की लागत एवं मजदूरी में सामान्य वृद्धि ;
2. एक क्यूसेक तक जल-मार्गों का निर्माण;
3. मुख्य नहर से अतिरिक्त शाखाएं;
4. बाढ़ सुरक्षा और कटाव-रोधी उपायों पर अतिरिक्त व्यय;
5. अतिरिक्त पुलों का निर्माण; और
6. गाद निष्कासक और सिल्टिंग वेसिन का निर्माण।

Extention of Raipur-Rajim-Dhantari (Madhya Pradesh) Narrow Gauge Line

2785. **Shri Shri krishna Agrawal:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a survey for the extension of Raipur-Rajim-Dhantari (Madhya Pradesh) narrow gauge line on South Eastern Railway has been made and Government have given their approval for it;

(b) whether construction work has not been started there ; and

(c) if so, the reasons therefor and the steps being taken to start the work?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to c) Based on the recommendations of the Uneconomic Branch Lines Committee, a traffice survey for conversion of Raipur-Rajim-Dhantari N.G. section into B.G. was carried out and the report is under examination. A decision regarding conversion of this line will be taken after the report is examined and the results thereof become known. However, there is no proposal for the extension of Raipur-Rajim-Dhantari Narrow Gauge Line.

Passenger and Goods Train Services in Chhatisgarh Area (Madhya Pradesh)

2786. **Shri Shri krishna Agrawal:** Will the Minister of **Railways** be pleased to State :

(a) whether no passenger and goods train service except for transportation of pig iron which is exported to Japan, is available on raillive in Chhat isgarh (Madhya Pradesh) area on South Eastern Railway;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to introduce passenger and goods train services on this line keeping in view the backwardness of this region; and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) There are at present no passenger services on Kottavalasa-Kirandul section of South Eastern Railway.

(b) & (c) A proposal to introduce a mixed Passenger-cum-goods train on this line is currently under examination and action as feasible shall accordingly be taken.

एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालयों में ले जाये गये मामले

2787. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 से एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालयों में कितने मामले ले जाये गये और कितने मामले अन्तिम रूप से निबटाये गये;

(ख) कितने मामलों में फैसला अन्तिम रूप से सरकार के विरुद्ध हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों और इस अधिनियम के प्रवर्तन की अवधि के दौरान हुये अन्य अनुभावों को ध्यान में रखते हुये अब तक ध्यान में आई कमियों को इस अधिनियम में संशोधन करके दूर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो संशोधी विधेयक संसद् में कब तक लाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) : न्यायालय को ले जाये गये 14 मामलों में से दो मामले आवेदक कम्पनियों द्वारा वापस ले लिये गये थे और तीन मामलों का सरकार के पक्ष में निर्णय हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय में अनिर्णीत 6 मामलों में से तीन कम्पनियों द्वारा और तीन सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। तीन मामलों में, आयोग के ही विरुद्ध कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत अपीलों में से, एक का पक्ष में निर्णय हुआ और दो रद्द कर दी गई थीं।

(ग) तथा (घ) : एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के कार्यकरण की सरकार सतत संवीक्षा कर रही है। एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के संशोधन किये जाने का प्रश्न, उसके कार्यकरण से कमियों को दूर करने की दृष्टि से, सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है। उच्चन्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विषय में दी गई न्यायिक अधिघोषणाओं पर इस अधिनियम में संशोधनों को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व ध्यान में रखा जाएगा।

चौथी योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश को मुख्य सिंचाई सुविधायें

2788. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी योजना में हिमाचल प्रदेश में मुख्य सिंचाई सुविधाओं का लक्ष्य कहां तक प्राप्त हुआ है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : चौथी योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में बृहत/मध्यम सिंचाई क्षेत्र में कोई भी परियोजना कार्यान्वयनर्थ प्रस्तावित नहीं की गई थी।

कटिहार (बिहार) में रेलवे गोदामों से सामान की चोरी

2789. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार (बिहार) में रेल गोदामों से बड़े पैमाने पर सामान की चोरी होती रहती है ;

(ख) क्या मोहर तोड़ने वाले और समाज विरोधी तत्व बेरोक टोक रेलवे के माल गोदाम तक चले जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1972–73 में कितनी हानि होने का अनुमान है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) यह सच नहीं है कि कि कटिहार में चोरी और उठाईगीरी बहुत अधिक होती है लेकिन यार्ड के बहुत बड़े और कई स्थानों पर खुला होने के कारण बुक किये हुए परेषणों के साथ आपराधिक छेड़छाड़ के कुछ मामले वहां हुए हैं।

(ग) कटिहार में चोरी और उठाईगीरी के कारण 1972–73 के दौरान अनुमानतः 19,746 रु० के माल का नुकसान हुआ।

कटिहार में माल की चोरी एवं उठाईगीरी की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) यार्ड और माल गोदाम पर रेलवे सुरक्षा दल द्वारा दिन रात पहरा दिया जाता है।

(ii) यार्ड और माल गोदाम के भेद्य खण्डों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों और कुत्ता दस्तों के गश्त को तेज कर दिया गया है।

(iii) अपराधियों और चोरी की सम्पत्ति लेने वालों को पकड़ने में पुलिस और रेलवे यूनियनों से सहायता और सहयोग प्राप्त किया जाता है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में हिमाचल प्रदेश को सिंचाई सुविधायें देने का लक्ष्य

2790. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को सिंचाई सुविधाएं देने के लक्ष्य को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक की क्षमता कितनी होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजना का कार्यान्वियन राज्य सरकारों द्वारा अपनी-अपनी विकासात्मक योजनाओं के भाग के रूप में किया जाता है। 1974-75 के लिए हिमाचल प्रदेश की वार्षिक योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन का लक्ष्य

2791. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में चौथी योजना में बिजली उत्पादन का लक्ष्य-पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो कितनी कमी रही तथा इस के क्या कारण हैं; और

(ग) लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). आशा है कि चौथी योजना के अन्त में 109.3 मेगावाट विद्युत् जनन क्षमता के लक्ष्य के प्रति यह 1973–74 के अन्त तक केवल 48.3 मेगावाट ही चालू की जाएगी। सिविल कार्यों में विलम्ब हो जाने के कारण गिरि बाटा जल-विद्युत् केन्द्र में (2× 30 मेगावाट) 60 मेगावाट क्षमता की चौथी योजना अवधि में चालू करना संभव नहीं होगा : संयंत्र में कुछ खराबियां होने के कारण नोगली जल-विद्युत् परियोजना में एक मेगावाट (2× 0.5 मेगावाट) को चालू करने में भी विलम्ब हो गया है । इन परियोजनाओं पर राज्य प्राधिकारियों द्वारा कार्य में शीघ्रता लाई जा रही है।

पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में हिमाचल प्रदेश के लिये रेलवे सुविधाओं के बारे में अन्तिम निर्णय

2792. **श्री वीरभद्र सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष हिमाचल प्रदेश को दी जाने वाली रेल सुविधाओं सम्बन्धी लक्ष्य अन्तिम रूप से निर्धारित कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस की रूपरेखा क्या है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) अभी तक नहीं लेकिन प्रस्तावों पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चौथी योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में रेल सुविधा सम्बन्धी लक्ष्य

2793. **श्री वीरभद्र सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी योजना में हिमाचल प्रदेश के लिये निर्धारित रेल सम्बन्धी लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो गए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो लक्ष्य की प्राप्ति में कितनी कमी रही है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) : सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय चौथी योजना में हिमाचल प्रदेश में नयी रेल लाइनों के निर्माण से है। चौथी योजनावधि में हिमाचल प्रदेश में किसी नयी लाइन के निर्माण को अनुमोदन नहीं किया गया है। अतः लक्ष्य प्राप्ति में किसी प्रकार की कमी का प्रश्न नहीं उठता।

मोदी, जे० के० मोहन मीकेन, मफत लाल और भारत टयब (रौनक सिंह) औद्योगिक समूह

2794. **श्री मधु लिमये**: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोदी, जे० के०, मोहन मीकेन, मफत लाल और भारत ट्यूब (रौनक सिंह) औद्योगिक समूह 1969 से तेजी से समृद्धशाली होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत चार वर्षों में उनके कुल परिसम्पत्तियां और बिक्री में कितनी वृद्धि हुई हैं; और

(ग) इन समूहों को 1969 से 1973 तक कितने औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र दिये गये हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ): (क) तथा (ख) फरवरी, 1973 की परिशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति के अनुसार एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत केवल पंजीकृत उपक्रम अर्थात्—

(1) वे उपक्रम जो स्वयं या अपने अन्तः सम्बन्धित उपक्रमों सहित 20 करोड़ रुपयों की अपेक्षा कम नहीं की परिसम्पत्ति रखते हैं और इसके द्वारा धारा 20(क) के उपबन्धों को आकर्षित कर रहे हैं, या

(2) वे उपक्रम जो स्वयं या अपने अन्तः सम्बन्धित उपक्रमों सहित 1 करोड़ रुपयों की अपेक्षा कम नहीं की परिसम्पत्ति रखते हैं और इसके द्वारा एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 20(ख) के उपबन्धों को प्रभावित कर रहे हैं, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अध्याय 3 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस नीति और विनियम के उद्देश्य हेतु बड़े औद्योगिक गृह के रूप में समझे जाते हैं। अतः प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) में यथा अपेक्षित सूचना, उसमें विशिष्ट नामों के समूह की शर्तों में देना सम्भव नहीं है। आगे एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत वार्षिक बिक्री परिसम्पत्तियों में परिवर्तन आदि के विषय में सूचना देना अपेक्षित नहीं है।

(ग) इन कम्पनियों से सम्बन्धित उपक्रमों जो भूतपूर्व औद्योगिक लाइसेंस जांच समिति द्वारा प्रश्न में उल्लिखित विशिष्ट समूह के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये गये थे और जो एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये हैं, को दिये गये औद्योगिक लाइसेंस /आशय-पत्रों की संख्या निम्नांकित है :--

वर्ष	मोदी समूह		जे० के० समूह		मफ्त लाल समूह	
	ला०	आशयपत्र	ला०	आ० पत्र	ला०	आ० पत्र
1970	1	—	1	1	1	3
1971	1	3	8	2	5	1
1972	4	6	3	5	4	4
1973	1	4	6	3	2	2

1969 के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। मोहन मीकिन ब्रेवरीज् लिमिटेड ने, भी जो एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रम है, 1973 में 2 लाइसेंस प्राप्त किये थे ।

श्री सिंथेटिक्स को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिये आशय पत्र का जारी किया जाना

2795. **श्री मधु लिमये** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री सिंथेटिक्स की नायलोन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 2,100 टन प्रति वर्ष करने के लिये आशय-पत्र दिया गया है;

(ख) क्या कम्पनी को अपनी फैक्टरी के लिये विद्युत उत्पादन हेतु डीज़ल जनरेटर आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की इस कम्पनी तथा अन्य कम्पनियों को मैसूर, मद्रास, पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा स्थापित की जाने वाली संयुक्त क्षेत्र की प्रस्तावित परियोजनाओं की उपेक्षा कर के विस्तार करने की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो बांगर ग्रुप और अन्य एकाधिकार गृहों से सम्बन्धित कम्पनियों के विस्तार सम्बन्धी आवेदन पत्र मंज़ूर कर लिये जाने के क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्तमान संयंत्रों के उत्पादन को प्रति दिन 12 मीटरी टन लाने के सरकारी निर्णय के आधार पर गैर-सरकारी क्षेत्र में विस्तार हेतु आशय पत्र जारी किये गये थे। तदनुसार वर्तमान एककों जिन्होंने पहले ही पर्याप्त रूप में लाइसेंसीकृत क्षमता को कार्यान्वित किया था तथा जिनका उत्पादन 6 मीटरी टन प्रतिदिन था अथवा इससे अधिक है, को 12 मीटरी टन प्रतिदिन तक विस्तार करने की अनुमति दी गई थी तथा उन एककों को जो प्रति दिन लगभग 3 मीटरी टन अथवा इससे कम हेतु लाइसेंसीकृत अथवा उत्पादन कर रहे थे, को प्रति दिन 6 मीटरी टन उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी गई थी, यदि उन्होंने अपनी वर्तमान लाइसेंसीकृत क्षमता को पर्याप्त रूप में कार्यान्विन कर लिया हो।

उपरोक्त में, यह देखा जा सकेगा कि प्रौद्योगिकी आर्थिकीय आधार पर क्षमता के विस्तार करने की अनुमति दी गई तथा बहुत बड़े और बड़े तथा अन्य औद्योगिक घरों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता गया।

ब्यटिल एल्कोहल के मूल्यों में वृद्धि

2796. **श्री मधु लिमये** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1973 में ब्यूटिल एल्कोहल के मूल्यों में 700 रुपये प्रति टन की वृद्धि हुई है;

(ख) क्या 1973 के मध्य में इसी प्रकार की वृद्धि हुई थी;

(ग) क्या मूल्यों में वृद्धि करने के लिये उत्पादनों ने सांठ-गांठ कर ली है; और

(घ) क्या एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन किये जाने के लिये इस मामले को एकाधिकार और निर्बन्धनात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को सौंपा जा रहा है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

लेखा परीक्षा विभाग के सीनियर स्केल अफसरों की उत्तर रेलवे में प्रतिनियुक्ति

2797. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के सीनियर स्केल के अफसरों को जोनल रेलवे के लेखा परीक्षा और लेखा विभागों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कुल कितने सीनियर स्केल के अफसर पहली जनवरी, 1974 तक एक वर्ष से अधिक समय के लिये उत्तर रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ग) इन अधिकारियों को पहली जनवरी, 1974 तक कुल कितना प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया गया; और

(घ) क्या इन अधिकारियों को अनुभव प्राप्त करने के लिये विभिन्न अनुभागों में नियुक्त किया गया है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सम्भवतः यह संदर्भ भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अफसरों की रेलों पर प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में हैं; यदि ऐसा है, तो हां।

(ख) एक

(ग) 2936.22 रुपये।

(घ) जी हां।

भारतीय संबिधान का पूर्ण रूप से पुनर्विचार करने का प्रस्ताव

2798. **श्री एम० रःम गोपःल रेड्डी : क्या बिधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के संविधान को देश की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिये उस पर पूर्ण रूप से पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अरकोणम (दक्षिण रेलवे) में इंजीनिरिंग वर्कशाप का निरीक्षण

2799. **श्री था किरुत्तिननः** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 और 1973-74 में तमिलनाडु राज्य के फैक्टरी निरीक्षकों ने दक्षिण रेलवे में अरकोणम में इंजीनियरिंग वर्कशाप का निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या फैक्टरी निरीक्षकों ने वर्कशाप को कोई प्रतिवेदन भेजा है; और

(ग) प्रतिवेदन का सार क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सूचना अनुबन्ध में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल- टी०- 6398/74]

एकाधिकार गृहों की आस्तियों में वृद्धि

2800. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या **बिधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षों में एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन में उल्लिखित 75 एकाधिकार गृहों की कुल आस्तियों में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या एकाधिकार कम्पनियों की संख्या भी 75 से बढ़कर 93 हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो उन कम्पनियों का आस्तियों में कितनी वृद्धि हुई है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : (क से (घ) : प्रश्न में उल्लिखित "एकाधिकारी घरानों" से उन वृहत औद्योगिक घरानों के लिये निर्देश है, जिन पर एकाधिकार जांच आयोग की रिर्पोट में चर्चा की गई थी। इन घरानों की इसके पश्चात् औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा पुनः परीक्षा की गई थी, एवं इनमें से केवल बीस घराने, जिनकी परिसम्पत्तियां 35 करोड़ रुपयों से अधिक बढ़ गई थीं, औद्योगिक लाइसेंस नीति के प्रसंग में बृहत औद्योगिक घराने समझे गये थे। फरवरी, 1973, में जब सरकार ने, अपनी संशोधित लाइसेंस नीति की घोषणा की थी, से बृहत औद्योगिक घरानों के सम्बन्ध में आधारभूत परिवर्तन हो गये हैं। इस संशोधित नीति की दृष्टि से, एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत उपक्रम, अर्थात्:—

(1) वे उपक्रम, जिनके पास स्वयं अथवा अपने अन्तः सम्बन्धित उपक्रमों सहित, 20 करोड़, रुपयों से कम नहीं की परिसम्पतियाँ हों, जिससे वे धारा 20(क) के उपबन्धों को आकर्षित करते हों, अथवा

(2) वे प्रमुख उपक्रम, जिनके पास स्वयं अथवा अपने अन्तः सम्बन्धित उपक्रमों सहित, 1 करोड़ रु० से कम नहीं की परिसंत्तियां हों, जिससे वे एकाधिकार एवं निवन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 20(ख) के उपबन्धों को आकर्षित करते हों: बृहत औद्योगिक घराने समझे जाते हैं।

2. एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत, इसकी धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों के लिये, अपनी परिसम्पतियों के मूल्यों में वर्ष प्रतिवर्ष के परिवर्तनों की बाबत सूचना भेजना अपेक्षित नहीं है। धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों का सारभूत विस्तार, यह निश्चित करने के लिये, अधिनियम के अध्याय 3 के उपबन्धों के अनुसार विनियमित होता है, कि इससे आर्थिक शक्तियों के, जन हित के विरुद्ध संकेन्द्रण, को रोका जा सके।

अशोधित तेल के मूल्यों के बारे में भारत और ईराक के बीच समझौता।

2801. **श्री त्रिदिव चौधरी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष भारत और ईराक के बीच हस्ताक्षर किये गये दीर्घकालीन आर्थिक समझौते के अन्तर्गत ईराक द्वारा भारत को सप्लाई किये जाने वाले अशोधित तेल के मूल्यों के लिये इन दोनों के बीच कोई अन्तिम और सुदृढ़ समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो अब अशोधित तेल का प्रति बैरल मूल्य क्या निश्चित किया गया है और क्या आगामी वर्षों में इस मूल्य समझौते में मूल्यों के संशोधन के खंड हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 1974 में ईराक द्वारा सप्लाई किये जाने वाले अशोधित तेल के मूल्य के सम्बन्ध में भारत एवं ईराक के बीच एक करार किया गया।

(ख) इस स्तर पर न तो सहमति प्राप्त प्रति बैरल अशोधित तेल के मूल्यों और न ही भारत व ईराक के बीच किये गये करार के खण्डों को बताना जनहित में हैं।

पैट्रोल तथा पैट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने के बारे में योजना

2802. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'ओपेक' सदस्यों द्वारा अशोधित तेल के मूल्यों की अभूतपूर्व वृद्धि को ध्यान में रखते हुये सरकार ने पैट्रोल और अन्य विभिन्न पैट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने के लिये समय-समय पर, इनका मूल्य बढ़ाने के बजाये योजना आयोग संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से परामर्श कर कोई समेकित योजना और अनुमान तैयार किये हैं; और

(ख) अशोधित तेल के आयात में कितनी मात्रा कम करने का लक्ष्य रखा गया है और पैट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त 'एनर्जी' साधनों के स्थान पर 'एनर्जी' के किन वैकल्पिक साधनों को रख दिया जायेगा?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अशोधित तेल एवं परिष्कृत पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप तेल की खपत को कम करने की तथा तेल को उर्जा के दूसरे साधनों में परिवर्तित करने की विभिन्न सम्भावनाओं की सरकार जांच कर रही है। योजना आयोग द्वारा अनेक विशेषज्ञ समितियां गठित की गई है तथा ये पैट्रोलियम उत्पादों के प्रतिस्थापन के सम्भावनाओं तथा खपत कम करने के विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप पैट्रोलियम उत्पादों की खपत में बचत की सीमा का इस स्तर पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे सरकारी एवं सरकारी क्षेत्रीय वाहनों में मोटर स्पिरिट की खपत पर नियंत्रण रखें। ये आदेश केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों पर भी लागू होंगे।

फरक्का बांध परियोजना फोडर-नहर के ऊपर पुलों का निर्माण

2803. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्लारपुर के निकट आर० डी० 28 धुलिया पकुर अन्तर्राज्यीय सड़क के लिये आर० डी० 62, शकरगुर के निकट आर० डी० 34 पर फरक्का बांध परियोजना फोडर नहर पर पुलों के निर्माण के बारे में तथा आर० डी० 87 से 98 तक नहर खोदने आर० डी० 107 पर एन० एच० 34 के लिये 'डाईबर्शन' की व्यवस्था करने तथा आर० डी० 117 पर वी० ए० के रेलवे ट्रेक डाइवर्शन बनाने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या उचित सर्वेक्षण द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि बिहार में फरक्का बांध के ऊपर कितना पिछला 'केचमेंट एरिया' पानी में डूब गया है और क्या जलमग्न क्षेत्र के बारे में बिहार राज्य को सहमति दी गई है; और

(ग) फोडर नहर कब तक पूरी हो जायेगी गौर गंगा से हुगली भगीरथी चेनल में 40 क्युसेक जल का प्रवाह लाना कब तक संभव हो सकेगा?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) उल्लिखित कार्य की विभिन्न मदों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:—

कार्य	कार्य निष्पादन की वर्तमान स्थिति
(1) बल्लालपुर के निकट आर० डी० 28 पर पुल (2) शंकरपुर के निकट आर० डी० 34 पर पुल	बल्लालपुर-शंकरपुर क्षेत्र के लाभार्थ आर० डी० 28.5 पर सड़क के पुल की स्वीकृति अभी हाल में दी गई है। इस पुल का शिलान्यास 28-2-1974 को किया गया था।
(3) धुलियान-पाकुर सड़क के आर० डी० 62 पर पुल	एक एबेटमेंट कूप पर भार परीक्षण तथा खंभे को ऊंचा करने को छोड़ कर उपसंरचना पूरी हो गई है। डैक पट्टी की ढलाई प्रगति पर है।
(4) आर० डी० 87 से आर० डी० 98 तक नहर की खुदाई	कार्य प्रगति की प्रौढ़ावस्था में है।
(5) आर० डी० 107 पर एन० एच० 34 के लिये व्यपवर्तन (6) आर० डी० 117 पर बी० ए० के रेल पटरी के लिये व्यपवर्तन	रेलवे लाइन तथा राजपथ 34 दोनों को आर० डी० 112 पर रेल-मय सड़क पुल से व्यपवर्तित किया जायेगा। रेल यातायात पहले ही नये पुल को व्यपवर्तित किया जा चुका है। सड़क वाला भाग पूर्ण होने वाला है।

(ख) परियोजना द्वारा किये गये पम्प जल सर्वेक्षण के अनुसार 5,029 हैक्टेयर क्षेत्र डूब जायेगा। इसमें से, 390 हैक्टेयर पश्चिमी बंगाल, 2,620 हैक्टेयर बिहार और 2,019 हैक्टेयर बिहार अथवा पश्चिमी बंगाल में होगा जो कि दोनों राज्यों द्वारा किये जा रहे मध्य-प्रवाह सर्वेक्षण को अन्तिम रूप दिये जाने पर निर्भर होगा। आलावन के लिये दोनों राज्य सरकारें सहमत हैं तथा उन्होंने भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही शुरू कर दी है।

(ग) पोषक नहर पर 1974 की मानसून तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

केजहर (केरल) तथा मदुरै (तमिल नाडु) को भारतीय रेलवे की 'माइक्रोवेव नेट वर्क' के साथ जोड़ने का प्रस्ताव

2804. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल स्थित केजहूर में स्टेशन की एक नई इमारत बनाने का है;

(ख) क्या केरल राज्य मे केजहूर तथा तमिल नाडु में मदुरै को भारतीय रेलवे के 'माइक्रोवेव नेट वर्क' (सूक्ष्म तरंग प्रणाली) के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। केरल राज्य में केजहूर नाम का कोई स्टेशन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अमरीकी परमाणु-शक्ति-मुक्त विमान वाहक "किट्टी हाक" का हिन्द महासागर में प्रवेश

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : महोदय, मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनके प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें:

> "अमरीकी सरकार द्वारा अपने परमाणु शक्ति युक्त विमान वाहक 'किट्टीहाक' को हिन्द महासागर के अन्दर प्रवेश करने का आदेश दिये जाने का समाचार"

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सदन को मेरा वह वक्तव्य याद होगा जो मैंने पिछले नवम्बर में दिया था जब अमरीका की 'टास्क फोर्स' अपना विमान वाहक 'हानकाक' लेकर हिन्द महासागर में प्रवेश कर गई थी। अमरीकी स्रोतों ने तब कई सफाइयां पेश की थीं। मैंने इस घटना पर सरकार की आशंका व्यक्त की थी जो इस सम्भावना पर आधारित थी कि उससे स्थाई तौर पर अधिक संख्या में सैनिक उपस्थिति बढ़ेगी और इस तरह एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जायेगा जिससे बड़े बड़े देशों में होड़ बढ़ जायेगी और उस क्षेत्र में सैनिक स्पर्धा उत्पन्न हो जायेगी। इसलिये हमें इस सूचना के मिलने पर चिन्ता हुई है। 'किट्टी हाक' नामक विमान वाहक के आने के बारे में वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूतावास ने पुष्टि कर दी है। चाहे यह जहाज की पुनः स्थापना हो अथवा उसकी संख्या में वृद्धि हो, इस विश्वास की पुष्टि करता है कि अमरीका की नौ सेनायें हिन्द महासागर में पर्याप्त समय तक रुके रहना चाहती हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे बिना भी नहीं रह सकते कि डिगो गार्सियां में अमरीका द्वारा अड्डे की सुविधाओं का विस्तार इस क्षेत्र में अमरीका की नौसैना की इस प्रकार दीर्घकालिक उपस्थिति से जुड़ा है।

हिन्द महासागर के बारे में हमारी नीति कई बार व्यक्त की जा चुकी है किसी एक बड़े देश की नौसेना की बड़ी संख्या में उपस्थिति से निश्चय ही अन्य बड़े देशों की नौसेनाओं को आने का प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार की स्पर्धा से तटवर्ती देशों के लिये समस्यायें उठ खड़ी होंगी, जिनमें से बहुत बड़ी संख्या में देश हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाये रखने के इच्छुक हैं। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 16 दिसम्बर, 1971 के उस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया है जिसमें हिन्द महासागर को सदा सर्वदा के लिये शांति का क्षेत्र घोषित किया गया है और जिसमें बड़े देशों से कहा गया है कि वे हिन्द महासागर में अपनी अपनी सेनाओं का और विस्तार करने पर रोक लगायें। सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में तथा अन्य स्थानों पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये किये जाने वाले प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान भी दिया है। इसलिये हम हिन्द महासागर में अमरीकी नौसेना की निरन्तर उपस्थिति पर गम्भीर रूप से चिन्तित हैं जिसकी पुष्टि विमान वाहक 'किट्टी हाक' के आने से हुई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : डिगो गार्शिया अड्डे से हिन्द महासागर में अमरीकी सामरिक शक्ति का त्रिकोण पूरा हो जायेगा। अमरीका के अन्य दो सैनिक अड्डे दक्षिण अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया में स्थित हैं। अमरीका ने दक्षिण अफ्रीका में सायमसन्स टाउन से लेकर आस्ट्रेलिया में उत्तर-पश्चिम अन्तरीप तक नेगनेव, मेलडाइवज आदि अनेक नौसैनिक अनेक अड्डे बनाकर सैनिक संचार को बहुत सुदृढ़ तथा आधुनिक बना लिया है जिससे उनके परमाणु प्रक्षेपशास्त्रों तथा पंडुब्बियों को सहायता मिल सके।

'किट्टी हाक' में 80 विमान तथा 5,000 कर्मचारी रहते हैं तथा उसमें तीन विध्वंसक और एक आयलर होता है। अमरीका ने हिन्द महासागर में नौसैनिक अड्डों का जाल बिछा दिया है। थाईलैंड के आस पास उटापाओ, उड्स कोहट, नाखन, फैमन और डबोलों नामक स्थानों पर 6 सामरिक महत्व के अड्डे बना लिये हैं। डिमागो मार्शियां में अधिक सुविधायें जुटाने का अर्थ है ईंधन भण्डार की क्षमता में वृद्धि करना तथा बड़े जहाजों के लिये स्थान बनाना आदि । उन सुविधाओं के लिये 32.3 मिलयन डालर खर्च किये जा रहे हैं तथा इस सम्बन्ध में यह तर्क देना कि वहां सभी उपस्थित के कारण ऐसा किया जा रहा है। नितान्त भ्रामक है। पोलिटीको, मिलिट्री एफेयर्स के डायरेक्टर ने भी यह स्वीकार किया था कि 'हिन्द महासागर में चाहे रुसी शक्तियां रहें अथवा नहीं अमरीका अपने कार्य को आगे बढ़ायेगा।' अमरीका का कहना है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों के लिये अपने राजनयिक प्रयत्नों को सुदृढ़ कर रहे हैं। वास्तव में इन प्रयत्नों का उद्देश्य केवल पिछड़े हुये तथा विकासशील देशों का रक्त चूसना है।

इतना ही नहीं बंगला देश में चटगांव और कोक्स बाजार में 10 अमरीकी मत्स्य नौकायें गुप्तचरी का कार्य कर रही हैं जिनमें आधुनिक किस्म के उपकरण लगे हैं। श्री चव्हाण ने भी तब स्वीकार किया था कि पटना, बंगलौर में तथा अन्य दो स्थानों पर सी० आई० ए० के चार केन्द्र हैं। आसाम को भी वहां के मुख्य मंत्री ने सी० आई० ए० का अखाड़ा बताया है।

देश को यूनियन कार्बाइड से खतरा है। बिजारा में मत्स्य नौकाओं के नाम पर आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित नौकायें हमारे देश में गुप्तचरी कर रही हैं। भारत सरकार को नार्थ काटियम सरकार से सबक सीखना चाहिये । उन्होंने अमरीका के घुटने टिका दिये जब उन्होंने देखा कि वे उनके देश की एकता पर कुठाराघात कर रहे हैं । किन्तु हमारे देश की सरकार ने हमारे देश की प्रतिष्ठा को अमरीका के हाथों बेच दिया है।

यद्यपि श्री जानसन ने वियतनाम में सामूहिक हत्याकांड कराया है । तथापि प्रधान मंत्री ने उन्हें शांतिप्रिय व्यक्ति कहा है। जानसन ने अपने संस्मरण में कहा है कि भारत सरकार के कुछ उत्तरदाई व्यक्ति अमरीका के हितों के लिये कार्य करते रहे हैं "तत्कालीन खाद्य और कृषि मंत्री तथा खाद्य सचिव" इस सम्बन्ध में पूछे गये मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

भारतीय अड्डों से चीन के ऊपर उड़ान करने, अमरीका के फोटोग्राफ खींचने वाले विमानों को अनुमति दी गई हैं। अमरीका की एक धनाडय कम्पनी के सहयोग से 'पीस ईविडगो' नामक परियोजना बनाई गई है। उन्होंने वियतनाम में वजैली गैस की सप्लाई की है। हमारे देश के प्रतिभावान व्यक्तियों ने अमरीकी धनराशि का विरोध कया है किन्तु अब वह चोरी छिपे लाई जा रही है।

जैसा कि मैंने कहा है कि ये अमरीका से मिले हुये हैं तथा दुहरी नीति का अनुसरण कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि देश में जितना भी अमरीकी व्यापार है उन सब का अर्जन किया जाये जैसा कई देशों द्वारा किया गया है।

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने मेरे सहयोगियों तथा अधिकारियों पर व्यापक आरोप लगाये हैं तथा यह अनुचित है। **(व्यवधान)**

मेरा विचार है कि यदि भारतीय संसद सामूहिक रूप से अमरीका के नौसैनिक अड्डों की स्थापना के विरुद्ध आवाज उठाये तो उनका प्रभाव बहुत अधिक होगा। श्री ज्योतिमर्य बसु के वक्तव्य जैसे वक्तव्यों

से कोई लाभ नहीं होगा। सरकार की आन्तरिक नीतियों की आलोचना से कोई हित नहीं होगा। इस बारे में यह एक व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं वरन सरकार, देश और संसद का समग्र रूप से 'विरोध है। **(व्यवधान)** मेरा सुझाव है कि श्री ज्योतिर्मय बसु और उनकी पार्टी हमारे साथ मिलकर डिगो गार्शिया में नौसैनिक अड्डों की स्थापना के विरुद्ध आवाज उठाये। यह कह कर वह देश की कोई सेवा नहीं कर सकते कि भारत सरकार की उस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। अमरीका में भी विपक्षी दल इस अड्डे पर उतनी भारी धनराशि खर्च किये जाने का विरोध कर रहे हैं। अमरीका की इस कार्यवाही का विरोध हिन्द महासागर के आसपास के अन्य देशों द्वारा भी किया जा रहा है। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश भी चाहते हैं कि हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र रखा जाये।

श्री सी० के० चन्द्राप्पन (तेल्लीचेरी) : महोदय ! 'किट्टी हाक' विमान वाहक जहाज को भेजकर अमरीका ने विश्व जनमत की अवहेलना की है। मुझे ज्ञात हुआ है कि अमरीका न केवल यही एक जहाज हिन्द महासागर में नहीं भेजा। हिन्द महासागर में उस से पहले दो अन्य विमान वाहक जहाज हैं जिनमें 140 और 160 विमान हैं। फारस की खाड़ी में दो विध्वंसक तथा एक सम्फीरियन जहाज हैं। डिगो गार्शियां में भी दो विध्वंसक तथा एक कमांड शिप हैं। उसकी नौसैनिक शक्ति के अतिरिक्त यह 'किट्टी हाक' भी हिन्द महासागर में भेजा गया है जिसमें आधुनिकतम उपकरण हैं तथा 80 से 90 तक विमान हैं और लगभग 5,000 सैनिक है।

यह अमरीका की अत्यन्त गन्दी राजनीति है। भारत सरकार ने अमरीका के इस कृत्य का विरोध किया है तथा हम इस विरोध का समर्थन करते हैं। किन्तु हमारी समझ में यह नहीं आता कि अमरीका स्थित हमारा राजदूत सदा अमरीका की सराहना करता है तथा उसे हमारा मित्र तथा सहायक बताता है। इसके विपरीत अमरीकी राजदूत भारत के प्रत्येक भाग में अमरीका की गन्दी नीतियों का प्रचार करता है तथा अमरीका के आक्रामक रवैये का औचित्य सिद्ध करता फिरता है। क्या मंत्री महोदय अमरीका में नियुक्त राजदूतों के बारे में कोई कार्यवाही करेंगे?

अमरीकी समाचारपत्रों तथा भारतीय समाचार पत्रों में भी यह प्रचार किया जा रहा है कि अमरीका नौसैनिक शक्ति में इसलिये वृद्धि कर रहा है क्योंकि रूस भी ऐसा ही कर रहा है। हाल में एक भारतीय समाचारपत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि भारत ने रूस को पत्तन सुविधायें देने का प्रस्ताव किया है। यह भी समाचार प्रकाशित हुआ है कि जब रूस ने हिन्द महासागर में अपनी नौसैनिक शक्ति भेजी तो भारत शांत रहा किन्तु जब अमरीका ने ऐसा किया तो उसने रोष व्यक्त किया है। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस बारे में स्पष्टीकरण दें।

अमरीका का कहना है कि रूस हिन्द महासागर में परमाणु परीक्षण करने का प्रयास कर रहा है। भारत सरकार ने इस बात का खण्डन भी किया है। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस विषय में और स्पष्टीकरण दें कि मंत्री महोदय कृपया सभा को बतायें कि विरोध के अतिरिक्त सरकार वास्तव में और क्या कार्यवाही करेगी। सम्पूर्ण देश तथा सभी शांतिप्रिय देश अमरीका के इस आक्रामक रवैये का विरोध कर रहे हैं। कया भारत सरकार इस प्रकार के विरोध के अतिरिक्त अमरीका की भत्सर्ना करेगी क्योंकि साम्राज्यवादी देशों ने सदा विश्वशांति भंग करने का प्रयास ही किया है। बंगलादेश तथा वियतनाम आदि के सम्बन्ध में यह सिद्ध हो चुका है। अभी तक हम समझते थे कि हमारी समुद्री सीमा सुरक्षित है किन्तु हाल की घटनाओं से सिद्ध हो गया है कि हमारी उस सीमा पर भी घात लगाई जा रही है। बंगाल की खाड़ी में अमरीकी जहाज सभी जहाजों की गुप्तचरी कर रहे हैं। यद्यपि रूसी जहाज, पत्तन को साफ कर रहे हैं क्योंकि वहां पाकिस्तान ने कुछ विनाश कार्य किया था।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार क्या डिगो गार्शियां के बारे में ब्रिटेन से बातचीत करेगी तथा यदि वहां से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता तो राष्ट्रमण्डल में रहने का क्या लाभ है? अन्त में संक्षेप में कहना चाहता हूं कि भारत सरकार का नौसैनिक शक्ति तैयार करने के बारे में अमरीका और चीन के गठबन्धन के बारे में क्या मत है और राष्ट्रमण्डल के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य के विचार मुख्यतः भारत सरकार के विचारों से मिलते हैं। उन्होंने डिगो गार्शियां में अड्डा बनाये जाने पर विरोध व्यक्त किया है। जहां तक राजदूतों का सम्बन्ध है, उनका मुख्य कार्य दोनों देशों के सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न करना है। हमारा राजदूत भी यही कार्य कर रहा है। इसमें उसका कोई दोष नहीं है।

जहां तक श्री मोयनीदन के वक्तव्य का सम्बन्ध है, हम उसमें निहित तर्कों को अवैध मानते हैं। डिगो गार्शियां अड्डे के बारे में हमारा विरोध दृढ़ है तथा हम अपनी नीति पर अडिग हैं। इसके अतिरिक्त हमारा विचार है कि संयुक्त राष्ट्र में कमेटी और ग्रुप को सक्रिय कर दिया जाये। हिन्द-महासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखने के लिये महासभा के संकल्प के अनुसार हिन्द महासागर में नौसैनिक अड्डों की स्थापना के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय मत जुटाने के लिये उक्त ग्रुप को सक्रिय किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तब तक तो डिगो गार्शिया में सब काम पूरा हो जायेगा।

श्री स्वर्ण सिंह : वह तो लगभग पूरा ही है। उसकी शक्ति को बढ़ाया जा रहा है। किसी एक अड्डे के लिये नहीं वरन हिन्द महासागर में हम सभी नये पुराने अड्डों का विरोध करते हैं। हम सभी गुटनिरपेक्ष देशों का मत एकत्र करके इसका विरोध करेंगे तथा अमरीका इतने देशों की आवाज की उपेक्षा नहीं कर सकता। स्वयं अमरीका में भी इस का विरोध किया जा रहा है।

जहां तक राष्ट्रमण्डल का सम्बन्ध है उसके अधिकांश सदस्य देश डिगो गार्शियां में अड्डों की स्थापना के विरुद्ध हैं। राष्ट्रमण्डल एक ऐसी संस्था है, जहां अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा होती है तथा सम्बन्धित राष्ट्र पर मिल कर प्रभाव डाला जाता है। राष्ट्र मण्डल के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। राष्ट्रमण्डल के ही कारण आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा था। एशियाई, अफ्रीकी और कैरेबियन देशों की यही इच्छा है कि हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये रखा जाये।

जहां तक चीन और अमरीका की सांठगांठ का प्रश्न है हमें अभी चीन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि उसने कहा है कि हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखा जाये।

श्री समर मुखर्जी : क्या चीन ने संयुक्त राष्ट्र संकल्प का समर्थन किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने कहा है कि चीन ने इस बात का समर्थन किया है कि हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखा जाये।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : यदि हिन्द महासागर में कोई एक देश आता है तो अन्य देश भी आने का प्रयास करेंगे। सरकार के प्रयत्नों के बावजूद हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखना कठिन हो गया है तथा हमारे देश को उसी दिशा में खतरा उत्पन्न हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अमरीका और ब्रिटेन में डिगो गार्शिया में अड्डे बनाने के बारे में कोई संधि हुई थी ?

भारत राष्ट्र मण्डल का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यह कहा गया है कि राष्ट्रमण्डल के अधिकांश देश हिन्द महासागर में अमरीका की उपस्थिति से गंभीररूप से चिंतित हैं।

भारत सरकार ने ब्रिटेन को इस बात के लिए सहमत करने के लिए क्या प्रयत्न किये कि वह अमरीका के साथ इस प्रकार की संधि न करें ? क्या राष्ट्रपति मण्डल में कभी इस समस्या पर चर्चा की गई है ? ब्रिटेन ने भारत पर यह आरोप लगाया कि हिन्द महासागर के एक बड़ी ताकत की उपस्थिति पर भारत मौन रहा। क्या सरकार ने कभी इस आरोप का खण्डन किया ? भारत सरकार की हिन्द महासागर में रूसी शक्ति के प्रसार के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ? क्या प्रावदा में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर विदेश मंत्री का ध्यान दिलाया गया है कि हिन्द महासागर एक विशाल और मुक्त महासागर है जिसका कोई राष्ट्र उपयोग कर सकता है ?

[उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER **in the Chair**]

क्या भारत सरकार ने रूस से कभी कहा कि इस प्रकार का कथन भारत की सुरक्षा के लिए घातक है।

क्या यह सच नहीं है कि हिन्द महासागर के आसपास के देशों ने किसी न किसी बड़ी ताकत को किसी न किसी प्रकार की सुविधाएं दी हैं। क्या यह सच नहीं है कि हिन्द महासागर में ब्रिटेन के साथ-साथ अमरीका और रूस के भी अड्डे हैं जैसे कि सीचैल्स मेडागास्कर आदि स्थान। समाचार है कि बारबारा में रूसी अड्डा है जहां एम० ए० एम० मिजाइल्स भी स्थापित हैं। इसी प्रकार अन्य अनेक स्थान हैं।

जब इन्हीं देशों ने किसी न किसी बड़ी ताकत को सुविधा दी हैं तो हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र कैसे बनाये रखा जा सकता है ?

क्या यह बात सच है कि भारत सरकार ने बंगला देश सरकार के साथ अपने मंत्री संबंध होने के कारण बंगला देश की सरकार अथवा रूस की सरकार को इस बात के लिए मनाने का प्रयास किया है कि वह बंगला देश से अपनी नौसेना को हटा ले ताकि जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वयं ही कहा है अन्य बड़े राष्ट्र भी इस ओर आकर्षित न हो जायें ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम विषय की परिधि से बाहर होते जा रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : श्रीमान् जी ये सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं किन्तु हम इस समय हिन्द महासागर को शांति के क्षेत्र के रूप में बनाये रखने के बारे में विचार कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : डियगो गार्शिया का तथा अन्य देशों का भी उल्लेख किया गया है : उन्होंने यह कहा है कि एक बड़े राष्ट्र की उपस्थिति से अन्य बड़े राष्ट्र भी आकर्षित हो जायेंगे। अत. यही मेरा प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि रूस का आणविक बेड़ा आ रहा है, तो उसका कारण यह है कि अमरीकी आणविक बेड़ा यहां उपस्थित है। मैं इस बात को समझ सकता हूं किन्तु हम अब हिन्द महासागर के समूचे प्रश्न के बारे में प्रश्न करने लगे हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : ये सभी संबंधित बातें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात को समाप्त कीजिए।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : ऐसे समाचार प्राप्त हुए हैं कि वहां अमरीका के काफी अधिक जलपोत हैं जिनमें सूचना एकत्र करने के लिए संचार की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार यह भी समाचार मिला है कि गत 9 वर्षों से हिन्द महासागर में रूस के भी 18 से 20 जहाज हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है कि एक बड़े राष्ट्र की इस गतिविधि से अन्य बड़े राष्ट्र भी ऐसे गतिविधियों के लिए आकर्षित न हो जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने अपना प्रश्न पूछ लिया है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : यह सच है कि भारत सरकार हिन्द महासागर को शांति के क्षेत्र के रूप में बनाये रखने में अब तक असफल रही है। हम मंत्री महोदय से यह स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि उनके प्रयास कहां तक सफल रहे हैं अथवा क्या सरकार इस मामले में बिल्कुल ही असफल रही है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि देशों का सभी तरह से व्यापक रूप से इस प्रकार अन्तर्गस्त होना तथ्यों पर आधारित नहीं है और हमें हमेशा विभिन्न पत्तनों द्वारा नौसैनिक एककों या नौसैनिक जलयानों को सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में यदि भेद को समझना चाहिए। उदाहरण के तौर पर भारत खाद्य पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं आदि को खरीदने के लिए भी सभी मित्र देशों की नौसेनाओं को सामान्य बैंकरिंग सुविधाएं देता है चाहे यह अमरीका हो अथवा ब्रिटेन हो अथवा फ्रांस या रूस हो। अतः शांति के समय में इन सामान्य सुविधाओं को आपत्ति जनक नहीं समझा जाता है। किन्तु माननीय सदस्य ने कुछ अधिक बढ़ा चढ़ा कर ही कहा है। ऐसा मालूम होता है कि उन पर पश्चिमी समाचार पत्रों के लगातार प्रचार का प्रभाव पड़ गया हो ....

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं कल से संबंधित नहीं हूं और आप यह नहीं कह सकते हैं कि मैं चीन अथवा रूस का या ब्रिटेन के लिए नहीं अथवा इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं किसी के प्रचार से प्रभावित हुआ हूं। क्या मेरा अपना दिमाग नहीं है ?

श्री स्वर्ण सिंह : दिमाग में सदैव सूचना नहीं होती है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मंत्री महोदय सभी बात का मजाक उड़ा रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री स्वर्ण सिंह : सूचना दूसरों द्वारा सप्लाई की जाती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह हरियाणा में कांग्रेस में नहीं थे।

श्री स्वर्ण सिंह : वह मेरे मित्र हैं। रूस द्वारा मडगास्कर, मारीशियस, स्कोत्रा, सोमालिया तथा इराक में अपने अड्डे बनाये जाने के बारे में दिया गया वक्तव्य तथ्यों के आधार पर

सिद्ध नहीं होता। इनमें से किसी देश के इस आरोप को स्वीकार नहीं किया है। सभी देशों ने इससे इनकार किया है। **(व्यवधान)** मैं आपको बह बताना चाहता हूं कि आप ने जो यह कहा है कि इन देशों में अड्डे हैं, यह बात सही नहीं है। माननीय सदस्य ने हमारे एक मित्र देश अर्थात् बंगला देश का उल्लेख किया और यह भी कहा है कि वहां रूस की नौसेना उपस्थित है। मेरे विचार में श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा है कि कोक्स बाजार और कुछ अन्य क्षेत्रों में अमरीकी जलयात मौजूद हैं। निस्संदेह ही सदन को मालूम है कि युद्ध के समय पाकिस्तानी नौसेना द्वारा चटगांव तथा कोक्स बाजार में सुरंगे बिछा दी गयी थीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने मुझे गलत समझा है। दस जहाज़ कोक्स बाज़ार और चटगांव में थे और वे अमरीका से सम्बन्धित थे और वे मछली पकड़ने के बहाने काम कर रहे थे। किन्तु वह चटगांव और कोक्स बाज़ार आदि का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं श्री राव के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं न कि श्री ज्योतिर्मय बसु के प्रश्न का। श्री राव ने कहा है कि रूस की नौसेना उपस्थित थी। तथ्य यह है कि रूस से चटगांव और कोक्स बाज़ार के कुछ भागों से सुरंगें हटाने के लिये उनसे सहायता मांगी गई थी। आप रूस की इस कार्यवाही को रूसी नौसेना की उपस्थिति नहीं कह सकते। हम किसी भी देश द्वारा किसी अड्डे की स्थापना का विरोध करते हैं चाहे वह देश कोई भी हो। यह विरोध पूर्ण है क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि इससे तनाव पैदा होगा। दूसरा यह आरोप बिल्कुल ही निराधार है कि भारत किसी देश की अपेक्षा किसी अन्य देश के प्रति पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहा है। सर एलस डगलस होम द्वारा दिया गया यह कथित वक्तव्य बिल्कुल निराधार है कि हम चुपचाप बैठे हुए हैं जब कि अन्य देशों की नौसैनाएं हिन्द महासागर में अपने अड्डे बना रही है। हमारा आधार स्पष्ट और सुसंगत है। हम इस क्षेत्र में किसी विदेशी नौसैनिक बेड़े की उपस्थिति या किसी अड्ड की स्थापना किये जाने का विरोध करते हैं।

राष्ट्रमण्डल के देशों के प्रयासों के बारे में यह प्रश्न पूछा गया है उन्होंने सुविधाओं के विस्तार का विरोध क्यों नहीं किया। राष्ट्रमण्डल में इस मामले पर चर्चा करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। किन्तु हमने ब्रिटेन को तथा कथित संचार अड्डों की स्थापना के लिये भी अपना विरोध प्रकट कर दिया था। मैंने अपनी सामान्य नीति के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया है।

स्थगन प्रस्ताव के संबंध में

RE: MOTION FOR ADJOURNMENT

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब नियम 377 के अन्तर्गत मामले पर विचार करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने जेल में भेजे गए गुजरात के छात्रों के बारे में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भेजा है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा करके शान्ति रखिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार अव्यवस्था पैदा कर रही है। यहां कोई भी व्यवस्था नहीं है।

Shri Madhu Limaye (Banka): On a point of Order, Sir......

Please see item Nos. 2 and 3. Yesterday two hundred students were arrested. They have been put in 'C' class which is most improper. The Minister should come forward with a statement in this regard.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। दो सौ छात्रों को जेल में डाल दिया गया है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने जेल में डाले गए उन लड़कों की गिरिफ्तारी के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। **(व्यवधान)**

उन्हें 'सी' क्लास में रखा गया है। उन्हें तुरन्त 'बी' क्लास दी जानी चाहिये। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा ध्यान श्री मधु लिमये के व्यवस्था के प्रश्न की ओर है। जहां तक मैंने समझा है कि श्री मधु लिमये कहते हैं कि मई 2 और 3 के बीच व्यवस्था का प्रश्न है।

Shri Madhu Limaye: My point of order is about the business of the House. Our notices may kindly be admitted.

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Shri Madhu Limaye: I am speaking according to rules.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है.....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति मैं श्री मधु लिमये के व्यवस्था के प्रश्न के बारे में बतलाने जा रहा हूं श्री मधु लिमये..... **(व्यवधान)**

Shri Madhu Limaye: You have listned to my point completely and you are going to give your ruling about it.

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया मेरी बात सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप मेरी बात सुनिये। तब मैं आप की बात को सुनूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपा करके बैठ जाइये। मैं यह कहना चाहता हूं...

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह बात नहीं कर सकते कि आप वहां से आज्ञा दें और अध्यक्ष पीठ वैठा रहे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान् जी, यदि आप हमे इस दृष्टि से ले रहे हैं..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी श्री बसु कहेंगे, उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ***

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये। मेरा ध्यान श्री मधु लिमये के व्यवस्था के प्रश्न की ओर है।

Shri Madhu Limaye: Mr. Deputy Speaker, Sir, please listen to me patiently.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा करके मुझे यह बताइये कि आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास किया है। आप ने कहा है कि मद संख्या 3 पर विचार करने से पूर्व हमें नियम 377 के अन्तर्गत दी गई कुछ सूचनाओं पर विचार करना है।

Shri Madhu Limaye: Notices under rule 377 come between these two items.

उपाध्यक्ष महोदय जो कुछ भी सूचनाएं अध्यक्ष को दी गई थीं, उन पर उन्होंने पूरी तरह विचार किया था। उनमें से कुछ को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। जिन्हें स्वीकार नहीं किया, गया था वे यहां नहीं हैं.....(**व्यवधान**) चूंकि वे मेरे समक्ष नहीं हैं, इसलिये उन्हें विचारार्थ स्वीकार नहीं किया गया है।

Shri Madhu Limaye : Whether the notice regarding the arrest of boys has been admitted ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में बताने जा रहा हूं। यदि आप गुजरात के बारे में कह रहे हैं। मुझे बताया गया है कि कल इस मामले को उठाया गया था.....(**व्यवधान**) श्री बसु मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये.....(**व्यवधान**) जो कुछ भी श्री बसु कहेंगे, उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ***

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वह हस्तक्षेप कर रहे थे.....(**व्यवधान**)

Shri Madhu Limaye: Mr Deputy Speaker, Sir, it is not proper. You can not prevent a member like this.

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी श्री बसु कहेंगे, उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ***

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि आप नियमानुसार नहीं चल रहे हैं, इस लिये मैं यह कह रहा हूं कि जो कुछ भी आप कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री लिमये ने गुजरात के छात्रों के बारे में कहा है। कल जब गुजरात के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी तो इस मामले को उठाया गया था। उस समय मंत्री महोदय ने कहा था कि वह इस समूचे मामले पर विचार करेंगे।

Shri Madhu Limaye: How did he come to know about it. Those students were arrested during the night and they were given 'C' Class.

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

***Not recorded as ordered by the Chair.

उपाध्यक्ष महोदय : अतः नियमों के अनुसार इस मामले को नहीं उठाया जा सकता।

Shri Madhu Limaye: Whether there is any item on the order paper about his statement.

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि वह इस बारे में विचार करेंगे। कुछ सदस्यों ने स्थगत प्रस्ताव भेजे थे और ऐसा हो सकता है कि कुछ अन्य सदस्यों ने अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रस्ताव भेजे हों।

नियमों के अनुसार जिस विषय पर एक सत्र में चर्चा हुई सो उसी सत्र में उस विषय पर दोबारा चर्चा नहीं की जा सकती।

कल इस मामले पर चर्चा हुई थी.....

श्री एच० एम० पटेल (ढ़ढ़का) : इस पर चर्चा नहीं हुई थी।

Shri Madhu Limaye: The arrests were made yesterday and the arrested persons were given 'C' Class during the night.

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे यही कुछ बताया गया था कि गुजरात के छात्रों का कल उल्लेख किया गया था। बेशक मैं कल यहां नहीं था। यदि आप कहते हैं कि कल इसका उल्लेख नहीं किया गया था तो मुझे कार्यवाही-वृत्तान्त की जांच करनी पड़ेगी। मेरा विचार है कि इसका कल उल्लेख किया गया था, इसलिये इस पर चर्चा हुई थी।

श्री एच० एम० पटेल: इस पर चर्चा नहीं हुई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पटेल, मैं आप की बात बाद में सुनूंगा।

यह एक तकनीकी बात है। यदि आप कहते हैं कि इस पर चर्चा नहीं हुई थी, कि केवल इसका उल्लेख ही किया गया था। चूंकि आप सब जोश में हैं, इसलिये मैं आप की बात सुनूंगा। किन्तु मैं आप सब से प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करके सहयोग दें। संक्षेप में कहें तथा विषय से बाहर मत जायें। मैं अन्तिम निर्णय देने से पूर्व आपकी बात सुनूंगा।

Shri Madhu Limaye : The Government should give the information yesterday we were not even told that the 29 resignations are pending with the speaker of Gujarat Assembly and here the ruling was given by the speaker that.....

उपाध्यक्ष महोदय: यह एक भिन्न प्रश्न है। आप प्रसंग से बाहर की बात कर रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : I am not going out of the way. I had raised the point that nothing has been said about 29 resignations pending with the speaker of Gujarat Assembly. Will the Government spell out its reactions on the demand of the boys to institute an enquiry into the allegations of corruption, and granting compensation to the persons who have been killed or injured and to look into the incidents of firings ? The Assembly can be dissolved either by the order of the President or on a strong demand of the Public.

श्री एच० एम० पटेल: इन गिरफ्तारियों से पैदा हुई गम्भीर स्थिति के बारे में आज सभा में एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये था। नव निर्माण समिति ने, जिसके सदस्य छात्र हैं, पहले ही घोषणा की है। कि आज अहमदाबाद बन्द रहेगा। क्या यह मामला इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इस के बारे में वक्तव्य दिया जा सके।

श्री पी० जी० मावलंकर (ग्रहमदाबाद) : भारत सरकार इन गंभीर तथ्यों के बारे में इस सभा को जानबूझ कर ग्रन्धकार में रख रही है । छात्रों की गिरफ्तारी इस बात का ज्वलंत उदाहरण है । मंत्री महोदय हमें यह बताने में सफल नहीं हो पाये हैं कि छात्रों को कहां ग्रौर किस उत्तेजना के फलस्वरूप गिरफ्तार किया गया है । उन्हें कितने समय में जेल में रखा जायेगा ग्रौर उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है । मंत्री महोदय ने केवल यही कहा है कि वह वक्तव्य देंगे । किन्तु ग्राज ग्रभी तक कोई भी वक्तव्य नहीं दिया गया है । इस की प्रतिक्रिया स्वरूप गुजरात की नव-निर्माण समिति ने 'ग्रहमदाबाद बन्द' का पहले ही ग्राव्हान कर दिया है । समूचा नगर बन्द है ग्रौर वहां 1000 पुलिस के सिपाही पहरा दे रहे हैं ग्रौर छात्रों ग्रौर सामान्य जनता को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार एक वक्तव्य दे, ताकि हम प्रश्न पूछ सकें ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The Government have insulted the students by keeping them in 'C' class Jail. They are not criminal. They had come to the capital for a political agitation. If the Government go on treating the students in this manner, this agitation would not remain confined to the students of Gujarat only. Even the citizens of Delhi can also join it. The Government should not make it a prestige issue and dissolve the Assembly there.

Shri S.M. Banerji (Kanpur) : We want that the boys should be released, so that normaley can be restored. They should be treated as political prisoners. It is improper that they were given 'C' class.

उनको तुरन्त रिहा किया जाना चाहिये, ग्रन्यथा स्थिति ग्रौर भी बिगड़ सकती है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ग्रब तक गुजरात की राजधानी से 1500 युवक ग्रा चुके हैं । उनको गम्भीर कठिनाइयों को झेलना पड़ रहा है । ग्राज 200 ग्रौर युवक यहां पहुंच रहे हैं । इन नवयुवकों को राजनीतिक कैदी का दर्जा न देना ग्रौर उनके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार करना एक ग्रपमानजनक बात है ।

कल श्री दीक्षित ने यह स्पष्ट ग्राश्वासन दिया था कि वह इसकी जांच करेंगे । वे 20 घंटे से ग्रधिक समय ले चुके हैं । हमें ग्राशा थी कि ग्राज प्रातः एक विज्ञप्ति जारी की जायेगी । परन्तु ऐसा नहीं हुग्रा । उपाध्यक्ष महोदय सरकार से कहें कि यह हमें बताये कि क्या वह उन्हें रिहा कर देगी ग्रौर क्या जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाता, उन्हें राजनीतिक बन्दी का दर्जा दिया जायेगा ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : श्री दीक्षित ने कल दिये गये ग्रपने ग्राश्वासन को **(व्यवधान)** पूरा नहीं किया है । मैं यह मांग करता हूं कि इन गिरफ्तार किये गये 210 छात्रों को बिना शर्त रिहा कर दिया जाये ।

दूसरा उन्हें ग्रपराधी नहीं समझा जाना चाहिये इन्हें राजनीतिक ग्रान्दोलनकारी समझा जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बिना कार्यवाही वृत्तान्त को देखे ऐसे कुछ भी नहीं कह सकता । यदि उन्होंने ऐसा ग्राश्वासन नहीं दिया है, तो प्रश्न ही नहीं उठता । छात्रों के प्रति बेहतर व्यवहार के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री जो यहां मौजूद हैं संबंधित मंत्री तक यह बात पहुंचा देंगे । ग्रतः हमें इस बात को समाप्त कर लेने दीजिये । मैं श्री गणेश से ग्रनुदानों की ग्रनुपूरक मांगों (सामान्य) को प्रस्तुत करने की प्रार्थना करता हूं । श्री के० ग्रार० गणेश ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1973-74

Supplementary Demands for Grants (General), 1973-74

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वर्ष 1973–74 के बजट सामान्य संबंधी अनुपूरक अनुदानों की मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं उस पर आपत्ति करता हूं **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : शान्त रहिये । अब हम नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर विचार करेंगे ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

Matters under Rule 377

1. अनाज आदि के मूल्यों में कमी करने और उचित दर की दुकानों के माध्यम से अनाज का वितरण किये जाने की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के राजस्थान के निवास स्थान के सामने महिलाओं द्वारा कथित प्रदर्शन ।

2. मध्य प्रदेश के कतिपय जिलों में अनाज की कमी और वर्षा का अभाव ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरम) : कल कलकत्ता के राज भवन के सामने हजारों महिलायें प्रदर्शन कर रही थीं और यह मांग कर रही थीं कि खाद्यान्नों के मूल्य कम किये जायें तथा राशन की दुकानों से खाद्यान्न उचित मूल्य पर दिये जायें । इसके साथ ही वे सरकार को इस संबंध में कोई कार्यवाही न किये जाने के विरुद्ध रोष व्यक्त कर रही थीं । पुनर्गठित राशन व्यवस्था जिसके द्वारा गावों में चावल और गेहूं दिया जाता था पूर्ण रूप से असफल हो गयी हैं । इस संबंध में हमें सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी मिलनी चाहिये जिससे स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके । अन्यथा मुझे भय है कि कहीं कुछ और न हो जाये ।

मध्य प्रदेश के कतिपय जिलों में अनाज की कमी और वर्षा का अभाव

Shri Ranabahadur Singh (Sidhi) : During the last monsoon session, I had drawn the attention of the Government thrice to the fact that there has been failure of rains in Sidhi area of Madhya Pradesh. But every time we have been told that they have not received any information in this regard. In the meantime the situation has deteriorated as there has been no rains during the winter. Moreover, whatever little crops were there, they were damaged by frost. Therefore, it is very necessary to make recommendation to the State Government to supply foodgrains and to suspend the collection of compulsory levy in that area.

रेलवे बजट 1974-75—सामान्य चर्चा जारी

Railway Budget 1974-75—General Discussion—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम रेलवे बजट पर पुनः चर्चा करेंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : रेल बजट पर चर्चा से पूर्व मैं एक बात कहना चाहता हूं । आप ने गार्डों के नियमानुसार कार्य करने के आन्दोलन के कारण सभी यात्री गाड़ियों तथा माल तथा माल गाड़ियों काफी देरी से आने-जाने के बारे में आज के समाचारपत्रों में पढ़ा होगा ।

मैं रेल मंत्री महोदय से इस संबंध में वक्तव्य देने के लिये तथा इस सभा को आश्वासन देने के प्रर्थना करता हूं क्योंकि वह गार्डों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे हैं । वह हमें यह बतायें कि उनका इस आन्दोलन को समाप्त करने के लिये क्या करने का विचार है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं वाद विवाद शुरू करने से पूर्व एक प्रार्थना करना चाहता हूं । इस चर्चा के लिए आवंटित समय में से केवल 3 घंटे और 20 मिनट शेष रह गये हैं । मेरी विपक्ष के नेताओं से बात हुई है और इस बारे में मतैक्य है कि रेल मंत्री को कल उत्तर देने दिया जाये और आज छः बजे तक का समय उन सदस्यों को दे दिया जाये, जो इस पर बोलना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री जगन्नाथ मिश्र अपना भाषण जारी रखेंगे ।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani): The Railway Minister deserves congratulations for making endeavours to lay down the net work of new railway lines in backward areas. The Railway Minister had also announced that new railway lines should be constructed in the backward areas so as to develop them even if there is any loss.

There were certain rail lines which had been destroyed. These lines included Kosi line, Chitouni Bagha line, Saraiganj, Pratap ganj lines, Gohana—Panipat line. The Railway Minister has initiated the renovation of such lines. He has also felt the need of conversion of certain meter-gauge line into broad-gauge lines and initiated action. Similarly he has taken decisions about new lines also.

It becomes clear from this that he has tried to make railways a public utility service. He has taken decisions keeping in view the public interest. These decisions have not been based on parochial considerations . He has tried to do every-thing proportionately for the country.

Hon. members of the Opposition have mentioned labour and management relations in the Railways. I want to say that this matter is not a new to the Railway Minister. He has been a Labour Minister also. He knows that they have got certain rights. He has sympathies towards labour class. But he also feels that labour class must also discharge its duties towards society and must not play in the hands of reactionary forces and resort to strikes and other such activities which harm the society.

The Railway Minister has decided to establish Railway Service Commission in every state so that people of poor classes are not required to travel to far off places for appearing in interviews. One service has already been established with object in view.

These are important aspects but side by side I also want to say that this is a fact that trains are not running in time. The reason for this is that on certain Railways specially N.E. Railway less coaches are added to the trains which result in more load and over-crowding and ultimately it results in irregularity. Therefore efforts should be made to improve the things in this regard.

I also feel that increase in the cost of Platform ticket is unreasonable. People would avoid purchasing Platform ticket and instead purchase tickets for minimum denomination.

Bihar is covered by six Railways but there is no Zonal office in the state. Therefore a zonal office should be set up in Bihar.

On completion of Farakka Railway line 500 employees who had been employed in steamer service have become idle. I suggest that steamer service should be started at Monghya and these persons employed there.

Deluxe Train for Patna should stop at Mokameh. Conductor should be posted in Samastipur-Delhi coach which is attached to Assam Main to avoid inconvenience to passengers. A railway station should be constructed near Rajendra Bridge over River Ganges as lakhs of people come here. All the trains should stop at that station. Sindri is a Commercial city, therefore, it should be converted into a full fledged Railway Station. I also request that Muzaffarpur-Raxaul *via* Motihari line should be converted into a broad-gauge line. Similarly Himachal Pradesh lacks proper rail facilities. A new railway line should be converted between Nangal and Talwara.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : There is no doubt about it that our Railways are facing a serious financial crisis. The first reason for this situation is that there is no co-ordination between Railway Ministry and Planning Commission. Rail economy is affected by over-capitalisation and under-utilization. There should be proper Co-ordination between the two to improve the situation.

Railways are not for Railway Minister or for high officials who can have any number of saloons. Neither these are for travellers of Rajdhani Express or travellers of Air-conditioned trains. These are for travellers of third class. But no attention is being paid towards this category. I feel that there should be two categories of travellers, one who travel during day-time. They should get sitting accommodation and the other category who travel during night. They should get sleeping accommodation.

Additional trains should be run on religious festivals. The rush is increasing in trains. People travel on foot-boards and corridors of 1st class compartments. So much feelings have been aroused that now people have started thinking that when one category is travelling on foot-boards allowing another category to travel in first class is no Socialism. A time can come when people will start saying that when a ticket has been issued sitting accommodation must also be provided. Hence we should start improving their lot.

Conductors are provided on trains but people have to face difficulty in tracing them out. An electric signal outside the compartment could indicate his presence. It is not a big thing. But no attention has been paid towards this.

It appears to me that Railway Ministry is not at all serious about providing any facilities to passengers. More allocation of funds does not indicate increased facilities.

Railway Minister had announced that representation would be provided to workers in management. But will workers be provided representation in Railway Board ? Are they not capable of active participation in managment ? To-day there is a gap between Railway Board and a Railway worker. It is increasing but there is a need to cover this gap. It can be achieved by giving them proper representation.

Railway Service Commissions have been set up at a number of places. But this is not enough. A number of times it has happened that selections are made by the commission but before actually employing the selected persons Railway Service Commi-

ssion again advertises the said posts and calls for fresh applications this is not fair. So, the basic problem can not be solved by merely opening new Railway Service Commicsion.

There are only two trains for Delhi to Bombay *via* Jhansi. Most of the trains go *via* Baroda and Ratlam. This aspect should also be looked into.

There was a narrow-gauge line in old Gwalior State. It runs from Gwalior to Shivpuri. This line should be converted into meter-gauge and linked with Guna. In a meeting of the Railway Convention Committee the General Manager of the Central Railway had agreed to extend the Taj Express train upto Jhansi. But it has not so far been done. It reaches Agra at 10.30 a.m. and stands on the station upto evening. This waiting time could be utilized by extending it upto Jhansi and then bringing it back.

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बइ उत्तर-पूर्व) : रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे के असन्तोषजनक कार्य-करण का कारण अनुशासन की कमी और औद्योगिक संबंधो में गिरावट है । मैं भी यह मानता हूं कि अनुशासन में गिरावट आ रही है । परन्तु औद्योगिक संबंधों के बारे में उनके विचार यह स्पष्ट नहीं करते कि रेलवे का वर्तमान कार्यकरण बिगड़े औद्योगिक संबंधों के कारण है अथवा बिगड़े कार्यकरण के कारण संबंधों में गिरावट आ रही है । मैं समझता हूं कि वर्तमान औद्योगिक संबंध रेलवे के कार्यकरण के कारण नहीं अपितु प्रशासन के कार्यकरण के कारण हैं ।

आज न केवल श्रमिक ही वरन अधिकारी भी संगठित होकर आन्दोलनों का सहारा ले रहे हैं । अतः औद्योगिक सम्बन्धों पर विचार करते समय प्रशासकीय ढांचे पर विचार किया जाना चाहिये। अन्यथा स्थिति में सुधार नहीं हो पाएगा ।

समझ में नहीं आता कि रेलवे मंत्री के मन में यह विचार कहा से आया है कि मान्यता-प्राप्त यूनियन के चयन के लिये गुप्त मतदान होना चाहिये। अन्य कई ऐसे मंत्रालय हैं जिनके अधीन भी सर-कारी उपक्रय हैं परन्तु रेल मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य मंत्री ने इस प्रकार के विचार व्यक्त नहीं किये हैं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर अभी विभिन्न स्तरों पर चर्चा हो रही है और इसके पश्चात् श्रम मंत्रालय द्वारा व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। स्वीकृत मान्यताओं के स्थान पर रेल मंत्री अपने स्वयं के विचारों को कार्यान्वित करना चाहते हैं। इसके गम्भीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। इससे औद्योगिक सम्बन्धों के क्षेत्र में अशान्ति उत्पन्न हो सकती है। अतः रेल मंत्री को इस विषय में श्रम मंत्रालय के परामर्श के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये।

जहां तक उपनगरीय रेल प्रणाली से आय का सम्बन्ध है बम्बई में उपनगरीय रेल व्यवस्था से सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है । माननीय मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि बम्बई उपनगरीय रेल यातायात में प्रति वर्ष 6 प्रतिशत न्यूनतम वृद्धि होती है। परन्तु इसके बावजूद रेलवे प्रशासन ने उपनगरीय रेलों में भीड़ कम करने की दृष्टि से कोई सुचारू कार्यवाही नहीं की है।

यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि इस सम्बन्ध में दिये गए सुझावों के प्रति रेलवे प्रशासन ने विशेष रुचि नहीं दिखाई है। रेलवे अभिसमय समिति ने 1973 में प्रस्तुत एक प्रतिवेदन में बम्बई उप-नगरों के लिये पश्चिम रेलवे सेक्शन के लिये 'रेपिड रेलवे ट्रांसिट सिस्टम' एक योजना प्रस्तुत की है। इस योजना को कार्यान्वित करने से दैनिक यात्रियों को 30 प्रतिशत समय की बचत होती। इस पर कोई अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की भी आवश्यकता नहीं और न ही वर्तमान तकनीकी प्रबन्धों में परिवर्तन की आव-श्यकता है परन्तु फिर भी रेलवे प्रशासन ने उसे रद्द कर दिया है। माननीय मंत्री को इस पर फिर से विचार

करना चाहिये। बम्बई उपनगरीय रेलवे यातायात सम्बन्धी अन्य समस्याएं हैं अधिक तथा तेज चलने वाली एवं शटल गाड़ियों की मांग। इन बातों की वर्षों से उपेक्षा की जा रही है। गत दो वर्षों में मध्य रेलवे ने बम्बई उपनगर सेवा में एक भी नई गाड़ी की वृद्धि नहीं की है। जबकि इस अवधि में यातायात में 15 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में कुछ संगठनों ने अच्छी सिफारिशें की हैं उन पर कार्यवाही की जानी चाहिये। जिससे कि बम्बई उपनगरीय यात्रियों को राहत मिल सके।

रेलवे ने रविवार के दिन स्थानीय गाड़ियों की संख्या घटा दी है जबकि गत 6-7 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में सातों दिन एक समान भीड़ रहती है। अतः रविवार को भी अन्य दिनों की ही भांति गाड़ियां चलाई जाये।

भूतपूर्व रेल मंत्री ने एक समिति गठित की थी। उसने अपनी एकमत सिफारिशें भी दी थीं। उनमें से मुख्य सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की गई है। अतः उन्हें भी क्रियान्वित किया जाए।

रेलवे का बम्बई के लोगों के जीवन से बहुत महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है। औद्योगिक कच्चे माल के परिवहन के लिये रेल वैगन नहीं मिलते। बम्बई में अनेकों निर्यात-प्रधान उद्योग स्थापित हैं। रेल वैगनों की कमी का उनके कार्यकरण पर प्रभाव पड रहा है जिससे निर्यात आदेश भी रद्द करने पड़ रहे हैं। अतः इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाए।

बम्बई में कुछ शरणार्थी 1947 में आए थे वह रेलवे में नौकरी करने लगे। तब से वे लोग कुरला यार्ड में ही रह रहे हैं। सारे देश में इस प्रकार के लोग जहां पर रहते थे उन स्थानों के मालिकाना अधिकार उन्हे दे दिये गए हैं। यह लोग भी मांग कर रहे कि जिन बैरकों व जमीन पर वे पिछले 25 साल से रह रहे हैं उसके मालिकाना हक उन्हे दिये जाएं पर रेलवे प्रशासन ने उनकी इस मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : रेलवे बजट में हमेशा रेलवे वित्तीय अवस्था का गलत चित्र प्रस्तुत किया जाता है। 1973-74 के बजट में 25 करोड़ रुपये के लाभ की आशा थी परन्तु अब वह 128 करोड़ के घाटे में परिवर्तित हो गया है। मेरा अनुरोध है कि भविष्य में रेलवे वित्तीय अवस्था का सही चित्रण बजट में प्रस्तुत किया जाये।

रेल मंत्री ने 1974-75 के बजट में माल ढुलाई में 250 लाख टन वृद्धि का अनुमान लगाया है परन्तु यदि हम बजट-पूर्व प्रस्तुत की गई आर्थिक समीक्षा को ध्यान पूर्वक पढ़े तो उससे इतनी अनुमानित वृद्धि सम्भव नहीं प्रतीत होती। अतः हम यह जानना चाहते हैं कि ये आंकड़े किन आधारों पर तैयार किये गए हैं।

रेलवे में आज अनुशासनहीनता बहुत अधिक बढ़ गई है। आए दिन हड़तालें एवं 'नियमानुसार कार्य' की घटनाएं हो रही हैं। इन का प्रभाव माल की ढुलाई पर पड़ रहा है। दूसरी ओर कर्मचारियों पर हो रहे व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इन स्थितियों में रेलवे बजट बहुत अव्यवहारिक प्रतीत होता है।

उड़ीसा में इस समय लगभग 2000 कि०मी० रेल लाइनें हैं। ये आंकड़े प्रति 1000 वर्ग कि०मी० पर 13 कि०मी० बैठते हैं जबकि राष्ट्रीय औसत 18.4 कि०मी० है। इसी प्रकार उड़ीसा में 1 लाख

जनसंख्या पर 8.6 कि०मी० लाइनें हैं जबकि अखिल भारतीय औसत 11.39 कि०मी० है। इस असमानता को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। राज्य में इस समय भी कई महत्त्वपूर्ण स्थानों का दिल्ली के साथ दैनिक सीधा सम्पर्क नहीं है। भुवनेश्वर से राउरेकला और भुवनेश्वर से दिल्ली के लिये कोई सीधी गाड़ी नहीं है। पुरी से दिल्ली के लिये एक सीधी दैनिक गाड़ी चलाई जानी चाहिये।

नई रेल लाईनों के निर्माण की दिशा में उड़ीसा के साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ है। यह ठीक है कि बांसवानी—जाखपुर रेल लाइन का निर्माण किया गया है। परन्तु राज्य सरकार ने बारबिल-कोइसवली और तालचेर-विमलगढ़ रेल लाईन के निर्माण का भी अनुरोध किया था जिससे राज्य के विपुल खनिज निक्षेपों का विदोहन हो सके। कटक-परादीप लाइन का समुचित उपयोग नहीं हो सकेगा, जब तक कि लाईन का जाखपुरा से धायत्री तक विस्तार नहीं किया गया। अतः इसे बढ़ाया जाए।

बजट में ब्रांच रेलवे लाइन के सुधार के लिये उपबन्ध किया गया है परन्तु उड़ीसा की ब्रांच लाईनों की उपेक्षा की गई है। राज्य में दो ब्रांच लाइनें हैं। 1959 में केन्द्र सरकार ने अलाभप्रद ब्रांच लाइनों का अध्ययन करने एवं उन्हें लाभप्रद बनाने के उपाय सुझाने के लिये एक समिति गठित की थी। राज्य सरकार ने समिति से अनुरोध किया कि इन दिनों लाइनों को ब्राड गेज में परिवर्तित किया जाए और नौपाडा—गुनापुर लाइन को शयर गाडा तथा रूपसा—तलबन्ध लाइन को शयरंगपुर तक बढ़ाया जाए। समिति ने नौपाडा गुनापुर सेक्शन पर गाड़ियों की नाते बढ़ाने की सिफारिश की। परन्तु इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। रायगाडा मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्र है। अतः इसके विस्तार के लिये विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिये।

रूपसा-तलबन्ध लाइन की यातायात सम्भावनाओं पर विचार करके समिति ने इसको ब्राड गेज में बदलने का सुझाव दिया था। परन्तु बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। डी०बी०के० लाईन कोशपुर ज़िले के अनेक महत्त्वपूर्ण नगरों से गुजरती है। इस लाईन को अनेक वर्ष पूर्व चालू किया गया था परन्तु अभी तक इसे माल व यात्री यातायात के लिये इस कारण से नहीं खोला गया कि इसका निर्माण किरनडोल से विजय नगरम् तक लौह अयस्क ले जाने के लिये किया गया था। स्थानीय लोगों को सेवा से वंचित रखने का यह एक अभूतपूर्व उदाहरण है। कोरापुट देश का सबसे बड़ा ज़िला है। इसकी औद्योगिक सम्भावनाएं बहुत व्यापक हैं परन्तु डी०बी०के० रेलवे के असहयोग के कारण इसका औद्योगिकीकरण नहीं हो पा रहा। अतः मेरा अनुरोध है कि इस लाइन को माल तथा यात्री यातायात के लिये खोला जाये जिससे राज्य के इस पिछड़े ज़िले के विकास को बल मिले।

यह बहुत ही दुख की बात है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे के मुख्यालय को कलकत्ता से उड़ीसा स्थानान्तरित करने की मांग पर रेल मंत्रालय से निष्पक्षता से विचार नहीं किया। श्री हनुमन्तैया ने भुवनेश्वर में रेलवे सेवा आयोग का कार्यालय खोलने की मांग मान ली थी परन्तु फिर भी अभी तक उड़ीसा में रेलवे सेवा आयोग स्थापित नहीं किया गया है।

Shri Ram Shekhar Prasad Singh (Chapra) : Since the taking over of Railways by the Present Railway Minister, incidents of strikes, work-to-rule, no work etc. agitations have been taking place. The number of accidents has also all of a sudden increased. But the Railway Minister deserves praise for the way he has tried to do different works. Construction of new rail lines, re-opening of dead and old, abandoned rail lines, introduction of new trains, are such works for which he is being praised by the public.

The demand for opening a Railway Service Commission in Bihar was being raised since 1962. But it has been conceded only now.

There was vide-spread shortage of food-grains all over the country to the month of May. The Railway Minister conducted the rail department in such a manner that food-grains could be moved to different parts of the country from Haryana, Punjab and U.P.

Indian Railways are the greatest means of communication in the country. The Railways are devided in different Zones and Divisions . The Divisional system in N.F. and N.E. Railway was introduced from 1st May, 1969 and in all other Railway it existed prior to that date. It is time to review the system.

In N.F. Rly. all the five Districts have new Divisional offices.

In N.E. Railway Sonepur is still a district office, it may also be converted into a Divisional office. N.E. Railway has approximately 5 thousand Kilometers of Railway and has four Divisional offices where as N.F. Railway has only 3 thousands Kilometer of Railway line but has 5 Divisional offices. It has now become necessary to establish one more Division between Varanasi and Samstipur. Sonepur may be converted into a Divisional office. It has its historical importance and there are about 900 guarters which can be utilised. An announcement for the formation of a Divisional office in Sonepur was made by Lalit Babu on the bank of Ganga. That assurance may be met now.

The Railway Minister assured during last budget for allotment of book stalls. etc. to the educated unemployed. But this category of unemployed persons has not been provided with sufficient avenues of earning. No policy has been devided in this regard. No circular has been issued for giving preference to unemployed graduates and Harijans. The hon. Minister should announce a definite policy in this regard.

There is crores of acres of land under unauthorised occupation. I wrote to the honourable Minister against such occupation of land in Chapra but in spite of his interference it has not been checked.

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : मुझे खेद है कि दक्षिण रेलवे में कोई नयी परियोजना 1974–75 के बजट में नहीं रखी हैं। तमिलनाडु की जनता ने बहुत सी रेलवे योजनाओं तथा मद्रास नगर में ट्यूब रेलवे आदि की मांग की है।

एक तारांकित प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट हो जाता है कि पांचवीं योजना में दक्षिण रेलवे की कोई योजना सम्मिलित नहीं की गई। मेरा सुझाव है कि दक्षिण रेलवे की कुछ परियोजनाओं को पांचवीं योजना में सम्मिलित किया जाये।

14 लाख रेल कर्मचारियों के लिये अस्पतालों में केवल 10467 बिस्तर हैं।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised translated version of English translation of speech delivered in Tamil

प्रतिदिन 67.9 लाख लोग प्रतिदिन 108.00 गाड़ियों में यात्रा करते हैं जिनमें से 67.9 लाख तृतीय श्रेणी में होते हैं।

25 वर्ष की स्वतंत्रता के पश्चात भी 7098 में से 2598 रेलवे स्टेशनों में बिजली नहीं है और 6198 में पानी के कूलर नहीं हैं। रेलवे का राजस्व बढ़ने के बावजूद चिकित्सा सुविधायें उसी अनुपात से नहीं बढ़ रही हैं।

प्रस्तावित भाड़ों में वृद्धि से जनता का जीवन निर्वाह व्यय बढ़ेगा। क्या रेलवे मंत्री यथासंभव भाड़े में कमी करेंगे। 1969 से 1974 तक सामान के चोरी आदि होने के कारण रेलवे को प्रतिवर्ष लगभग 11 से 13 करोड़ रुपये की क्षति उठानी पड़ती है। भूतपूर्व रेलवे मंत्री श्री हनुमंतैया ने कांग्रेस संसदीय पार्टी में बताया था कि रेलवे की वस्तुओं के खराब होने तथा चोरी होने के कारण 100 करोड़ रुपये वार्षिक की हानि उठानी पड़ी। दूसरी ओर रेलवे कर्मचारियों की 8.33 प्रतिशत बोनस की मांग धनाभाव के कारण ठुकरा दी जाती है। 1969–73 तक 7.97 करोड़ रुपये का सामान मार्ग में चोरी हुआ जिसमें से 78.97 लाख रुपये का सामान बरामद किया गया जोकि खोये माल का 10 प्रतिशत है। उक्त अवधि में 520 हत्याएं तथा 2347 डकैतियां हुई। यह स्पष्ट है कि रेलवे मंत्री यात्रियों की जान माल की रक्षा के लिये प्रभावी कार्यवाही करने में विफल रहे हैं।

लाखों ऐसे फाटक हैं जहां पर कर्मचारी नियुक्त नहीं होता है जिसके कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हाल ही में कई दुर्घटनाएं घटी हैं। रेलवे मंत्री को मनुष्यों के जीवनों की सुरक्षा के लिये कार्यवाही करनी चाहिए।

शासक दल के भी कई सदस्यों ने भी रेलवे बोर्ड के भंग किये जाने की मांग की है। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक ने भी रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन का आग्रह किया है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता रेलवे की 2500 करोड़ रुपये की पंच वर्षीय योजना सफलता से क्रियान्वित नहीं की जा सकती।

मेरा निवेदन है कि रेलवे बोर्ड की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाये तथा सलेम इस्पात संयंत्र के लिये 13 किलोमीटर रेलवे लाइन के निर्माण की मंजूरी दी जाये :

श्री के० राम कृष्णन रेड्डी : (नलगोंडा) : रेलवे बजट का स्वागत करते हुए बीबीनगर से नदीकुडे रेलवे लाइन के निर्माण तथा मधरली गंटूर रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने के प्रस्तावों के लिये मैं रेलवे मंत्री को धन्यवाद देता हूं। नलगोंदा जिले में पिछड़े क्षेत्रों से गुजरने वाली यह पहली लाइन होगी।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए।

MR. DINESH CHANDER GOSWAMI in the chair.

जब निजाम रेलवे भारतीय रेलवे में विलीन की गई थी तो उसके 6 करोड़ रूपये को भूतपूर्व हैदराबाद राज्य में नयी रेलवे लाइन पर लगाने का आश्वासन दिया गया था। यदि अधिक नहीं तो उन्हें कम से कम 6 करोड़ रुपये की इस फालतू धनराशि को जो उन्हें निजाम रेलवे से प्राप्त हुई थी। बीबनगर से नाडीकुड़े तक रेलवे लाइन बिछाने के लिये रखना चाहिये था। रेल मंत्री को सभा की अनुमति प्राप्त करके इस राशि को बजट में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह रेलवे लाइन बडापल्ली के निकट कृष्णा नदी के पार जायेगी। अतः वहां पर एक रेल पुल भी बनाना होगा। यदि इसे सड़क एवं रेल पुल के रूप में बनाया जाये तो इस क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ पहुंचेगा। इस का 50 प्रति-

शत व्यय रेलवे विभाग करेगा और 50 प्रतिशत आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार करेगी। मुझे आशा है कि राज्य सरकार ऐसा करने में संकोच नहीं करेगी –

हैदराबाद और सिकन्दराबाद आन्ध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण नगर हैं परन्तु राजधानी से केवल हैदराबाद जाने वाली कोई सीधी रेल गाड़ी नहीं है। केवल दक्षिण एक्सप्रेस है और उस में भी मद्रास के डिब्बे लगे होते हैं। अतः वह भी एक लिंक एक्सप्रेस है। सिकन्दराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है और हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश की राजधानी है। अतः एक एक्सप्रेस गाड़ी जो दक्षिण एक्सप्रेस से भी तेज हो, दिल्ली से हैदराबाद तक चलाई जानी चाहिए। यह गाड़ी 4 बजे शाम के बाद दिल्ली से चलनी चाहिये और 10 बजे रात तक हैदराबाद या सिकन्दराबाद पहुंच जानी चाहिये जिस से इस यात्रा में दो रातें गाड़ी में सोना न पड़े। इस समस्या पर तुरन्त ध्यान देना चाहिये और सभी संबंधित लोगों को रेलगाड़ियों के समय में समायोजन करने के लिये निदेश देने चाहियें।

वातानुकूलित दर्जे का किराया दुगना किया जा रहा है। संसद सदस्यों तथा उनके परिवारों को बिना और किराये दिये वातानूकूलित दर्जे में यात्रा करने की अनुमति होनी चाहिये। स्लीपर की व्यवस्था करने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। रात के समय यात्रा करने वाले यात्रियों को स्वतः स्लीपर मिल जाना चाहिये। मेरा एक सुझाव यह भी है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ियां डीजल की बजाये बिजली से चलाई जानी चाहियें।

हैदराबाद और सिकन्दराबाद, दोनों नगरों की जनता की मांग पूरी करने हेतु नानपल्ली से फालरवाना और सिकन्दराबाद से नानपल्ली तक गोलाकार बड़ी रेल लाइन की व्यवस्था की जानी चाहिये।

करीमनगर जिले से हो कर सिकन्दराबाद से वरधा तक चलने वाली रेलवे लाइन का सर्वेक्षण किया गया था। यह रेल गाड़ी निकटवर्ती रामगुन्डम औद्योगिक क्षेत्र से भी हो कर जायेगी। इस पर शीघ्र ध्यान देना चाहियें और इसकी मंजूरी शीघ्र दी जानी चाहिये।

प्रत्येक जोन के लिये पृथक रेलवे लोक सेवा आयोग होना चाहिये। अब, केरल, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिये मद्रास जाना पड़ता है जोकि बहुत ही असुविधाजनक है। अतः पृथक पृथक रेलवे लोक सेवा आयोग बनाये जाने चाहिये।

Shri Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : An over head bridge should be constructed on level crossing in Jamshedpur. This level crossing is insufficient in meeting the requirements of increased traffic. The work of P.W.I. or Engineers should be properly checked because it has been observed that many accidents could be avoided but for their slackness.

The Government have revised the cost of the platform ticket to Rs. 0.50 P. but the minimum ticket would cost Rs. 0.30 P. It should have been uniform. The corruption at all levels is rampant in Railways. The hon'ble Minister should look into this aspect. I have read in the newspapers today that there will be grand auction tomorrow This one day notice is hardly sufficient for auction. The Railways will have to dispose of these things at threw away prices. They should sell non-ferrous metals to small scale industries. The traders purchase the material at threw away prices and sell to the re-rollers and earn big profit. The Railways should sell this scrap straight to the re-rollers.

The compensation being given to the victims of Railway accidents should be raised from Rs. 50,000 to Rs. 1 lakh. There should be greater cooperation between Railways and Ministry of Steel and Mines to avoid heavy losses. It should be on solid footing and not on paper only. Railway Board should not be abolished. Government should adotp tough line and take work from them. It should be reorganised.

There are two forces *viz.* G.R.P. and R.P.F. being maintained by Railways. They should maintain only one force because none of them own the responsibility to check the pilferage. They just put off the responsibility. The Railway should stop leakage and plug the holes instead of increasing the fares of III class.

The Railways should introduce a direct train from Tata Nagar to Delhi. I wo uld like to suggest that Adra division should be bypassed by South Bihar Express because it is troubled area. The train should be introduced from Bihar to Bihar *via* Gaya, Gamoh, Ranchi, Muri and Tatanagar.

The sick wagon should be got examined in Delhi. It has been observed that wagons are declared sick on flingy grounds. Special attention should be paid towards maintenance aspect.

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : इस बजट में रेलवे के किरायों और माल भाड़े में वृद्धि करके रेलवे के राजस्व में वृद्धि करने का काफी प्रयत्न किया गया है। परन्तु इसके बावजूद 52 करोड़ रुपये का धाटा दिखाया गया है। मुझे इस बात में संदेह है कि वह घाटा 52 करोड़ रुपये तक ही सीमित रह सकेगा। जब आगामी वर्ष के लिये बजट प्रस्तुत किया जायेगा तब यह घाटा 150 करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगा।

यह अनुमान लगाया गया है कि 2170 लाख टन माल ढोया जायेगा। परन्तु यदि इसमें से 170 लाख टन माल कम ढोया गया तो रेलवे की आय में 68 करोड़ रुपये की कमी हो जायेगी। ऐसा न हो तो ठीक है परन्तु गत वर्ष से पता चलता है कि इस प्रकार की स्थिति होती है। प्रस्तावित आय से 50 करोड़ से कम की हानि नहीं होगी और इस के परिणामस्वरूप उक्त घाटा 102 करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगा। फिर किरायों में और माल भाड़े में वृद्धि के कारण वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि होगी और रेल मंत्री कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते में वृद्धि को रोक नहीं पायेंगे। इसके परिणामस्वरूप घाटा और बढ़ेगा जो 150 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा। यदि रेलवे के प्रशासन कुशलता और अनेक तरीकों से रेलवे के कार्यकरण में सुधार करके यदि इस घाटे को कम किया जा सके तो बड़ी अच्छी बात होगी। रेलवे को आधुनिक प्रौद्योगिकी अथवा विज्ञान का उपयोग करना चाहिये। रेलवे का एक आर० डी० एस० ओ० विभाग है। क्या उसने कोई उपयोगी कार्य किया है। मेरे विचार में उनके क्रिया-कलाप और उपलब्धियां संतोषजनक नहीं हैं। अतः इस संगठन में प्रतिभाशाली वैज्ञानिक नियतन किये जाने चाहियें जो रेलवे प्रशासन को नयी दशा दें। एक नौजवान इंजीनियर ने माइक्रो मिनिमम राडार नाम की मशीन का आविश्कार किया था जिस के प्रयोग से रेल दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था और उससे रेलवे प्रशासन में सुधार हो सकता था। परन्तु दुर्भाग्य से इस मशीन की उचित जांच नहीं की गई। यदि यह मशीन काम की नहीं थी तो उस में रेलवे के इंजीनियर सुधार कर सकते थे परन्तु उन्हें इस प्रकार के युवक इंजीनियरों के उत्साह को कम नहीं करना चाहिये। मंत्री महोदय को इस सबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

वर्ष 1960–61 में रेलवे वैंगनों की संख्या 3,07,900 थी और उनमें 5562 लाख टन माल ढोया गया था। वर्ष 1972–73 में उन की संख्या 3,84,283 थी और उन में केवल 2013 लाख टन माल ढोया गया। अतः इस में प्रति वर्ष कमी होती जा रही है। आर० बी० लाल जांच समिति ने भी कहा था कि वैगनों की आवाजाही दोषपूर्ण है और कुछ उपाय किये जाने चाहियें। क्या मंत्री महोदय इन अस्तव्यस्त पड़े वेगनों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में विचार करेंगे ? यदि रेलवे के सभी डिबीजनों में प्रयोग में ना लाये जाने वाले ऐसे वैगनों की संख्या का हिसाब लगाया जाये तो वह 15000–20,000 के लगभग होगी जिससे प्रतिदिन 30 लाख रुपये की हानि हो रही है। रेलवे के राजस्व में सुधार करने के लिये इस पहलू पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। वैंगनों के उचित प्रयोग के लिये श्री चौधरी नामक किसी व्यक्ति ने एक मशीन का आविष्कार किया है। रेल मंत्रालय को इस मशीन की जांच करवानी चाहिये।

रेलवे सुरक्षा दल के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और उनसे इन रक्षकों को भक्षक बताया गया है। इन शिकायतों में इनको रेलवे में चोरी के लिए जिम्मेदार बताया गया है। अतः इस मामले की भी जांच की जानी चाहिये।

अन्त में मैं रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि सीमान्त रेलवे पर न्यू मैनागुडी से सीताई तक एक नई रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिये जिसकी लम्बाई लगभग 80-85 किलोमीटर होगी। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये यह लाइन अत्यन्त आवश्यक है।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं इस बजट का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि वह लाइट रेलवे को पुनः चालू करने पर विचार कर रहे हैं जब कि उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि हावड़ा आमता लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जायेगा और एक रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। परन्तु आज फिर यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि पुरानी लाइट रेलवे चालू होने वाली है। मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री हमें सही सही जानकारी दें।

इस समय गार्ड नियमानुसार कार्य कर रहें हैं। परन्तु इससे पहले उत्तर सीमान्त रेलवे पर कुछ रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। 600 से अधिक कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया गया है। आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी कानून के अधीन गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। उनका दोष केवल इतना है कि वे 10 घण्टे की ड्यूटी को क्रियान्वित करवाना चाहते हैं। सभा को पता है कि लोको कर्मचारियों की यह एक मुख्य मांग थी कि उनकी ड्यूटी घण्टे, जो अब 12 से 20 घण्टे तक है, कम किये जाने चाहियें। गत अगस्त में इस संबंध में समझौता हो गया था और इस में स्पष्ट किया गया था कि 6 सप्ताह में इस प्रणाली को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। वस्तुतः रेलवे बोर्ड के दफ्तरशाह इस व्यवस्था को लागू नहीं करना चाहते। गत दिसम्बर से उत्तर सीमान्त रेलवे में पूर्ण शांति थी और वहां कोई हड़ताल नहीं हुई थी। उत्तर सीमान्त रेलवे के महा प्रबंधक से समझौता हो गया था कि वहां पर 10 घण्टे की ड्यूटी वाली प्रणाली शांतिपूर्ण ढंग से लागू कर दी जायेगी। परन्तु अब वह अपने वचन को पूरा नहीं कर रहे और लोको कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी आरम्भ कर दी है। इसी लिये बड़े पैमाने पर गिरफतारियां, मुअत्तलियां और दंड के रूप में स्थानान्तरण किये जा रहे हैं। ऐसा करने से स्थिति और भी बिगड़ जायेगी।

यदि रवैया ऐसा है तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि रेलवे प्रशासन दस घंटे की ड्यूटी को क्रियान्वित करना चाहता हैं।

शिकायतों संबंधी समिति के सदस्यों श्री डी० बी० भौरा ने समिति की बैठक में कहा था कि हावड़ा डिवीजन में 10 घंटे की ड्यूटी को क्रियान्वित करना कठिन नहीं होगा लेकिन लोको-मैन के प्रतिनिधि-मंडल से उन्होंने इस बात से बिल्कुल इनकार किया।

गत दिसम्बर के बाद यह आशा की गयी थी कि लोको रनिंग स्टाफ एस्सोएियेशन को सभी स्तरों पर अपनी शिकायतें पेश करने का अधिकार मिलेगा। लेकिन उत्तर सीमांत रेलवे के लोको एस्सोशियेशन के जनरल मेनेजर से दस घंटे की ड्यूटी के बारे में बातचीत करने का अधिकार नहीं दिया गया। यह समझौते का उल्लंधन करने का एक ज्वलंत उदाहरण है। स्पष्ट आश्वासन तथा समझौता होने के बावजूद भी रेलवे प्रशासन समझौते को क्रियान्वित करने से इनकार कर रहा है। रेलवे कर्मचारियों ने आठ घंटे की ड्यूटी, बातचीत के अधिकार आदि की मांग की है। सरकार को इन मांगों के 10 अप्रैल, 74 से पहले पहले पूरा करने का नोटिस दिया है जिसके बाद, मांगे पूरी न होने पर, रेलवे कर्मचारी देश भर में हड़ताल अथवा आन्दोलन करने के लिये उतारू हो जायेंगे। सरकार को पिछले अनुभवों से भी कुछ सीखना चाहिये। स्थिति के बिगड़ने से पहले ही कुछ करना चाहिये। सरकार को जन विरोधी नीतियां त्यागनी चाहियें अन्यथा स्थिति बिगड़ जायेगी।

श्री ए० के० एम इसहाक (बसिरहाट) : पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नाम का एक क्षेत्र है जिसमें सचमुच सुंदर जगल है। इस सारे क्षेत्र में कृषि की जा सकती है। सारे सुंदरबन में केवल एक ही फसल होती है जबकि वहां तीन फसलें पैदा की जा सकती हैं। यदि इस समूचे क्षेत्र को कृषि के अधीन लाया जाये तो पश्चिम बंगाल अन्न के मामले में कमी का राज्य नहीं रहेगा।

इस क्षेत्र में मुर्गीपालन की भी बहुत अच्छी संभावनायें हैं लेकिन आवागमन के साधनों के अभाव में यह भी असंभव है। कपास भी इस क्षेत्र में पैदा की जा सकती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है।

रेल मंत्री महोदय को सुंदरबन विकास बोर्ड ने चार रेल लाइनें बिछाने संबंधी प्रस्ताव भेजे थे। इन चार लाइनों की लम्बाई 60 मील होगी। इन लाइनों के बनने पर पश्चिम बंगाल घाटे का राज्य न रहेगा।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है जिसमें हसनाबाद से बारसाट तक केवल 14 मील की एक रेल लाइन है। हसनाबाद सियालदह से 30,35 किलोमीटर दूर है। मैं यह अनुरोध करता आ रहा हूं कि हसनाबाद तथा सियालदह के बीच सीधी लाइन होनी चाहिये। मैं अब भी रेल मंत्री से यही अपील करता हूं।

जफौरपुर में एक नया स्टेशन खोलने के बारे में मैंने एक प्रस्ताव भेजा था। मैं फिर से उन से इस स्टेशन को शीध्र स्थापित करने के लिये अपील करूंगा।

मार्टिन रेलवेज को बंद कर दिया गया है लेकिन इसी सदन में तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा इसके कर्मचारियों को खपाने के बारे में दिये गये आश्वासन के बावजूद भी अब तक इस रेलवे के कर्मचारियों को खपाया नहीं गया है। मेरा अनुरोध है कि आश्वासन को पूरा किया जाये तथा इन कर्मचारियों को खपाया जाये।

बजट के घाटे को पूरा करने के लिये सरकार ने रेलों के किरायें तथा भाड़े बढ़ाये हैं इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम अपने वैगनों का पूरा उपयोग कर रहे हैं ? इस बात का पता लगाया जाये कि पूरे वैगनों का उपयोग करने से हमें कितना लाभ होता ।

रेलवे में चोरी तथा उठाईगिरी को रोकने के लिये हम ने रेलवे सुरक्षा दल बनाया हैं। इस दल पर 13 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय होता है जबकि हमें 36 करोड़ रुपये की क्षति पूरी करनी पड़ती है। इस स्थिति में मैं पूछना चाहता हूं कि रेलवे सुरक्षा बल पर व्यय करने से हमें क्या लाभ प्राप्त हुआ ? मंत्री महोदय को इस प्रश्न की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ?

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे सुझावों की ओर ध्यान दें।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे (सांगली) : पांचवीं योजना में रेलवे के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। रेल मंत्री ने गत वर्ष के बजट में पिछड़े क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के मन में नयी आकांक्षायें पैदा की थी। इस वर्ष भी इन्होंने ऐसा ही किया है । इस वर्ष के बजट में मिराज-लेटूर लाइन को ब्राड गेज में बदलने का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस लाइन के काम को शुरू भी किया जायेगा अथवा नहीं ? मेरे विचार में रेलवे बोर्ड इस कार्य को पांचवीं पंच-वर्षीय योजना की सारी अवधि में भी शुरु नहीं कर सकेगा। क्योंकि पृष्ट 13 पर 12 अन्य लाइनों का उल्लेख किया गया है।

किराये, भाड़े आदि में वृद्धि से सरकार को प्रतिवर्ष 106 करोड़ रुपये की आय होगी। कहा जाता है कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फलस्वरूप रेलवे कर्मचारियों पर प्रति-वर्ष लगभग करोड़ 100 रुपये अधिक व्यय होंगे जो दूसरे शब्दों में यात्रियों से अधिक किराया ले कर पूरा किया जायेगा।

मेरा सुझाव है कि 25 किलोमीटर के लिये 5 पैसे अधिक किराया लेना बंद किया जाये। प्लेटफार्म टिकट भी 50 पैसे के स्थान पर 25 पैसे होना चाहिये।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि व्हील और एग्जल का एक संयंत्र मिराज में भी स्थापित किया जाना चाहिये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र मिराज में सितार बनाते हैं और उन्हें रेल द्वारा बाहर भेजने पर बहुत व्यय आता है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें तथा ऐसी व्यवस्था करें जिससे सितार निर्माताओं को सितार बाहर भेजने पर अधिक पैसा न देना पड़े।

Shri C.D. Gautam (Balaghat): Sir, a large quantity of coper deposits have been found in the district of Balaghat in Madhya Pradesh. In this context I would like to suggest that a railway line should be constructed connecting Balaghat and Bharvaily where big mines are situated. It would also transport forest products of the area.

Jabalpur-Gondia and Gondia—Chandrapur narrow gauge lines should be converted: into broad gauge lines to provide direct link from Northern India to Southern India. Similarly narrow gauge railway lines between Jabalpur and Nayanpur, Shivani Chhindwara Nagpur should be converted into broad gauge lines.

I also suggest that Utkal Express should be made daily service to facilitate the passengers from Bihar, Orissa and Madhya Pradesh. It is a long standing demand of the people of Balaghat that a new railway line should be constructed from Katangi to Tirodi, a distance of eight miles only.

Bamboo is an important produce of our area. But adequate railway wagons are not provided by the Railway Board for transportation of this product resulting in heavy loss to the people.

Regarding the Headquarters of South Eastern Railway I suggest that it should be transferred from Nagpur to a central place like Bilaspur or Raipur.

It has been observed that there is large scale corruption in Railways in shape of pilferage, ticketless travel and misappropriation by the railway employees like booking clerks ticket collector, etc. I request that hon. Minister should look into all theses matters.

Trains running on Jabalpur-Gondia lines do not stop at Hatta Road station in the night resulting in great inconvenience especially to the students, milk-men and government employees. This difficulty should be removed.

I also suggest that an over bridge should be constructed at level-crossing near Sarekha. I received a letter from the ex-minister of Railways conveying the sanction of the Central Government for the bridge. I request that this project should be taken up soon.

दर्शकों को संसद सदस्यों से मिलने से रोकने के बारे में

Re : Alleged Prevention of visitors from meeting Members of Parliament

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Sir, I want to raise an important matter under rule 340 and request that this debate should be adjourned for a while.

सभापति महोदय : मुझे आप का नोटिस मिल गया है। यह मामला नियम 340 के अन्तर्गत नहीं आता। तथापि आप के नोटिस में उल्लिखित मामला निश्चत रूप से ही गंभीर है। इस मामले में अध्यक्ष महोदय जांच करना चाहते हैं। जांच के बाद आप को इस बारे में बता दिया जायेगा। मैं आप को कुछ मिनट दे सकता हूं। चर्चा स्थगित नहीं होगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Certain students from Gujarat wanted to see members of Parliament and they sent chits in my name. But the security staff did not deliver those chits to me thus depriving them of the opportunity to meet me. It resulted in clash between the security staff and the students.

I think visitors are allowed to see Members of Parliament and security staff have no right to withhold the chits of visitors. It is a serious matter and I have given a notice of privilege motion. It is not a party matter.

सभापति महोदय : निश्चित ही यह गंभीर मामला है तथा उसकी पूरी पूरी जांच की जायेगी।

रेलवे बजट 1974-75 सामान्य चर्चा—जारी

Railway Budget 1974-75, General discussion—Contd.

Shri Ram Bhagat Paswan (Rosera): At the outset I would like to Congratulate the hon. Minister for his efforts to develop the most undeveloped regions of the country. He has sanctioned the construction of Sakari-Hasanpur and Lokaha-Jhanjharpur railway lines which would be of great importance for this backward area. Other lines would

play an important role in the development of agriculture and trade and the construction work on these lines would provide employment to the large number of poor people.

In view of the fact that Rasara has a sub-Divisional Headquarters and other institutions like college, Hospital and Courts, I suggest that all the fast trains especially 'G.L.' train should stop at the station. An assurance was also received from the hon. Minister to this effect but it has not yet been implemented.

I also demand a new railway station at Simariya Ghat so that lakhs of the passengers are not required to walk a distance of four miles to purchase their tickets. A direct train between Darbhanga and Baijnath Dham should also be introduced. The proposed Samastipur-Jaynagar broad gauge line should be taken up immediately to facilitate the people of backward area.

I also invite the attention of the hon. Minister to the irregularities in the appointment of Scheduled Caste and Scheduled Tribe people in class IV and Class I posts. I request the hon. Minister that the reserved quota of posts in the categories should be given to S.C/T.C. candidates in full. He should take special interest in this regard.

The hon. Minister must be aware of the pitiable condition of the casual labour in the Railways. I suggest that minimum wage must not be less than Rs. 5 or Rs. 7 in these hard days of price rise.

It has been observed that late running of trains on North-Eastern and Eastern Railways has become perpetual. The hon. Minister should ensure punctuality in this regard. I am sorry to comment that some railway employees and officers engage themselves in strikes disregarding public interests. In this context I suggest that trade unions formed on political background should be derecognised.

I also suggest that instead of having two forces, R.P.F. and G.R.P., there should be only one force in Railways. Personnel of Railway Force should be under the control of the Station Masters so that their services are utilised at proper times and effectively.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : रेलवे की आय में कमी के बारे में जनता में कुछ प्रश्न उठे हैं जिनका मंत्री महोदय को संतोषजनक उत्तर देना चाहिये । मैं रेल मंत्रालय तथा रेलवे बोर्ड पर यह आरोप लगाता हूं कि उन्होंने बड़े व्यापारियों और उद्योगों को जानबूझ कर अधिक रियायतें दी हैं तथा उनसे साइडिंग चार्ज पूरी तरह वसूल नहीं किये । दक्षिण-पूर्व रेलवे में कई उद्योगपतियों से लाखों रुपयों की राशि वर्षों से वसूल नहीं की । इसके क्या कारण हैं ?

इसी प्रकार विलम्ब शुल्क का प्रश्न है । सर्वविदित है कि कलकत्ता शालीमार यार्ड में पूजा के समय माल डिब्बे भरे हुए खडे रहते हैं तथा व्यापारी उनको बहुत दिनो तक खाली नहीं कराते । मैं जानना चाहता हूं कि विलम्ब शुल्क की कितनी राशि वसूल की गई है । इस वर्ष जनवरी और फरवरी के महीनों में जूट मिलों को 1750 माल डिब्बे अलाट किये गये जो लगभग 5-6 सप्ताह तक हावड़ा और शालीमार में बेकार खड़े रहे । इसका विलम्ब शुल्क कितना अधिक होगा । क्या यह शुल्क वसूल किया गया है ।

जहां तक रेल भाड़े की दरों का संबंध है उनका निर्धारण व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं किया गया। यह सच है कि रेल उद्योग जन उद्योग है तथा उस का ध्येय जनता की सेवा करना है। खाद्यान्न जैसी वस्तुओं के भाड़े की दरों को भी उचित माना जा सकता है । किन्तु कोयला तथा अन्य कच्चे माल जैसी वस्तुओं के भाड़े का संबंध है उन की दरें बहुत कम रखने में कोई औचित्य नहीं है। बांस का भाड़ा भी बहुत कम रखा गया है यद्यपि यह कागज मिलों के लिये कच्चा माल है जिसे बिड़ला जैसे उद्योगपति मगांते हैं अतः भारत सरकार की भाड़े की दरें तथा इससे संबंधित नीति अत्यन्त दोषपूर्ण है तथा इन्ही कारणों से रेलवे को घाटा होता है।

यह सच है कि रेलवे में हड़ताल के कारण जनता को कठिनाई होती है तथा रेल यातायात ग्रस्त-व्यस्त होता है। किन्तु सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिये क्या ठोस कदम उठाये हैं ? श्री एल० एन० मिश्र ने 27 जनवरी को रेलवे कर्मचारियों की फैडेरशन तथा अन्य यूनियनों को बुलाकर उनके साथ बात-चीत की थी। मैं जानना चाहता हूं कि उसमें क्या निर्णय किया गया।

मंत्री महोदय ने रेलवे में एक फैडरेशन बनाने की बात कही है। मेरे विचार में इस स्थिति में जब वहां कई यूनियनें विद्यमान हैं गुप्त मतदान द्वारा एक यूनियन बनाये जाने का कार्य व्यवहार्य नहीं है। इससे समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सकता। क्या मंत्री महोदय ने यह प्रयत्न करने का विचार किया है कि रेलवे में विद्यमान सभी यूनियनों तथा सभी श्रेणियों की यूनियनों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व करने वाली एक फैडरेशन बनाई जाए जिसमें किसी राजनैतिक पार्टी का कोई प्रभुत्व न हो ?

आल इणिडया रेलवे मैन फैडरेशन जैसी संस्था को भी, जैसा कि श्री कुरेशी को ज्ञात होगा, कुछ गैर-मान्यता प्राप्त संस्थाओं के साथ मिल कर एक संयुक्त कमेटी बनानी पड़ी है क्योंकि उसे ज्ञात था कि गैर मान्यता प्राप्त होने पर भी यह संस्थाएं कई श्रेणियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उक्त कमैटी ने पांच मांग की हैं तथा कहा है कि यदि रेलवे बोर्ड 10 अप्रैल तक उन के साथ बात-चीत नहीं करेगा तो वे कोई कार्यवाही करने को स्वतंत्र है।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ? क्या सरकार वही पुराना रवैया अपनाएगी कि गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों से बात-चीत नहीं करनी ? मेरे विचार में इस प्रकार देशव्यापी आन्दोलनों को नहीं रोका जा सकता। मेरा अनुरोध है कि सरकार यह रवैया त्याग कर बात-चीत के माध्यम से सभी समस्याओं को ही सुलझाने का प्रत्यन करें।

Shri Chandulal Chandrakar (Durg): In spite of the fact that we have the second largest railway system in the world, our railways have been running in a loss. This is a matter which has to be carefully considered. Some of the reasons for the deficit in railway earnings are poor maintenance, increasing pilferage and thefts and the poor conditions of railway wagons which are again due to bad maintenance. These matters should be looked into by the hon. Minister.

I would like to suggest that efforts should be made to see whether it is possible to have only one union on the Railways. In 1953-54 our present President, Shri Giri, when he was the Labour minister, succeeded in having a single union in Railways. The hon. minister should evolve certain measure on the lines. I think the system of secret ballot would not be of any use. Government should have some negotiations for this purpose.

So far as the development of backward areas are concerned Government have repeatedly said that new railway lines would be laid in the backward areas but they have not made much progress in this regard. The most backward areas are being neglected in this matter. There is no railway line in the district of Bastar. The number of railway lines is very few in Surguja and Raigarh also. I request that the Government should earnestly take up the matter of laying new railway lines in these backward areas.

The survey for constructing the railway line between Dalla-Rajhara and Bailadilla has been completed but the line has not been laid as yet. I request that this line should be completed without any further delay.

In spite of the fact that the State Reorganisation Commission have recommended to the Central Government to pay special attention to the development of Madhya Pradesh which is full of mines. This state is the most neglected one. There is no direct and fast train available for the people of Chhatisgarh to come to Delhi or Bhopal. I, therefore, demand that a direct and fast train from Durg or Raipur to Delhi *via* Nagpur and Bhopal should be introduced as soon as possible.

I also invite the attention of the hon. minister to the fact that the representation of the people of Madhya Pradesh in railway services is negligible. The main reason of it is that is not any office of Railway Service Commission of South-Eastern Railway in Madhy Pradesh. I suggest that an office of the Railway Service Commission of this Railway should be set up at Bilaspur or Raipur for providing employment opportunities to the local people.

All the trains in this area run regularly late. Chakradharpur-Nagpur passanger train has never been punctual throughout the year. It should be checked.

The decision taken during the First Five Year Plan regarding the continuance of only broad gauge and metre gauge lines has not been implemented so far. I suggest that a commission should be appointed to decide whether there should be only two types of the railway lines in the country.

I also suggest that the 50 per cent promotions in the Railways should be made from rank and file always. Saloon system should be abolished. The practice to engage Khalisi in domestic work by officers should be curbed immedialtely.

The rate of 50 rupees per acre charged from the Railway employees for the land beside the railway track is on the high side. It should be Rs. 10 per acre. I also demand that all the railway codes should be translated in Hindi and in other Indian languages.

Government should introduce flying squad system in Railway also to check the running staff and to ensure that no one is on duty under intoxication. It would help in minimising the cases of accidents.

The increase in railway rate of platform ticket and fares for passenger trains upto 50 kilometres is not justified. This increase should be withdrawn.

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur): Despite the difficulties and financial strains during the last year, the Minister of Railways has drawn up schemes for certain new works to be executed during the coming years.

The Public Relations Organisation in the Railways should be competent enough to educate the people not to destroy the properties of the Railways.

The work relating to the conversion of metre gauge lines into broad gauge should be taken up first in the backward areas.

The Ayurvedic and Unani systems of Medicine should be encourged in the hospital in the Railways.

The amount of Rs. 4 crores earmarked for providing amenities to passengers should be enhanced.

If demurrage is realised in a strict way, it may go a long way in enhancing the finances of the Railways.

Even after spending a sum of Rs. 13 crores on the Railway Protection Force, the thefts are on increase. We have to find out where the snag exists.

The unit of territorial Army in the Railways should be strengthened.

So far as the organisation of the Board is concerned, it is good and the Board should be maintained and strengthened.

Shed on the platform at the Jaunpur station should be constructed and the platform a Pindara Halt be elevated.

The Patna-Delhi Express train which was cancelled due to coal shortage, has not yet been re-started. This train should be re-started at an early date.

With these words, I support the Railway Budget.

Shri T.D. Kamble (Latur): I would like to say a few words about the new railway lines in Maharashtra. The construction work on Bani-Chanaka Railway line (76 km. long and which involves the cost of Rs. 5.3 crores) was sanctioned in 1973-74. But no sanction was given for the remaining lines nor any provision for them has been made in the Budget. A sum of 4 lakh 30 thousand rupees was earmarked for the survey of Miraj Kurduwadi-Latur and Latur to Latur Road. Similarly Rs. 5 lakh 76 thousand was earmarked for the survey of Manmad-Parbhani line. The hon. Minister should tell us as what extent he would be able to complete these lines during the current Five Year Plan. In the new Five Year Plan a sum of Rs.100 crores has been earmarked for the new railway lines.

A mention has been made in this Budget about the survey for Ramgundar-Nizama bad line on the South-Central Railway. It is a commendable thing. If the Government wants this line to be economical, they should link it from Nizamabad to Latur Road.

It is a matter of worry that the Railways go in loss. I want to give certain suggestions in this regard.

The punctuality of the trains should be maintained.

Now-a-days a number of accidents take place. It should be looked into and the defaulters be punished.

Arrangements of water at the Railway stations as well as in the trains should be made.

Certain steps should be taken up to mitigate the over-crowding in the trains.

There are some agents at the railway platforms who provide seats and sleepers in the trains to the passengers and take some money from them. I do not know how these persons manage to provide reservation to the passengers while reservation is not available at the reservation counters ? This evil practice should be done away with.

The Harijans and Adivasis in Grade III should be provided jobs as per the percentage fixed for them.

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj): The expenditure is not commensurate with the income of the people. This is an unbalance. The burden of increase in fares falls on the poor. In view of these matters the balance is needed.

The administration should be toned-up. None seems to be sincere towards his responsibility. Late running of trains is a common feature. It should be streamlined.

Coaches of the trains, particularly in Assam Mail are not cleaned.

Take the example of Bihar. It is very difficult to get-on the First class compartment. Constables are in large number among the first class passengers and the bonafide First-class passengers are deprived of seats. Nobody is there to see to it. So far as the protection Force is concerned, thefts and losses are on the increase. The administration of the Railway Protection Force should be toned-up.

There is no waiting room for third class passengers at the Kishanganj railway station. Over-bridges should be constructed at Kishanganj, Purnea Jn., Thakurganj and Pothia.

Stoppage of trains should be provided at Pothia station because that is an important Mandi and Station.

May I know the steps being taken by the Ministry of Railways with regard to assurance given by the hon. Minister on July 29, 1973 about the reinstatement of Harijans and Muslims ?

So far as vending is concerned, it is a matter to be looked into as to whether the vending licences have been given to Harijans and members of minority communities.

I am of this view that there should be one union in one industry.

Crores of rupees are being spent on D.L.W. Attention should be given to the working of the D.L.W.

Railway Time-Tables should be published in Hindi, Urdu and Bengali.

श्री शंकरराव सामन्त (कोलाबा) : गत वर्ष की अनेक विरोधी परिस्थितियों के बाद रेल मंत्री को बहुत चतुराई से काम करना पड़ा है । गत अगस्त में हुई लोकों कर्मचारियों की हड़ताल के बाद रेल मंत्री ने सबक लिया और उसके बाद उन्होंने श्रेष्ठतर कार्यकरण का परिचय दिया । 'धीरे-धीरे काम करो' 'नियमानुसार काम करो' जैसे हथकंड़े अभी भी जारी हैं परन्तु रेल मंत्री को इन राष्ट्र-विरोधी आन्दोलनों के समक्ष झुकना नहीं चाहिये ।

रेलवे सुरक्षा बल के बारे में सुझाव देता हूं । इसके कार्यकरण में सुधार की अनेक वर्षों से बात-चीत चल रही है परन्तु अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है । रेलवे प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि रेलवे सुरक्षा बल उसी कार्य-कुशलता से कार्य करे जिससे किसी राज्य की पुलिस करती

है। ऐसा तभी किया जा सकता है जब अधिकारियों को कठोर परिक्षण दिया जाये जैसा कि पुलिस प्रशिक्षण स्कूलों में दिया जाता है।

बजट भाषण के पृष्ट 11 पर मंत्री महोदय ने कहा कि आप्टा-दासगांव सेक्शन में 'अर्थ-वर्क' के निष्पादन के लिये मंजूरी दे दी गई है। परन्तु 'अर्थ-वर्क' के लिये बजट में कोई उपबंध नहीं किया गया है। इस लाइन पर निर्माण कार्य तुरंत होना आरम्भ चाहिये।

पिछड़े क्षेत्रों में भी कार्य आरम्भ किया जाना चाहियें।

Shri Ram Surat Prasad (Bansgaon) : The Ministry of Railways have made provision to mobilise resources by way of increasing fares but the increase will be justified only when more facilities are provided to the third class passengers.

In this department the reservation for Scheduled Castes has not been fulfilled. Attention should be given to provi de employment to the persons belonging to Scheduled Castes.

Unless the persons responsible for recruitment fulfil the quota reserved for Scheduled Castes, the entry of their conduct should not be made in the register.

A Service Commission for N. E. Railway should be established at Gorakhpur.

The conversion work in Barabanki and Gorakhpur areas in Uttar Pradesh is not being done as rapidly as is being done in Bihar.

In Gorakhpur district, Bansgaon is a backward area. It is a backward area and no industrialist comes forward to set up an industry in Gorakhpur region. The reason is that there are no means of transport in this area. I requested Shri Hanumanthaiyha, Shri L.N. Mishra and the Prime Minister for laying railway lines in this backward area but they replied stating that the railway lines in this area will prove uneconomical as there are no industries. What a good logic it is. No railway lines will be laid because there are no industries and no industries will be set up because there are no means of Transport including railways. It means this area will continue to remain as backward area as ever. I want to submit that the responsibility of making development of an area rests with the Government. So I request the hon. Minister to carry out surveys in Gorakhpur region for the purpose of laying railway lines so that its backwardness may be removed and it is pushed towards development.

Though there is a provision of reservation for Scheduled Castes in the matter of direct recruitment and promotions to the higher posts but there is no such provision in respect of upgradation of post which is a new way of giving promotion. I want that either the system of upgradation should be scrapped or the provision of reservation for the Scheduled Castes should be made. I also want that the 9 UP and 10 DOWN Express trains should be made to halt at Sardarnagar in my constituency, as this arrangement will provide convenience to the people of my area. The goods yard should be shifted to Surajkund from the Gorakhpur main station. It will remove the great inconvenience being caused to the public at present. I also want that a thorough enquiry should be made into the case of pilferage of medicines worth thousnds of rupees from the Gorakhpur Hospital and the culprits should be severely punished. In the end, I request the hon. Minister that overbridges on a road leading to Gorakhnath Temple at Jefpur Dharmashala and Uraghat Cantt. should be constructed so that the road transport may run smoothly there. With these words I support the Railway Budget.

Mr. Chairman : As the hon. Members know the discussion on Railway Budget is going to conclude today and the time left with us is very short. So hon. Members will get three minutes each now.

Shri Chiranjit Jha (Saharsa) : Sir, first of all I would like to congratulate the Minister of Railways for his progressive and socialistic outlook and successful performance of railways under his ministership in spite of the state of scarcity, unrest and strikes. He achieved success in sending supplies of food grains to drought-effected, famine stricken and scarcity bound areas and in keeping the railway traffic moving. Secondly, I want to make an appeal to the railway employees, not to resort to strikes and agitations in view of critical economil situation of the country. In this context I want to make a suggestion that a second line of defence on the pattern of Home Gaurds should be formed out of railway employees to carry on the work at the time of crises.

The North-Eastern Zone is a very large one and it can easily be bifurcated. I would like to know whether Government will think over the question of making a tenth railway zone consisting of the eastern portion of that railway and a part of North-Eastern Railway zone. Further I suggest that a railway division should be set up at Saharsa because it is a central place in Kosi Commissionery. I also suggest that the bridge being constructed at Kosi river should be converted into a rail-*cum*-road bridge. There is also need of connecting the areas of Madhepura to Sinheshwara by railway line and the railway line may further be extended to Bhimshankar. It will provide much convenience to the public and it will add to the earnings of Railways.

श्री सैयद अहमद आगा (बारामुला) : श्रीमन्, मैं कुछ उन बातों का उल्लेख करना चाहूंगा जिन पर मंत्री महोदय को विचार करना चाहिये। मैं रेलवे बजट का समर्थन करता हूं। साथ ही यह भी बताना चाहता हूं कि बजट बनाते समय रेलवे मंत्री काश्मीर को भूल गये थे। जम्मू को रेल लाइन पुनः चालू करने में 26 वर्ष लगे। वर्ष 1900 में ही बौरबेले ने यह प्रतिवेदन दिया था कि श्रीनगर को जम्मू से जोड़ा जा सकता है परन्तु सरकार ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरा अनुरोध है कि जम्मू और श्रीनगर के रेल लाइन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये ताकि काश्मीर के अलगाव की स्थिति शीघ्र ही समाप्त हो जाये। मुझे पता लगा है कि काश्मीर घाटी की रेलवे लाइन बिछाने की दृष्टि से सर्वेक्षण कराया गया है। न मालूम कब तक यह लाइने वहां बिछाई जायेंगी।

अब मैं तीसरी श्रेणी के यात्रियों की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। रेल विभाग को सब से अधिक आय इसी दर्जे में यात्रा करने वालों से होती है। इन यात्रियों से प्रतिवर्ष आय 34.54 करोड़ रुपये होती है जबकि प्रथम श्रेणी के यात्रियों से केवल 4.45 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं। किन्तु तीसरी श्रेणी के डिब्बों में मूल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं। वहां भीड़ अधिक होती है। पीने का पानी वहां नहीं होता। इन यात्रियों को मूल सुविधाएं अवश्य प्रधान की जानी चाहिये।

सरकार प्रमुख मार्गों का विद्युतीकरण करना चाहती है। परन्तु वह छठी पंच वर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिये बिजली घर स्थापित करना चाहते हैं। वर्तमान तेल संकट को देखते हुए यह कार्य पंचवर्षीय योजना में ही किया जाना चाहिये।

Shri Ram Parkash (Ambala) : Mr. Chairman, Sir, I congratulate the Minister of Railways for this budget as it will bring about the improvement in the existing state of affairs. Today the progress of the country to a large extent depends on the railways. In my opinion the main factor responsible for the current shortage of essential commodities and high prices is the slow movement of railway wagons.

The greatest reason of price rise in our country is the slow movement of railways. The railway Department is worst affected as regards the strikes by its employees. This phenomenon has caused shortage of essential commodities and dislocation of the economy of the whole country. Huge quantities of coal are lying at the pitcheads and railway sidings but due to shortage of wagons it is not reaching consumers. I request the Railway Minister to take firm steps against those who incite railway workmen to go on strike and thus indulge in anti-social activities.

The hon. Minister should take steps to supply diesel to the States of Punjab and Haryana so that they can operate their tubewells and produce more wheat. As regards my region I would like to say that the construction work on Jagadhari-Chandigarh and Jagadhari-Paonta railway lines should be expedited, as the survey in respect thereof has already been carried out. More passenger trains should be made available between Ambala and Saharanpur. The Janta Express should again be made to halt at Baroda station between Ambala Cantt. and Saharanpur, because its non-stoppage is causing great inconvenience to the public.

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : सभापति महोदय, यह उल्लेख बार-बार किया जाता है कि यातायात-व्यवस्था में रेलवे का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इस से बड़े पैमाने पर माल की ढुलाई होती है इससे कृषि और औद्योगिक विकास में बहुत अधिक मदद मिलती है। किन्तु जहां तक उड़ीसा का संबंध है, वहां खनिज पदार्थों की बहुतायत है, फिर भी वहां रेलों का विकास नहीं किया गया है। गोपालपुर पत्तन को इसके निकटवर्ती उपजाऊ भूमि से जोड़ने के लिये एक लाइन का सर्वेक्षण 1946 में किया गया था, दूसरा सर्वेक्षण 1947 में किया गया था किन्तु इस लाइन पर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में रेलवे का विकास क्यों नहीं किया जा रहा है। उड़ीसा में कोयला खानों के मुहानों पर भारी मात्रा में कोयला इकट्ठा हो गया है और वैगन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। रेलवे बोर्ड के चैयरमैन को उड़ीसा से कई तार इस बारे में भेजे जा चुके हैं चीनी, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, कोयला आदि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई देश के विभिन्न भागों में ठीक से नहीं हो पा रही है। अतः अपेक्षित संख्या में वैगन तत्काल सप्लाई किये जाने चाहिये, जिससे यह समस्या हल हो जायेगी।

Dr. Kailash (Bombay-South) : Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Railway budget. I want to congratulate the Railway Minister for his new approach of providing new railway lines in the backward areas of the country. As regards the area of Ratnagiri-Kolaba in Maharashtra a railway line, which we call West Coast Railway, was to be laid. Sufficient earth-work was done on it last year but it is still incomplete. I request the Minister that the work on it should be expedited. The speed of Rajdhani Express and Frontier Mail should be increased so that the former may cover the distance between Delhi and Bombay in originally scheduled time of 17 hours and the latter in 21 hours. I would also like to know the difficulty in including T.T.Es and T.T.Is in the category of running staff while the Drivers and Guards are already regarded as running staff. There will be no benefit of extending the period of reservation to one year, as it will provide more opportunities for blackmarketing in reservation tickets. Moreover, there is no necessity of appointing railway agents for booking of tickets etc.

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : सभापति महोदय, मैं सभा के प्रति आभारी हूं कि ....

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल पूरा कीजिए।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 31 मार्च, 1974/22 फाल्गुन, 1895 (शक) के 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, March 13, 1974/Phalguna 22, 1895 (Saka)

MGIPRRND—IV N.S.—12LSS/74—31-5-74—490

PLS 48. XXXVI. 15. 74(N)
1895

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006. 1974